

# “विकासशील अर्थव्यवस्था में डंकल प्रस्ताव का प्रभाव भारत के विशेष संदर्भ में”



इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डी० फिल० उपाधि हेतु  
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

द्वारा

जीतेन्द्र नाथ दुबे

शोध छात्र

निर्देशक

डॉ० जे०एन० मिश्र

उपाचार्य

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

**1998**

# अनुक्रमणिका

| अध्याय क्रम   | पृष्ठ सख्या |
|---|-------------|
| प्राक्कथन   | I - VI      |
| 1 शोध अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र एवं विधि                              | 1 – 7       |
| 2 आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि                                       | 8 – 24      |
| 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत एवं<br>वर्तमान तथा अतीत वर्तमान में विचलन | 25 – 61     |
| 4 गैट   | 62 – 77     |
| 5 डकल प्रस्ताव उरुग्वे दौर  | 78 – 145    |
| 6 विश्व व्यापार संगठन   | 146 – 175   |
| 7 डकल प्रस्ताव का प्रभाव  | 176 – 228   |
| परिशिष्ट  | I - XIII    |
| संदर्भ ग्रंथ सूची   | I - II      |

# प्राक्कथन

प्रकृति का यह शाश्वत नियम रहा है कि शक्तिशाली जीव छोटे जीव को अपना आहार बनाते रहे हैं। वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था पर दृष्टि रखने पर स्पष्टतः यह प्रकृति का शाश्वत नियम प्रत्यक्षतः लागू होता है। विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपने हितों को सर्वोपरि रखने की प्रवृत्ति की विद्यमानता विकासशील राष्ट्रों को शकालु प्रवृत्ति अपनाने के लिये बाध्य कर रहा है। डकल प्रस्ताव इस सन्दर्भ में एक कडी के रूप में विद्यमान है।

साठ के दशक के अन्तिम वर्ष में पश्चिमी देशों में छात्र, मजदूर आन्दोलन के रूप में बवडर उठा था जिसमें साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों को निरर्थक सिद्ध करके एक नये युग के लिये जमीन तैयार की। इस बवडर ने पूँजीवाद को अपनी तमाम शक्तियाँ बटोर कर अपने ढहते हुए किले को बचाने के लिये युक्ति खोजने को विवश किया।

वियतनाम युद्ध में अमेरिका जैसी महाशक्ति की पराजय के बाद पूँजीवादी देशों को स्पष्ट दिखाई देने लगा कि परमाणु हथियारों और आन्तरिक युद्ध की तैयारियों के बावजूद वे अपनी सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और न ही तीसरी दुनिया के ससाधनों के दोहन से अपने को समृद्ध बनाना अब उनके लिये संभव होगा क्योंकि अब उनके ससाधन समाप्त होने वाले हैं। ससाधनों के दोहन के लिये तीसरी दुनिया के पर्यावरण का विनास करने के बाद जब इसका खतरा स्वयं उन पर मड़राने लगा तो वे तीसरी दुनिया के देशों में जनसंख्या नियन्त्रण,

पर्यावरण व्यवस्था, तथा उसके लिये आवश्यक शिक्षा, साक्षरता के प्रसार के लिये धन खर्च करने लगे। इसके साथ ही इन देशों में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता क्षीण हुई या उसकी आवश्यकता नहीं रही तो उत्पादन हीनता की कल्पना सामने आयी। अर्थात् कालाबाजारी, सूदखोरी, दलाली, मुद्रा मूल्य और कीमतों में हेराफेरी से होने वाली आय से राष्ट्रीय आय में सुधार किया जाने लगा।

अवैध धन की समानान्तर व्यवस्था से इस प्रक्रिया को और बल मिला क्योंकि वैध और अवैध आर्थिक गतिविधियों का भेद लगभग समाप्त हो गया। इस तरह पूँजीवादी देशों में कृति समृद्धि का उफान आया और इस उफान के स्पर्श ने तीसरी दुनिया के कुछ देशों विशेषकर उनके मध्य वर्ग को प्रभावित किया। इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी की क्रान्ति ने इस कृत्रिम समृद्धि को सौ गुना चका चौंध के साथ प्रस्तुत किया और इस चकाचौंध में तीसरी दुनिया के बढ़ते हुए मध्य वर्ग को कृत्रिम समृद्धि तथा कृत्रिम उपभोग का नसेडी बना दिया। इन देशों की सरकारों को मध्य वर्ग के दबाव में आकर "ऋण कृत्वा घृत पिबेत" की नीति अपनानी पड़ी, इससे समृद्ध देश जिनका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गैट जैसी संस्थाओं पर अधिकार था, सारे विश्व को अपना कर्जदार बनाने की स्थिति में हुए और वे साहूकार की हैसियत से सारे विश्व पर मनमाना हुक्म चला सकते थे। डकल प्रस्ताव इस हुक्मनामे की इबारत है।

प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रस्ताव मरणासन्न पूँजीवादी में नया प्राण फूँकेगे या ये बुझते दीप की लौ की तरह इसे कुछ समय के लिये प्रदीप्त मात्र करेंगे? प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही लगता है क्योंकि जिन दो समस्याओं के कारण विश्व का



### III

वर्तमान सकट प्रस्तुत हुआ है उनका समाधान नई अर्थव्यवस्था से नहीं होगा। इसकी समस्या बढ़ती हुई बेरोजगारी है जो मनुष्य की आत्मा का क्षय रोग है और दूसरी है विषमता की जो सामाजिक द्वेष, घृणा और हिंसा बढ़ाकर समाज का कैसर सिद्ध होगी।

डकल प्रस्ताव विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित एवं संचालित करने वाला दस्तावेज है। यह गैट के पुराने स्वरूप में संशोधन करके उसका व्यापार की सभी वस्तुओं तक विस्तार कर रहा है। इसमें गैट प्रबन्ध के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र भी आता है जो पहली नहीं था। इसके अतिरिक्त इसमें सेवाओं का व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार और व्यापार सम्बन्धी विनियोग उपाय नये प्रावधान हैं। कृषि सम्बन्धी प्रावधान में कृषि को मिलने वाली सरकारी सहायता को घटाने और उसे 13.3 प्रतिशत (विकासशील देशों में 10 प्रतिशत) तक लाने की शर्त है। स्मरणीय है कि इस समय यूरोप, अमेरिका और जापान में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता 30 से 50 प्रतिशत है जो अधिकतर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये होती है। भारत में यह सहायता कठिनाई से तीन-साढ़े तीन प्रतिशत है और यह अधिकतर खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाओं की सहायिकी तथा समर्थन मूल्य के रूप में होती है इसका उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना नहीं, निर्वाह स्तर को बनाये रखना और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को निम्न सात अध्यायों में विभाजित किया गया है।

- 1 शोध अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र एवं विधि
- 2 आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि

- 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत एव वर्तमान तथा अतीत वर्तमान में विचलन
- 4 गैट
- 5 डकल प्रस्ताव उरुग्वे दौर
- 6 विश्व व्यापार संगठन
- 7 डकल प्रस्ताव का प्रभाव

प्रथम अध्याय के अन्तर्गत शोध-अध्ययन का उद्देश्य एव क्षेत्र विधि सकल्पना और सीमाओं का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत आर्थिक विकास, आर्थिक सवृद्धि, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण एव विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार तृतीय अध्याय के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत एव वर्तमान जिसमें ब्रिटिश पूर्व अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था एव ब्रिटिश पश्चात् या स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की अर्थव्यवस्था तथा वर्तमान अतीत में विचलन का विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत गैट की स्थापना तथा उसके द्वारा सम्पादित दौर का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। पाचवे अध्याय में उरुग्वे दौर की वार्ताओं के साथ-साथ डकल प्रस्ताव की रूप रेखा तथा उपबन्धों का विश्लेषण किया गया है। छठे अध्याय के अन्तर्गत विश्व व्यापार की स्थापना एव उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विश्लेषण है। सातवा अध्याय इस शोध अध्ययन का मूल बिन्दु डकल प्रभाव है इसके अन्तर्गत डकल प्रस्ताव का

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सुझाव दिया गया है।

## साभारोक्ति

सर्व प्रथम मैं अपने शोध-निर्देशक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सहनशीलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति वाणिज्य जगत के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक सरस्वती पुत्र डॉ० जगदीश नारायण मिश्र रीडर, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का आभारी हूँ जिनके पुत्रवत् स्नेहाशीलता की छाया में अद्भुत वात्सल्य प्रेम का अनुभव करते हुए मैं यह शोधकार्य पूर्ण कर सका। मैं गुरुदेव की महती कृपा का सदैव ऋणी रहूँगा। ऐसे ही महान गुरु का सानिध्य हमें सदैव मिले यही मेरी स्पृहा है। इसके साथ ही साथ मैं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ विशेष आभारी हूँ जिनके द्वारा समय-समय पर विविध प्रकार के सहयोग प्राप्त होते रहे हैं।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अधिष्ठाता प्रो० एस पी सिंह का भी आभारी हूँ। जिन्होंने समय-समय पर शोध कार्य पूर्ण करने हेतु मेरा उत्साह वर्धन किया।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो० जगदीश प्रकाश का भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने शोधकार्य का सुअवसर प्रदान कर अनन्त सहयोग प्रदान किया।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के रीडर, मृदु भाषी डॉ० प्रदीप जैन का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने विषम परिस्थितियों में मार्ग दर्शन करते हुए शोध कार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु अदम्य उत्साह वर्धन किया जो मेरे लिये वन्दनीय है।

मैं अपने गुरुजन वृन्द प्रो० पी सी शर्मा, प्रो० जे के जैन, प्रो० के एम शर्मा, डॉ० सरफराज अहमद अशारी, डॉ० बद्री प्रसाद त्रिपाठी, डॉ० वी एम वैजल, डॉ० ए के मुखर्जी, डॉ० अजनी मालवीय, प्रो० आर एस डी द्विवेदी, डॉ० आर के सिंह, का भी मैं विशेष आभारी हूँ। जो अपना अमूल्य समय एवं सुझाव प्रदान करते रहे हैं।

मैं अपने देवता तुल्य पिता एवं अपनी पूज्य माताजी के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने शोधकार्य सम्पन्न करने हेतु समस्त प्रकार की सहायता प्रदान की और समय-समय पर शोधकार्य पूर्ण करने के लिये उत्साह वर्धन करते रहे। उनके चरणों में कोटिश प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जन्म जन्मांतर तक इन्हीं माता पिता सानिध्य प्राप्त होता रहे।

मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बन्धुओं के प्रति विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने सदैव मेरा उत्साह वर्धन कर इस कार्य को सरल बनाने में हर सम्भव सहायता प्रदान की।

मैं अपने ज्येष्ठ अग्रज पुत्र अर्विंद दुबे के अनन्य सहयोग के लिये सस्नेह आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने विभिन्न विषम परिस्थितियों में अभिन्न सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपने परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करते रहे हैं।

## VII

मैं अपने भाजे विवेक शर्माजी को सस्नह धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विभिन्न प्रकार के सहायोग के लिये जिससे मुझे शोधकार्य करने में सरलता का अनुभव हुआ।

मैं अपने शोध सहपाठी श्याम कृष्ण पाण्डेय के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान कर मेरे शोध कार्य को सम्पन्न होने में गति प्रदान की।

मैं शोध सहपाठी राजेन्द्र कुमार मिश्र को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों में सतत् उत्साह वर्धन करते रहे।

मैं अपने शोध सहपाठी रुद्र प्रभाकर मिश्र (सपरिवार) को विशेष आभार प्रकट करता हूँ जिनका सहयोग अविस्मरणीय है।

मैं अपनी शोध सहपाठिनी, उत्साहदायनी, नामानुकूल कमलवत गुणों से परिपूर्ण डॉ० कमलेश कुमारी पालीवाल (कमल) का विशेष आभारी हूँ जिनके बिना मैं शोधकार्य पूर्ण ही नहीं कर सकता था, वास्तव में सुश्री पालीवाल की ही सकारात्मक प्रेरणा ने शोधकार्य सम्पन्न करने लिये प्रेरित हुआ और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सहयोग विना मागे प्राप्त होते रहे इसके लिये मैं उन्हें कोटिश धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें लम्बी उम्र प्रदान करें।

## VIII

मै महेन्द्र कुमार शर्मा जी का विशेष आभारी हू जिन्होंने अपना अमूल्य समय एव सहयोग प्रदान कर शोधकार्य को सरल बनाने में विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करते रहे। इसके लिये मै उन्हें सस्नेह धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

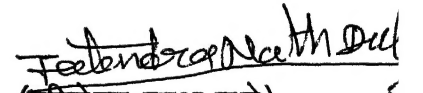
विशेष सामग्री को अधिक अद्यतम् और उपयोगी बनाने के लिये जिन विभिन्न प्रतिवेदनो पत्रिकाओ और सदर्थ ग्रंथो का प्रयोग किया गया उनके प्रणेताओ और प्रकाशको के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ

मै मोहम्मद शाहिद भाई (सपरिवार) का विशेष आभारी हूँ जिनके विशेष सहयोग के द्वारा ही मेरा मुद्रण कार्य सम्पन्न हुआ।

अन्त में मोहम्मद इस्तियाक को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिनके सहयोग के मुद्रण कार्य अति सरलता से समय पर सम्पन्न हुआ।

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 3-10-98

  
(जीतेन्द्र नाथ दुबे)

## अध्याय : 1

शोध अध्ययन का उद्देश्य,  
क्षेत्र एवं विधि

## उद्देश्य एवं क्षेत्र :

विगत पाच दशको मे विश्व अर्थव्यवस्था मे बहुआयामी परिवर्तन हुए। जिसमे अर्थ व्यवस्थाओ का स्वरूप भी प्रभावित होता रहा है यथा पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे सरकारी हस्तक्षेप तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओ मे व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रवेश आदि आज विश्व मे कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूर्णतया पूजीवादी ओर न पूर्णतया समाजवादी रह गयी है। अन्तर इतना है कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिक प्रभुत्व है ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था मे सरकारी हस्तक्षेप काफी मात्रा मे विद्यमान है। कुलमिलाकर यह कहा जा सकता है कि सभी अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर अग्रसर हैं केवल मात्रा या प्रतिशत का अन्तर है।

दूरी ओर 80 के दशक से विश्व के कई भागो मे आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशो मे भी कुछ मदी के आसार समय समय पर परिलक्षित हुए हैं जिनसे वहाँ रोजगार एवं औद्योगिक विकास की समस्या अनुभव की गयी। इसी लिये विश्व अर्थ व्यवस्था में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक एवं व्यापार से सम्बन्धित समझौते का गठन हुआ। विश्व स्तर पर आर्थिक आद्योगिक एवं व्यापार नीतियो मे फेर बदल की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। व्यापार एवं तटकर सम्बन्धी सामान्य समझौते को समाप्त कर एक नये व्यापारिक विस्तृत समझौते का अस्तित्व मे लाया गया। नये समझौते मे न केवल पाश्चात्य यूरोपीय देशो की अर्थव्यवस्था का प्रभावित



किया बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों को प्रभावित कर रहा है।

अतः वर्तमान अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया में विकसित एवं विकासशील सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। हो सकता है कुछ देशों पर सकारात्मक और कुछ देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। परन्तु यह निश्चित है कि अर्थव्यवस्थाएँ किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होंगी।

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक सुधारों व आर्थिक पुनर्संरचना से किसी न किसी रूप में गहरी सीमा तक प्रभावित हो रही हैं। विकासशील देशों की अपनी विशेषताएँ एवं अपनी सीमाएँ हैं जहाँ संसाधनों का अल्पदोहन है वही पर पूँजी की कमी एवं परम्परागत ढाँचा विद्यमान है। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं का विचलन परम्परागतवादी अर्थव्यवस्था के ढाँचे से आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधि की ओर हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन ढाँचे एवं बाजार व्यवस्था में परिवर्तन विकासशील देशों की अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता यथा विश्व व्यापार संगठन से प्रभावित होगा।

वर्तमान समय में मौद्रिक, औद्योगिक एवं व्यापार गतिविधियाँ किसी देश के ऊपर समग्र रूप से नहीं निर्भर करती हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, क्रियाकलाप निर्धारित करती हैं विदेशी पूँजी का आगमन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार एवं

स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा एवं मात्रा समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है आज कोई भी देश यदि यह चाहे कि किस देश को कितना आयात और किस देश को कितना निर्यात करना है स्वयं निर्णय करे यह उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है।

डकल प्रस्ताव का प्रभाव न केवल विकसित देशों पर पड़ रहा है और भविष्य में पड़ेगा वरन् विकासशील देशों को भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दिशाओं में प्रभावित करेगा। आज "एशियन टाइगर्स" यथा दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर आदि की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। जबकि अस्सी के दशक के अन्तिम एवं नब्बे के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में पूँजीवादी, यूरोपीय देशों में एवं औद्योगिक सकट एवं बेरोजगारी के आसार नजर आये थे। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसी दशा में पूँजीवादी देशों विशेषकर अमेरिका के द्वारा डकल प्रस्ताव के माध्यम से "गैट" में परिवर्तन करके एक नयी विश्व अर्थव्यवस्था कायम करने की बात सोची गयी और जिसे अन्ततः कार्य रूप दे दिया गया।

आज एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप के तमाम ऐसे विकासशील देश हैं जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाये हुए हैं परन्तु आर्थिक एवं औद्योगिक उतार चढ़ाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में निर्वाध विदेशी पूँजी आगमन बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना तथा अवश्यक वरीयता वाले उद्योग में भागीदारी आदि हो रही है जो कि डकल प्रस्ताव का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से प्रभाव कहा जा सकता है। इस शोध के द्वारा इस बात का पता लगा कि विकासशील देश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर डकल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। या पड़ सकता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसपर भारत का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास निर्भर करता है। इस अध्ययन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं प्रकृति के साथ साथ विचलनो को भी समझाया जायेगा जिससे भावी विकास रणनीति तय की जा सके, इस लिये इस शोध प्रबन्ध में विकासशील एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं लक्षणों को जानने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत, वर्तमान एवं विचलन को जानने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ शोध का केन्द्र बिन्दु उरुग्वे दौर डकल प्रस्ताव जिसकी पृष्ठभूमि "गैट" है और परिणति विश्व व्यापार संगठन है को विस्तृत रूप से अध्ययन करने एवं प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है।

यद्यपि शोध का विषय विकासशील देशों पर डकल प्रस्ताव का प्रभाव भारत के विशेष सदर्भ में है परन्तु एक व्यक्तिगत शोधकर्ता के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह विकासशील देशों में जा कर उनका अध्ययन करे एवं उसके वास्तविक परिणाम निकाले। इसलिये शोध के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील देश के प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है, परन्तु किसी वित्तीय एवं सरकारी सहयोग के अभाव में एक शोध छात्र के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रारम्भिक आकड़ों के आधार पर अध्ययन करना दुरुह कार्य है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के

कुछ चयनित क्षेत्रों से सम्बन्धित अध्ययन कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है।

इस विषय पर शोध करना एवं उसके परिणामों को जानना वर्तमान में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भविष्य में इसका और अधिक महत्व होगा जो नये शोधकर्ताओं के लिये एक दिशा देगा।

## संकल्पना :

प्रस्तुत अध्ययन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित संकल्पनाएँ की गयी हैं। यथा

- 1 कृषि (विशेष कर कृषि बीजों एवं अनुसंधान) की स्थिति
- 2 पेटेंट में परिवर्तन किस सीमा तक होगा।
- 3 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई पी आर) सम्बन्धी पहलू।
- 4 सेवा क्षेत्र में व्यापार की स्थिति (जो एक नई दिशा दे सकती है)
- 5 विनियोग सम्बन्धी उपाय तथा
- 6 सहायिकी आदि।

ये सभी उक्त बिन्दु अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यवस्थाएँ एवं राजनैतिक परिवर्तन के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं व्यापार की दिशा भी प्रभावित करेंगे।

## शोध विधि:

अध्ययन को अर्थपूर्ण एवं वास्तविक विश्लेषण करने के लिये एक उचित उपयुक्तशोध प्रारूप का निर्माण आवश्यक होता है। जिसमे सम्भावित समस्याओं के हल अथवा सुधार उपाय निहित होते हैं। क्योंकि दोषपूर्ण अध्ययन के कारण एक उपयुक्त अच्छा शोध विषय भी गलत विचार धारा प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये एक वास्तविक सोच एवं विधि आवश्यक होती है।

शोध की रूप रेखा शोध प्रारूप से सम्बन्धित होती है। इस शोध में अध्याय 4, 5, 6 एवं 7 में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समको के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करने की कल्पना की गयी है। परन्तु द्वितीयक समको के द्वारा ही सूचनाओं को एकत्रित किया गया है। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर डकल प्रस्ताव के प्रभाव को जानने एवं लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

## अध्ययन की सीमारें :

इस महत्वपूर्ण शोध विषय की कुछ सीमाये भी है, जैसे

- 1 सूचनाओं को प्राप्त करना एक जटिल कार्य है।

- 2 चूँकि यह कृषि उद्योग एवं सेवा या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित है इस लिये किसी भी वर्ग विशेषकर कृषक वर्ग से प्रतिक्रिया जानना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि अभी कृषकों को इसका पूरा ज्ञान नहीं है और दूसरे वे सरकारी विभाग का व्यक्ति जान कर दूर रहना चाहते हैं।
- 3 इस विषय पर अब तक शोधकार्य का आभाव रहा है इस लिये इस दिशा में कठिनाई अनुभव हुई है।
- 4 छितरे हुए व्यक्तिगत साहित्य जो उपलब्ध है उसमें पक्षपात पूर्ण विचार हो सकते हैं।
- 5 वित्तीय एवं सरकारी सहयोग के आभाव में व्यक्तिगत शोध-कर्ता के सीमित साधनों को देखते हुए प्राथमिक आकड़ों का सकलन कठिन कार्य है।

यद्यपि इस विषय पर अभी तक विशेषकर उत्तर भारत में शोध कार्य नहीं हुआ है इस लिये प्रयाप्त साहित्य का आभाव है डकल प्रस्ताव (मुख्य रूप से अधिकृत प्रकाशन) तथा समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं एवं विद्वानों को उरुग्वे दौर से सम्बन्धित रहे हैं के प्रकाशनों से ही सहायता लेने का प्रयास किया गया है।

## अध्याय : 2

आर्थिक विकास

एवं

संवृद्धि

आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि को अधिकांश जन एक ही समझते हैं व एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। परन्तु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह गलत है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि को जन समुदाय द्वारा एक ही समझना भ्रॉति है। यद्यपि कि परम्परावादी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक सवृद्धि शब्द का प्रयोग किया है। आज आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि दो अलग-अलग बिन्दु हैं और आर्थिक विकास आर्थिक सवृद्धि को समाहित करते हुए ही पूर्ण होता है। अतः आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि को अलग-अलग समझना तथा उनके भेदों को जानना आवश्यक है।

## आर्थिक विकास:

आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले संस्थागत एवं संरचनात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं, आर्थिक विकास की अवधारणा का आधार समाज द्वारा मान्य वे मूल्य हैं जिनपर समाज के निर्माण की संकल्पना की गई है। आर्थिक विकास को कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया था। चार्ल्स किडल वर्जर तथा जी०एम० मायर आदि। आर्थिक विकास के संबंध में मायर की अवधारणा यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक लम्बी अवधि में वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो और इसके साथ परम निर्धनता के रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि न हो।



अलग-अलग विद्वानों ने आर्थिक विकास को भिन्न-भिन्न प्रकारों से परिभाषित करने का प्रयास किया परन्तु एक बहुप्रचलित परिभाषा यह दी जा सकती है कि "आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय एक दीर्घ कालीन सदर्भ में बढ़ती है और यदि आर्थिक विकास की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी।"

उपर्युक्त बहुप्रचलित परिभाषा के विश्लेषण स्वरूप कई बिन्दु निकल कर सामने आते हैं जो आर्थिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। इस शृंखला में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन निहित हैं। आर्थिक विकास एक दीर्घ कालीन प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहती है। राष्ट्रीय आय के वास्तविक रूप का संबंध वस्तुतः मूल्य स्तर से है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी कही जायेगी जब मूल्य स्तर में वृद्धि राष्ट्रीय आय वृद्धि की दर से नीची हो जिससे कि लोग अपनी बढ़ी हुई वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग अधिक वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त करने में कर सकें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जीवन स्तर में लगातार सुधार का परिचायक है।

आर्थिक विकास का एक पहलू यह भी है कि अर्थव्यवस्था का विभाजन एवं आधुनिकीकरण को जिनसे की अर्थव्यवस्था में नये-नये क्षेत्रों का विकास हो तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो और अन्ततः बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण

समाधान हो। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की अवधारणा में यह भी निहित है कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में व्याप्त आर्थिक विषमता में कमी आये। इसी परिपेक्ष्य में आय वृद्धि का वितरण सामाजिक न्याय की दृष्टि से हो।

आर्थिक विकास का सम्बन्ध जीवन के उच्च मूल्यों को प्राप्त करने से है। अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता, भुखमरी तथा महामारी आदि समस्याओं से निदान पाया जा सके। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा आर्थिक विकास के लिए दी गई परिभाषा में उपर्युक्त तत्वों को समाहित किया गया है। अतः आर्थिक विकास की प्रकृति, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक है जिसका उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से है तथा परम्परागत वर्ग से हटकर नये वर्ग के लोगों से है। आर्थिक विकास का सम्बन्ध सामाजिक न्याय तथा मानवीय मूल्यों से है।

## आर्थिक संवृद्धि :

आर्थिक संवृद्धि का सम्बन्ध मौद्रिक परिवर्तनों से है तथा इसके साथ ही साथ उत्पाद, आय आदि चरों के मात्रात्मक वृद्धि से है। यदि कोई देश अधिक उत्पादन करता है और धन अर्जित करके उसमें वृद्धि करता है तो इसे आर्थिक संवृद्धि कहा जायेगा। आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा एक संकुचित अवधारणा है। आर्थिक संवृद्धि आर्थिक विकास की भाँति संस्थागत कारणों को ध्यान में रखते हुए

सरचनात्मक परिवर्तन न होकर आय एवं उत्पादन आदि की मात्रात्मक वृद्धि से है। आर्थिक सवृद्धि का प्रत्यक्ष व सीधा सबन्ध जितना आय एवं उत्पादन आदि आर्थिक योगो की वृद्धि से है उतना मूल भूत आधारशिला या ढाँचे को तैयार करने से नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सवृद्धि का सबन्ध बड़े हुए उत्पादन और राष्ट्रीय आय से है। कालान्तर में आर्थिक सवृद्धि का अर्थ सामान्यतः कुल राष्ट्रीय आय के वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा आय में वृद्धि से है।

इस प्रकार आर्थिक सवृद्धि कुल मिलाकर राष्ट्रीय उत्पादन व राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि से है जिसे मौद्रिक रूप में समायोजित करने से है।

## आर्थिक विकास व आर्थिक संवृद्धि में भेद :

आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि के पूर्ववत् किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं हैं। इन दोनों में भेद करना सैद्धान्तिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीति निर्माण के दृष्टि कोण से आवश्यक है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक सवृद्धि के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

- 1 आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है जब कि आर्थिक सवृद्धि सकुचित रूप में आर्थिक विकास का एक अंग है।

- 2 आर्थिक विकास का सबन्ध अर्थव्यवस्था के बहुआयामी विकास एवं विभाजन से है जबकि आर्थिक सवृद्धि का सबन्ध उत्पादन एवं आय के आर्थिक योगों से है।
- 3 आर्थिक सवृद्धि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रात्मक वृद्धि या उसके आर्थिक चरों के वृद्धि से सबन्धित है जब कि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि को दर्शाता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक व नैतिक सभी कारण सम्मिलित होते हैं।

आर्थिक विकास व आर्थिक सवृद्धि के सम्बन्ध में सामान्य धारणा यह भी है कि आर्थिक विकास का प्रयोग विकसित देशों के लिए तथा आर्थिक सवृद्धि का प्रयोग विकासशील देशों के लिए होता है यह एक भ्रान्ति है। वास्तविकता तो यह है कि आर्थिक सवृद्धि एवं आर्थिक विकास एक दूसरे के अंग हैं और परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं इस लिए आर्थिक विकास व आर्थिक सवृद्धि के अन्तर की ओर बल देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

## **अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण :**

विश्व अर्थव्यवस्था में विकास के प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर परिवर्तन किए गए परम्परावादी विचार धारा के अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के तीन वर्गीकरण किए यथा विकसित, अल्पविकसित, तथा अविकसित परन्तु कालान्तर में चलकर 1960 के दशक तक संयुक्त राष्ट्र सभा के

अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित शब्द को परिभाषित करने में कुछ कठिनाई का अनुभव किया और नये सिरे से वर्गीकरण किये विकसित अर्थ व्यवस्थाएँ वे हैं जो विकास के उच्चतम प्रतिमानों को प्राप्त कर चुकी हैं। अल्पविकसित या अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जो विकास के प्रतिमानों को पाने के लिए अग्रसरित हैं। अविकसित अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जो स्थिरता वर्ग अवस्था में हैं। परन्तु नए वर्गीकरण के अनुसार अब मुख्य रूप से दो ही वर्गीकरण प्रचलित हैं एक तो विकसित और दूसरा विकासशील आज विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था स्थिरता की अवस्था में नहीं है केवल (अन्टार्टिका को छोड़कर) सभी अर्थव्यवस्थाएँ विकास की ओर अग्रसरित हैं उनकी गति भले ही मन्द हो।

विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित करने के मापदण्ड समय—समय पर परिवर्तित होते रहे। इस सदर्भ में विश्व बैंक ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनो में इन माप दण्डों को परिभाषित करने का प्रयास किया, विश्व बैंक प्रतिवेदन 1988 में विकास शील अर्थव्यवस्थाओं के समूह को समाप्त करके एक नया वर्गीकरण किया जिनमें निम्न आय, मध्यम आय तथा उच्चआयवाली अर्थव्यवस्थाएँ तथा गैर सूचित अर्थव्यवस्थाएँ वर्गीकृत की गई हैं। इसी श्रृंखला में विश्व बैंक प्रतिवेदन 1991 में निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ—साथ अन्य अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने विश्लेषणात्मक समूह भी प्रस्तुत किए जिसमें तेल निर्यातक देश, अतिऋण ग्रस्त

मध्यम आय वाले देश आदि को सम्मिलित किया गया विश्व बैंक ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी निम्न आय वाली और मध्यम आयवाली अर्थव्यवस्थाओं का भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें सब सहारा अफ्रीका, यूरोप, मध्यपूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा लैटिन अमेरिका आदि।<sup>1</sup>

विश्वबैंक प्रतिवेदन 1996 में अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण देश समूह के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए निम्नवत किया गया है।<sup>2</sup>

### 1 निम्न आयवाली अर्थ व्यवस्थाएँ

ये वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनकी वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति आय 725 यू0एस0 डालर या उससे कम थी।

### 2 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ

ये वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनकी वर्ष 1991 में प्रति व्यक्ति आय 725 यू0एस0 डालर से अधिक परन्तु 8956 यू0एस0 डालर से कम है।

### 3 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ

ये वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 1994 में 8956 यू0एस0 डालर से अधिक है।

---

1 विश्व बैंक प्रतिवेदन, परिभाषा एवं टिप्पणी 1991

विश्व बैंक प्रतिवेदन में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए एक नया समूह प्रस्तुत किया जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा गया, जिसके अन्तर्गत, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जापान, लैक्जिम वर्ग मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीटजरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य आदि हैं।<sup>3</sup>

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर अधिकतर विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ निम्न आयवाली और मध्यम आय वाली समूह में सम्मिलित हैं यथा कीनिया, नाइजीरिया, मंगोलिया, बाना, पाकिस्तान, चीन, मोरक्को, इंडोनेसिया, फिलिपाइन्स, बल्गारिया, रोमानिया तथा भारत की 1994 की वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 320 यू०एस० डालर थी।<sup>4</sup>

कुछ विद्वानों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में ही देखने का प्रयास किया जिनका अभिप्राय पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं से है। परन्तु विकसित एवं अल्पविकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जो भेद किया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय माना। यद्यपि कि इसमें मतभेद हो सकता है क्योंकि तेल निर्यातक देशों के कुछ ऐसे देश हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति आय बहुत अधिक है फिर भी वे विकासशील या अल्पविकसित देश हैं यद्यपि कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में

---

3 विश्व बैंक प्रतिवेदन, 1996 पृष्ठ 9

4. वही. पृष्ठ 188

गभीर अन्तराल विद्यमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या कम और ससाधन तुलनात्मक रूप से अधिक है जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति इसके विपरीत पायी जाती है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट अन्तर प्रस्तुत करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लक्षणों को स्पष्ट करना आवश्यक है।

## विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण :

यदि विश्व की समस्त विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण हम करके देखें तो भिन्न-भिन्न देश की भिन्न विशेषताएँ हैं परन्तु विकासशील अर्थव्यवस्था के कुछ मूलभूत विशेषताओं में एकरूपता है जो इस प्रकार हैं

- 1 एक विकासशील देश प्रमुखतया प्राथमिक अवस्था के उत्पादक देश के रूप में अवस्थित होता है इन देशों की आधिकतम जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होती है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि कार्यों को संपादित करने के लिए देश की कुल जनसंख्या का 62 से 70 प्रतिशत जन-समुदाय लगा होता है इसके बावजूद भी कृषि उत्पादन अपनी प्राथमिक अवस्था से उबरने में सक्षम नहीं होती इसका कारण यह है यहाँ कृषिकार्यों को संपादित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यन्त्रों, रासायनिकों की तकनीक परम्परागत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन एवं उत्पादिता निम्न होती है।



सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि से सम्बन्धित उत्पादन का भाग अधिक होता है परन्तु विकसित देशों में इनका योगदान कम होता है। यदि हम 1993 के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के भाग को देखें तो भारत का 31 प्रतिशत ब्राजील का 11 प्रतिशत योगदान कृषि स्रोत से रहा है। जब कि विकसित देशों का सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कम योगदान रहा है यथा यू०के० 2 प्रतिशत जर्मनी 1 प्रतिशत फ्रांस 3 प्रतिशत आदि<sup>5</sup> इस लिए यह कहा जा सकता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है।

- 2 विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में दूसरी विशेषता यह है कि इन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। इसी कारण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है।

विश्व बैंक प्रतिवेदन 1995 के एक प्रकाशन के अनुसार 1993 में विकासशील देशों की प्रतिव्यक्ति आय जहाँ 200 से 2000 डालर के बीच रही वहीं विकसित देशों की प्रतिव्यक्ति आय 19000 और 25000 डालर के बीच रही। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिव्यक्ति आय नीचे स्तर पर रही और भारत की तो मात्र 300 डालर प्रतिव्यक्ति आय रही है।

- 3 जिस प्रकार से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नीचा आय स्तर है, ठीक उसी प्रकार यहाँ निम्न जीवन स्तर भी पाया जाता है जीवन स्तर को स्वच्छता एवं सुख प्रदान करने वाली विभिन्न आधारभूत वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अत्यन्त कम है। भारत श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश भूटान आदि देशों में प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी ऊर्जा एवं प्रोटीन उपलब्धि अत्यन्त कम है। इसी प्रकार सेवाओं की कमी भी इनकी चेष्टाओं के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने में बहुत ही कम सहयोग प्रदान कर पाती है। जहाँ कनाडा में प्रतिव्यक्ति व्यापारिक ऊर्जा का वार्षिक उपभोग स्तर 10,009 किलो ग्राम तेल ऊर्जा के बराबर है वहीं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उनकी उपलब्धता बहुत ही कम है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत नीचा है क्योंकि यहाँ प्रति चिकित्सक जनसंख्या भार की अधिकता इसमें बाधक होती है।
- 4 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः जनसंख्या का भार अधिक होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था अपने भू क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या भार को ग्रहण किये हुये है। इसका प्रमुख कारण वहाँ की अशिक्षित जनसंख्या है। बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से पिछड़ी हुयी है। आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या का अभिप्राय वहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग का अनुत्पादक होना है। सामान्यतः

कुल जनसख्या मे स्त्रियो, बच्चो व बूढो का अनुपात कार्य करनेवाली जनसख्या मे अधिक है। जनसख्या का बडा भाग केवल उपभोक्ता जो अन्य उत्पादन करने वालो पर आश्रित है। इन देशो की जनसख्या के पिछडेपन का आभास इस बात से होता है कि जहाँ स्वीटजर लैण्ड, स्वीडन, अमेरिका, और कनाडा आदि देशो मे साक्षरता स्तर 99 से 100 प्रतिशत के मध्य है वही भारत और पाकिस्तान मे साक्षरता प्रतिशत 51 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार बंग्लादेश और नेपाल मे साक्षरता 26 प्रतिशत और 14 प्रतिशत है।<sup>6</sup>

- 5 विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे भारी सख्या मे छिपी हुयी बेराजगारी है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओ मे जिस अनुपात मे मानवीय श्रम उपलब्ध है उस अनुपात मे रोजगार की उपलब्धता नही होने के कारण अधिक मात्रा मे बेराजगारी की विद्यमानता है। विकासशील अर्थव्यवस्था मे अपने मानवीय श्रम का प्रयोग उचित मात्रा मे न कर पाना इसकी 'आर्थिक स्थिति को सुव्यवस्थित होने से वचित रखता है। और यहाँ के बच्चो के विकास मे बाधा है। यदि विकासशील देश अपने मानवीय श्रम का उपयोग औद्योगिक इकाइयो के स्थापित तथा सचालित करने मे करे तो इनकी अर्थव्यवस्था

सुदृढ़ हो सकती है। परन्तु अभी तक इनके द्वारा अपने मानवीय श्रम का उपयोग न कर पाना इनकी विशेषता रही है।

- 6 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग अल्पमात्रा में अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। यदि वैज्ञानिक रूप से ये देश अपने यहां उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का सदुपयोग करें तो इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है परन्तु विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक तकनीक के द्वारा इनका उपयोग किया जाता रहा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक ससाधनों का सदुपयोग कम और दुरुपयोग अधिक मात्रा में हुआ है। भारत के द्वारा अपने प्राकृतिक ससाधनों का प्रचुर मात्रा में उपभोग वैज्ञानिक तरीके से न कर पाने की वजह से आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की श्रेणी में खड़ा पाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वन सम्पदा का प्राकृतिक ससाधन के रूप में दुरुपयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक उदाहरण हो सकता है यहाँ आज भी ग्रामीण निवासी लकड़ियों पर भोजन बनाते हैं जिससे विकसित देशों के द्वारा भोजन बनाने पर खर्च की गयी ऊर्जा से कई गुना ऊर्जा खर्च की जाती है। इसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

तकनीकी रूप से विकासशील देश पिछड़े हुये हैं। जिसके कारण ये अपने प्राकृतिक ससाधनों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और यह इन देशों की प्रमुख विशेषता हो गयी है।

- 7 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि इन देशों में आर्थिक विषमता व्याप्त है, एक ओर लोग अपार धन अपने में समेटे हुये हैं तो दूसरी तरफ लोग अधनगे और भूखे, पशुओं की भॉति जीवन यापन करते हैं। विकास शील देशों कि इस विषमता के कारण ही पूँजी निर्माण और इसको गति करने प्रदान करने की क्षमता का हास होता है और लोगों में ऊँच- नीच की भावना के तहत वैमनष्य स्थापित हुआ है।

इस आर्थिक विषमता को यदि हम भारत के सदर्भ में विश्लेषण करें तो पाते हैं कि हमारी राष्ट्रीय पूँजी का 80 प्रतिशत भाग आज कुछ औद्योगिक घरानों के पास है और बाकी 20 प्रतिशत राष्ट्रीय पूँजी 90 करोड़ लोगों के मध्य है। इस आर्थिक विषमता के कारण ही भारतीय अपने मानवीय श्रम की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है और वाछित सीमा तक पूँजी निर्माण में योगदान नहीं कर रहा है। इसलिये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विषमता उसकी एक प्रमुख विशेषता है।

- 8 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पूँजी की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश विनियोग को बढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर होता है। जिसके कारण बचत का स्तर अत्यन्त कम होता है, जिसके फलतः विनियोग की मात्रा भी अत्यन्त कम होती है। अर्थव्यवस्था की माँग के

अनुसार विकासशील देश अपने उद्योग धन्धो में विनियोग नहीं कर पाते हैं। जिसके फलस्वरूप इन देशों की प्रौद्योगिकी का स्तर का होता है कम स्तर की प्रौद्योगिकी का स्तर कम होती है कम स्तर की प्रौद्योगिकी के कारण एक ओर इनकी उत्पादन लागत कम होती है तो दूसरी ओर इनकी गुणवत्ता में कमी रह जाती है। यू०एस०ए०, यू०के०, कनाडा, जापान आदि देशों में सबल पूँजी के आधार के कारण प्रौद्योगिकी का स्तर ऊँचा है जब कि भारत और अन्य विकासशील देशों यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान आदि देशों की प्रौद्योगिकी का स्तर नीचा है। अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय आय का केवल 5 से 10 प्रतिशत ही पुनर्विनियोग के रूप में प्रयुक्त हो पाता है। जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत 15 से 25 तक है।

- 9 लगभग समस्त विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक अर्थव्यवस्थाएँ पायी जाती हैं। इन देशों में एक ओर बाजार अर्थव्यवस्था तो दूसरी ओर निर्वाह अर्थव्यवस्था पायी जाती है। बाजार अर्थव्यवस्था इन देशों में नगरीय प्रकृति की या नगरों के निकट होती है और निर्वाह अर्थ व्यवस्था दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है। नगरीय प्रकृति की अर्थव्यवस्था के तहत जीवन यापन करने वाले को लगभग सारी सुख सुविधाओं की सम्पन्नता उपलब्ध होती है। परन्तु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कृषि

सम्बद्ध क्रियाओं के उत्पादन के तहत जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होने के कारण यहाँ के लोगो का जीवन स्तर भी निम्न होता है। जो यहाँ की गरीबी और पिछड़ेपन के सत्य को सत्यापित करता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में नगरीय अर्थव्यवस्था सीमित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक होती है। भारत, पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान आदि देशों में 36 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या नगरों में रहती है और शेष जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में रहती है। जबकि विकसित देशों में स्थिति विपरीत है। स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, यू०एस०ए० आदि में 77 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है।

- 10 अल्पविकसित देशों के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में एक प्रमुख विशेषता है कि निर्यात परम्परागत वस्तुओं, प्रारम्भिक उत्पादों तथा कच्चे माल आदि तक ही सीमित रहता है। जब कि आयात का अधिकांश भाग निर्मित वस्तुओं यथा मशीनरी आदि के रूप में होता है। इनके द्वारा अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का आयात किया जाना एवं अपने ही द्वारा निर्यात कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं का आयात भी किया जाता है। इन देशों का व्यापार सतुलन सदैव ऋणात्मक रहता है और इसको सतुलित करने के लिये विदेशी ऋणों तथा अपने प्राथमिक कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर

होना पड़ता है । विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार असंतुलन प्रमुख विशेषता रही है ।

उपर्युक्त विशेषताओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था अपनी दरिद्रता के दुश्चक्र में फंसी हुयी है । जिससे निकल पाना निकट भविष्य में इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए सम्भव नहीं प्रतीत होता है । नवीन आर्थिक संरचना, आर्थिक सुधार एवं अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन एवं विश्व व्यापार संगठन कहीं तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास को त्वरित कर सकेगा, यह समय ही बतायेगा ।



## अध्याय : 3

*भारतीय अर्थव्यवस्था  
का अतीत एवं वर्तमान तथा  
अतीत वर्तमान में विचलन*

सृष्टि की सरचना मे कालचक्र का अपना विशिष्ट स्थान होता है वह अपनी गति से बेरोक टोक चला करता है। व्यक्ति व राष्ट्र व प्राकृतिक ससाधनो पर कालचक्र का प्रभाव पडता रहता है। समय की गति एव मानवीय तथा भौतिक पदार्थो व साधनो मे गहरा सह-सम्बन्ध पाया जाता है। हजारो वर्षो के इतिहास इस बात के साक्षी है। समय के साथ-साथ साम्राज्यो के उत्थान पतन एव गठन तथा उनकी सीमाओ मे परिवर्तन होते रहे है और भविष्य मे भी होते रहेगे। इसी प्रकार आर्थिक ससाधनो एव अर्थव्यवस्थाओ के स्वरूप एव आकार मे भी परिवर्तन होते रहते है। चाहे यूरोप महाद्वीप हो या एशिया इंग्लैण्ड हो या अमेरिका, भारत हो या चीन सभी राष्ट्रो के जीवन मे उतार चढाव देखने को मिले है। सम्पन्नता, विपन्नता तथा स्थिरता की अवस्थाए प्राय सभी राष्ट्रो के जीवन मे देखने को मिलती रही है। आज विश्व के पटल पर बडी तेजी से परिवर्तन हो रहे है। किसी भी राष्ट्र के अर्थिक जीवन को वहाँ उपलब्ध ससाधन, राजनीतिक दशाए, सामाजिक सरचना आदि प्रभावित करते है। इस परिप्रेक्ष्य मे भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत एव वर्तमान तथा वर्तमान से विचलन का विश्लेषण किया जा सकता है।

## **भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत :**

भारतीय सस्कृति एव सभ्यता विश्व की अति प्राचीनतम सभ्यताओ मे से एक है। तमाम धर्मग्रन्थो एव वेदो मे भारत की समग्र सम्पन्नता का वर्णन किसी न किसी रूप मे किया गया है भारत वह भूमि रही है जहाँ विदेशी आक्रमणकारियो ने अनेको बार आक्रमण किए और भारत पर आधिपत्य जमाया तथा देश के वैभव को

लूटा—खसोटा। इस प्रकार का क्रम सैकड़ों—सैकड़ों वर्षों तक एक के बाद एक चलता रहा। यह भूमि सम्राज्यों के उत्थान एवं पतन की भूमि रही है। भारत की सम्पन्नता को देखकर ही लोग इस ओर आकर्षित होते रहे हैं। कितने ही साम्राज्यों ने भारत के वैभव एवं सम्पदा से ही अपने—अपने आर्थिक आधार बनाये एवं सम्राज्यों का विकास किया।

भारत का अतीत बहुत ही वैभवशाली रहा है। भारत के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिये हमें पाँच हजार वर्ष पूर्व के प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों के विश्लेषण करने पड़ते हैं। जिससे मुझे यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्ण रूप से विकसित नगरीय अर्थव्यवस्था थी जिसे हम आज सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 1299600 वर्ग किलोमीटर रहा है।<sup>1</sup> जिस समय यहाँ के लोग पूर्ण विकसित अवस्था का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय इनका रहन सहन, खान—पान, इत्यादि सभी क्रिया कलाप आधुनिक नगरीय अर्थव्यवस्था के समान रहे हैं।

परन्तु कालचक्र के घातक प्रभाव से यह अर्थव्यवस्था भी अपने को न बचा सकी और लगभग एक हजार वर्ष तक स्थिर रहने के बाद पूर्ण रूप से विनिष्ट हो जाती है। फिर ऋग्वैदिक काल का प्रादुर्भाव होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नए सिरे से उद्भव तथा विकास होता है, इस काल में भी पशुधन की प्रचुरता के कारण जनजीवन सुखमय रहता है। फिर धीरे—धीरे ऋग्वैदिक ग्रामीण व्यवस्था का

विकास होता है, जो बाद में चल करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होती है। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के विश्लेषण से हमें यह विदित होता है कि उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था थी। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने गाँवों से ही कर लेते थे क्योंकि एक गाँव में ही कपड़ा धोने वाला धोबी, कृषि कार्यों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों का निर्माण करने वाला लोहार, नाई और बढई आदि एक ही गाँव में रहते थे जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निरन्तर सीढ़ियों को चढ़ते हुए घनानन्द के शासन काल में अपने पूर्ण रूप से वैभवशाली अर्थव्यवस्था को प्राप्त करती है। जिस अर्थव्यवस्था को सिकंदर के आक्रमण ने भी भेदने की क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सका आगे चलकरके इस अर्थव्यवस्था को एक कुशल शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा एक कुशल प्रधान मंत्री विष्णु गुप्त की प्राप्ति होती है।

इन दोनों व्यक्तियों के अथक प्रयास के फलस्वरूप आधुनिक भारतीय उप महाद्वीप का अधिकतम भू-क्षेत्र एक राजनैतिक एवं आर्थिक सूत्र में बंधा और अपनी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक सुचारु रूप से संचालित करने में सफलता प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त द्वारा रचित पुस्तक 'अर्थशास्त्र' का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था परिपक्वता की

अवस्था लगभग प्राप्त कर लेती है इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चर्मोत्कर्ष को संचालित करने के लिए विष्णुगुप्त द्वारा लिखित रूप से कानूनी राज्यादेश तैयार किए गए और उनको कार्यरूप प्रदान किया गया। उस समय विविध प्रकार के करो का संग्रह किया जाता था। व्यवसायियों के लिए मार्गों की सुरक्षा प्रदान की गई जिससे उनके आर्थिक क्रिया कलापो में वृद्धि हुई, व्यवसाय का अधिकाधिक विकास हुआ, राजकीय आय में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ हुई। इसी अर्थव्यवस्था के बल पर एक विशाल राजनैतिक एवं आर्थिक आधारशिला का प्रादुर्भाव हुआ जिस पर चन्द्रगुप्त ने अपने शासन रूपी मकान का निर्माण कर एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन किया। इसका सत्यापन प्लिनी के इस अभिव्यक्ति से होता है कि चन्द्रगुप्त की सेना में छ लाख पैदल सिपाही तीस हजार घुड़सवार और नौ हजार हाथी थे। एक अन्य स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास आठ हजार रथ थे, इस विशाल सैन्य व्यवस्था को स्थापित करने में भारी मात्रा में आर्थिक खर्च भी हुए होंगे जिससे यह निश्चित होता है कि मौर्यों के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी।

चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित अर्थव्यवस्था अशोक के शासन काल में अपनी चर्मोत्कर्ष को प्राप्त करती है। और दुर्भाग्यवश अशोक के बाद ही इसके क्षरण की शुरुवात होती है और आगे चलकर गुप्त काल में पूर्णतया पुनरोत्थान को प्राप्त

करती है । गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है क्योंकि इस काल में सोने के सिक्कों की प्रचुरता इसकी आर्थिक स्थिति की सुदृढता को सत्यापित करता है ।

## ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था :

ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था परम्परागत एवं सुदृढ थी । भारत के विषय में सर्वाधिक दिलचस्प तथ्य यह है कि उसकी धरती सवृद्धि है और लोग गरीब हैं ।<sup>2</sup> रजनी पामदत्त ने यह तथ्य व्यक्त किया था कि भारत का वैभव उसकी प्राकृतिक सम्पदा, उसके प्रचुर साधन, उसकी अन्तःनिहित सवृद्धि जिसमें उसकी सम्पूर्ण वर्तमान आबादी को और उससे अधिक आबादी को सुखी बनाने की क्षमता है ।<sup>3</sup> ऐतिहासिक तौर पर छिट-पुट साहित्य से यह विवरण प्राप्त होता है कि यूनानियों के आक्रमण एवं आगमन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत थी । मौर्य वंश एवं गुप्त काल के दस्तावेजों एवं प्रशासनिक प्रणाली से यह स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि भारत एक सम्पन्न राष्ट्र था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इन महान शासकों ने स्वीकारा और स्थान दिया था । परन्तु इन दो महान शासकों के पश्चात् भारत का राजनैतिक एवं आर्थिक स्वरूप टूटता और जुड़ता रहा तथा धीरे-धीरे छोटे-छोटे प्रान्तों एवं शासकों में विभाजित होता रहा जिसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा । यह प्रक्रिया दीर्घ काल तक चलती रही और इस्लामिक एवं मुगल साम्राज्यों की स्थापना के परिणाम स्वरूप भी भारत ने

2 डार्लिंग, एम एल पंजाब दि पंजाब पीजेन्ट इन प्रासपर्टी एण्ड डेहलु 1925 पृष्ठ 73

3 दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, 1977, पृष्ठ 43

अपना आर्थिक वैभव काफी हद तक बनाये रखा। ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था एक आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अतिरेक सृजक अर्थव्यवस्था थी लेकिन अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण था और ग्रामीण समुदाय श्रम विभाजन के आधार पर आर्थिक क्रियाएँ संचालित करता था और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन ग्रामोद्योगों के माध्यम से हाता था। प्रत्येक गाँव एक स्वतन्त्र इकाई था। मुगलों के शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप यथावत बना रहा। हमारे परम्परागत आर्थिक ढाँचे को मुगलों ने बर्बाद किया मुगल वश का अन्तिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब के निजी चिकित्सक बेनिस निवासी मनुची ने कहा था कि मुर्शीदाबाद (तत्कालीन बंगाल की राजधानी) एवं लंदन में फर्क इतना ही है कि मुर्शीदाबाद लंदन की तुलना में अधिक सवृद्ध शाली है।

18वीं शताब्दी तक भारत की आर्थिक दशा उन्नत थी तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठन की भारतीय प्रणाली संसार के किसी भी दूसरे भाग में प्रचलित प्रणालियों से टक्कर ले सकती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से पूर्व भारतीय समाज अपने आर्थिक आधार की दृष्टि से पूँजीवाद से पहले के मध्य युगीन यूरोपीय समाजों से भिन्न था।<sup>4</sup>

भारतीय समाज पश्चिमी समाज के आगमन के पूर्व एक सुव्यवस्थित इकाई था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत की सामाजिक व्यवस्था परिवार और

---

4 वेश आस्ते, दि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इण्डिया 1936 पृष्ठ 5 भारत में अर्थशास्त्री सम्बन्धी विचारों का विकास 1980 पृष्ठ 1 में पी० के० गोपाल कृष्णन द्वारा उद्धृत है

जाति के प्रति अपने दायित्वो को पूरा करती थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता, काम करने वाली ग्राम पचायतो पर आधारित थी और इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रो के मध्य व्यापार तथा वाणिज्य पर आधारित श्रेणियो तथा नियमो के प्रति भी दायित्व थे। ग्राम वासियो का मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन तथा कुटीर उद्योग था।<sup>5</sup>

ब्रिटिश शासन से पूर्व कितने ही राजवशो का अवसान व उदय हुआ परन्तु भारतीय सामाजिक व आर्थिक संरचना को नही प्रभावित कर सके। भारत की औद्योगिक एवं दस्तकारी क्षमता इतनी शक्ति थी की उनके द्वारा निर्मित वस्तुओ के उत्पादन व निर्यात मे विश्व विख्यात था। उदाहरण के लिए भारत उस समय लौह निर्मित वस्तुओ का निर्यात करता था। जब दुनिया के बहुत से देश उसकी निर्माण प्रक्रिया से अपरिचित थे। हजारो वर्ष पूर्व भारतीयो द्वारा कुटीर उद्योगो के माध्यम से निर्मित पुरी एवं सोमनाथ मंदिरों के कपाट एवं गर्दर तथा मेहरौली का लौह स्तम्भ भारत के लौह इस्पात प्रक्रिया के मूक साक्षी है।

ब्रिटिश शासको के आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता एवं अतिरिक्त सृजन का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि भारत विश्व बाजार मे लगभग तीन हजार वर्षों तक सूतीवस्त्र निर्माण एवं निर्यात मे अपना एकाधिकार बनाए हुए था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोलिनक्लार्क ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1895 मे भारत मे जो वास्तविक मजदूरी दरे प्रचलित थी



वे जहाँगीर कालीन मजदूरी दरो की तुलना में  $1/4$  थी।<sup>6</sup> इसी प्रकार प्रो० राधाकमल मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "एकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया" में कहा है कि सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मजदूरी की जो दरें प्रचलित थीं उनकी तुलना में ब्रिटिश शासन काल में आधी से भी कम थी। लार्ड क्लाइव ने 1757 में बंगाल की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद को देखने के बाद यह लिखा था कि 'यह शहर उतना ही विस्तृत एवं आबादी वाला है जितना की लन्दन फर्क इतना है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास लन्दन की तुलना में असीम सम्पत्ति है"।<sup>7</sup>

भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत के विषय में विदेशी यात्रियों ने भी अपने यात्रा समरणों में भारत की सम्पदा एवं वैभव का उल्लेख किया है। उन दिनों आम तौर पर जनता में सवृद्धि थी। 17वीं सदी में भारत की यात्रा का विवरण लिखते समय टेविर्नियर ने टिप्पणी की कि "छोटे-छोटे गावों में भी चावल, आटा, मक्खन, दूध, चीनी तथा मिठाइयाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं।"<sup>8</sup>

इन सभी तथ्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तर किसी भी दृष्टि से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था से कम नहीं था। यद्यपि इस विषय में लोगो ने अपने मतभेद व्यक्त किए हैं पर्याप्त प्रामाणिक साहित्य की उपलब्धता के अभाव के सम्बन्ध में भी मतभेद है। यद्यपि कुछ विद्वानों एवं विचारकों

6 सिंह चरण भारत की भयावह अर्थिक स्थिति पृष्ठ 4

7 औद्योगिक आयोग प्रतिवेदन पृष्ठ 249 पर अद्धत्ता रजनी पामदत्त द्वारा आज का भारत में वर्णित पृष्ठ 44

8 दत्त रजनी पाम आज का भारत, पृष्ठ 44

यथा आर०सी० दत्त, डब्लू०एच० मोलैड, दादा भाई नौराजी, रजनी पाम दत्त आदि के लेखन से भारत की ब्रिटिश शासन से पूर्व सम्पन्नता का आभास मिलता है। इस बात की पुष्टि दूसरे देशों से आये यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी होती है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्था एवं उसके विविधिकरण को कृषि, उद्योग एवं व्यापार तथा परिवहन से देखा जा सकता है।

## कृषि -

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारम्भ से ही कृषि आधारित रही है वैसे भी आज की जो उन्नत अर्थव्यवस्था है उनके भी विकास का प्रारम्भिक आधार कृषि ही रही है, भारी भरकम उद्योग कभी भी विकास के मूलाधार नहीं रहे हैं, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय सामंती व्यवस्था में भूमि किसी की निजी सम्पत्ति नहीं थी। भूमि हिन्दू शासन काल में ग्राम समुदाय के अधीन थी। भू-स्वामित्व, भारत में साम्राज्यवाद के भूस्वामित्व अर्थ से भिन्न था। इसी कारण भारतीय सामंती व्यवस्था एवं यूरोपीय सामंती व्यवस्था में बुनियादी फर्क था। मुस्लिम शासकों ने भी भू-क्षेत्र में बदलाव हुआ स्वरूप ही अपनाया यद्यपि की शेरशाह और अकबर ने भूप्रणाली एवं भूराजस्व में परिवर्तन की कोशिश की।

भारत में कृषि तौर तरीकों में परिवर्तन तथा कृषि सुविधाओं के विस्तार के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावनाएँ समय-समय पर व्यक्त की गईं। कुछ विचारकों एवं विद्वानों ने इस बात का वर्णन किया है कि अंग्रेजी शासन के पूर्व भारतीय कृषि का स्वरूप एवं तरीका आदिम एवं परम्परावादी था। परन्तु उस समय

भी खाद्यान फसलो के साथ-साथ व्यापारिक फसलो यथा जूट, कपास, तम्बाकू एव मूँगफली आदि की पैदावार की जाती थी। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में भूराजस्व दरे ब्रिटिश शासन के पूर्व की अवधि से ऊँची थी। ब्रिटिश शासन से पूर्व सरकार द्वारा बहुत से सिचाई प्रबन्ध किए जाते थे।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सम्राज्यवाद से पूर्व भारतीय कृषि दशा अच्छी थी। उस समय फसलो में परिवर्तन एव जमीन को परती छोड़ना जिससे ऊपरी शक्ति में वृद्धि हो की व्यवस्था प्रचलित थी।

## उद्योग :

साम्राज्यवाद के आगमन पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ-साथ उद्योग अपनी अच्छी दशा में थे। भारत का औद्योगिक आधार बहुत मजबूत था यद्यपि कि लघु एव कुटीर उद्योग ही औद्योगिक उत्पादन के स्रोत थे। उस समय हमारे परम्परागत उद्योग ग्रामीण एव नगरीय आर्थिक संरचना के आधार थे, क्योंकि भारतीय गाँवों में स्वात्मनिर्भर था। सीधे-सादे औजारों से की जाने वाली दस्तकारी पर आधारित आत्मनिर्भर गाँव अंग्रेजों से पहले के भारतीय समाज का बुनियादी लक्षण था।<sup>9</sup> ये उद्योग न केवल घरेलू आवश्यकता की वस्तुएँ उत्पादित करते थे, बल्कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान भी उत्पादित करते थे। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ अपनी गुणवत्ता, कलाकारी एव नमूने के लिए विश्वविख्यात थी। अंग्रेजों के

पूर्व भारत ऊनी एव सूती वस्त्रो, जेवरात तथा अन्य धातु निर्मित वस्तुओ के लिए मशहूर था ।

अंग्रेजी साम्राज्य के पहले भारत का औद्योगिक सामान विश्व बाजार मे काफी चर्चित था, जिसकी पुष्टि 1916—18 मे औद्योगिक आयोग ने की है। जब यूरोप के सौदागर प्रथम बार भारत पहुँचे तो देखा कि भारत का औद्योगिक विकास किसी भी मामले मे विकसित यूरोपीय देश से कम न था ।<sup>10</sup>

## व्यापार

भारत का प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत का मिस्र से बहुत बड़ी मात्रा मे व्यापारिक सम्बन्ध था। भारत मे ढाका निर्मित मलमल एव देश के अन्य भागो मे निर्मित सिल्क का निर्यात किया जाता था। उस समय निर्यात की हमारी प्रमुख वस्तुएँ सूती कपडा हाथी दाँत रग, इत्र, मसाले तथा कलात्मक वस्तुएँ थीं। तत्कालीन हिन्दू एव मुगल शासको ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने की सकारात्मक नीति अपनायी थी, इसलिए मुगलो ने थलमार्गों का निर्माण भी कराया था जिससे कि पड़ोसी देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्ध कायम किए जा सके ।

इसके अतिरिक्त अंग्रेजो के पहले के भारत मे नगरीय क्षेत्र मे व्यापारियो का एक वर्ग था जो कि अर्थतन्त्र के आवश्यक आधार थे । भारतीय व्यापारी बहुत ही

---

<sup>10</sup> औद्योगिक आयोग प्रतिवेदत, 1961—78 पृष्ठ 6 ।

सक्रिय एव समृद्ध थे, उनके स्वयं के अपने परिवहन साधन थे और वे बाजार का सर्वेक्षण आदि भी करते थे। “भारतीय व्यापारी समुद्री जोखिमों को उठाते थे वे लाभ कमाते थे और उसमें से कल्याण कार्यों के लिए दान तथा राजा को भी कर देते थे”।<sup>11</sup>

## पोत निर्माण :

प्राचीन काल में व्यापार प्रायः जल मार्गों द्वारा ही होता था। अतः भारतीय व्यापारी नौकाओं या जहाजों द्वारा अपना व्यापार किया करते थे। इस सन्दर्भ में भारतीय जहाज निर्माण कला विश्व में अद्वितीय थी। भारत की नौकाओं एवं जहाजों निर्माण की कला का विवरण आदि धार्मिक ग्रन्थों एवं विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तान्तों से मिलता है। यूनानी यात्री मेगस्थनीज द्वारा किए गये भारत का वर्णन एवं चौदहवीं शताब्दी के विद्वान श्री रैनेल द्वारा रचित पुस्तक ‘हिन्दुस्तान अथवा मुगल साम्राज्य का मानचित्र’ में उल्लेख मिलता है।

अशोक ने अपने शासन काल में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र एवं पुत्री को जल मार्ग से ही बाहर भेजा था। भारत में निर्मित मजबूत जहाजों के माध्यम से ही ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका, मालाया एवं पूर्वी द्वीपसमूहों से व्यापारिक सम्बन्ध थे।

इस विषय में डा० आर०के० मुकर्जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘भारतीय पोत चालन का इतिहास’ में लिखा है कि भारत की प्राचीन सभ्यता इसलिए ससार के

कोने कोने तक पहुँची कि इसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति प्राप्त थी । इतिहास मे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जब सिकन्दर वापस जा रहा था तो 2000 भारतीय जहाजो पर अपने सेना एव समान ले गया था । इस प्रकार जहाज निर्माण की प्रक्रिया के अनेक उदाहरण मिलते है ।

## ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था :

भारत की प्राकृतिक संपदा एव विशाल बाजार को देखकर ही अंग्रेज भारत की ओर आकृष्ट हुए थे । और यह शुरुआत ईस्ट इंडिया कम्पनी से 1600 ई० मे की गयी थी । यद्यपि साम्राज्यवाद की जडे सत्रहवी एव अठरहवी सदी के मध्य मजबूत हुई । अंग्रेज कम्पनी के माध्यम से भारत मे व्यापार करने आये थे परन्तु धीरे-धीरे उन्होने अपना आधिपत्य कायम कर लिया । ब्रिटिश साम्राज्य की सम्पूर्ण अवधि मे भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चरणो एव उतार चढाव से गुजरना पडा । ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर हालत मे थी जैसा कि पहले कहा जा चुका है । लगभग 200 वर्षों के शासन के दौरान अंग्रेजो ने भारत के वैभव को लूटा खसोटा एव भारतीय अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया । अंग्रेजो ने खेत से उद्योग तक, गाँव से नगर तक के आर्थिक ढाँचे को तोड डाला और एक नयी संस्कृति, जो शोषणकारी थी, को जन्म दिया ।

अंग्रेजों ने भारतीय पूँजी को दबाकर आर्थिक तंत्र को कमजोर कर दिया  
 एवं अंग्रेजी पूँजीपत वर्ग का प्रभुत्व कायम कर दिया । अंग्रेजों ने भारत का शोषण  
 निम्न रूपों में किया ।

- 1 व्यापारिक पूँजी के रूप में ।
- 2 औद्योगिक पूँजी के रूप में ।
- 3 महाजनी पूँजी के रूप में ।

## 1 व्यापारिक पूँजी के रूप में

व्यापार के नाम पर भारत में कम्पनी द्वारा लूट खसोट की जा रही थी ।  
 बंगाल के नबाव ने सन् 1762 में अंग्रेज गवर्नर के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें  
 इस बात का उल्लेख था कि, "कम्पनी नुमाइन्दे हर परगना, गाँव, कारखानों में,  
 नमक, सुपारी, घी, चावल, मांस, मछली, टाट, अदरक, तम्बाकू, अफीम आदि का  
 क्रय विक्रय जारी रखते थे वे जबरन रैयतों, सौदागरों आदि से चौथाई मूल्य पर  
 माल हथिया लेते थे । इसके साथ ही रैयत के साथ जबरदस्ती एवं अत्याचार करके  
 एक रुपये के स्थान पर 5 रुपये वसूल करते थे ।"<sup>12</sup> इसी प्रकार सन् 1772 में एक  
 अंग्रेजी व्यापारी विलियम बोल्ट्स ने 'कन्सीडरेशंस आन इण्डियन अफेयर्स' नामक  
 प्रकाशन में वर्णन किया था कि "व्यापार के नाम पर व्यापार कम एवं लूट अधिक  
 थी ।" इसी प्रकार सन् 1858 में हाउस आफ कामन्स में यह बयान दिया गया था

---

<sup>12</sup> दत्त आर सी, भारत का आर्थिक इतिहास, भाग-1, पृष्ठ 15

कि, "इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं पायी गयी। जितनी सन् 1765-1784 तक ईस्टइण्डिया कम्पनी की सरकार थी।"<sup>13</sup> अतः व्यापारिक पूँजी के नाम पर भारत का शोषण किया गया।

## 2 औद्योगिक पूँजी के रूप में .

यदि ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति का जायजा लिया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय पूँजी की लूट से ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की नींव खड़ी की गयी थी, भारतीय उद्योगों को दफनाकर उनकी कब्र पर ब्रिटिश उद्योग का निर्माण किया गया था। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का स्रोत एवं ब्रिटिश निर्मित माल का बाजार बनाया था, जिससे भारतीय उद्योगों का पतन एवं ब्रिटिश उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ से औद्योगिक पूँजी की आँख में उन्मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति अपनाकर भारतीय औद्योगिक पटल का शोषण किया गया। मार्क्स ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इंग्लैण्ड की पूँजी उपनिवेशों की लूट थी और अठारहवीं शदी में इंग्लैण्ड में अचानक बड़े पैमाने पर जो पूँजी एकत्र हुई वह ज्यादातर भारत की लूट व शोषण से इकट्ठा हुई थी। भारत में केवल उन्हीं उद्योगों के विकास को छूट दी गयी थी जो भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक थे।

---

13 दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, मैकमिलन ऑफ इण्डिया लि०, 1977, पृष्ठ 127-128



### 3. महाजनी पूँजी के रूप में -

भारत में सामंती वर्ग का पूँजीपति के रूप में उदय ब्रिटिश पूँजीवादी हितों के आधार पर ही हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक पूँजी के शोषण के तरीकों को समाप्त न करके उसे महाजनी पूँजी के रूप में रूपान्तरित कर दिया गया। भारत में अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन के तहत भारत में परिवहन तथा यातायात के साधनों का विकास तथा यूरोप की भाँति बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय जनता का हित न होकर, ब्रिटेन की व्यापारिक एवं सामरिक आवश्यकता की पूर्ति करना था। भारत की जनता से लूट करके भारत में एकत्रित पूँजी ब्रिटेन की ओर से भारत में निवेशित पूँजी कर्ज के रूप में दी गयी। जिससे उल्टे भारत से रायल्टी एवं ब्याज वसूल किया जाता था।<sup>14</sup>

### ब्रिटिश काल में आर्थिक शोषण :

ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान व्यापार के रूप में भारत का आर्थिक शोषण किया गया और यह शोषण की प्रक्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लम्बे समय तक जारी रही जब तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में कायम रहा। इस उपनिवेशी शोषण का एक मात्र लक्ष्य रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया जाये और भारत से अधिक मात्रा में लाभकमाया जाय। ईस्टइण्डिया कम्पनी नबाबों से भारी मात्रा में धनराशि वसूल करती थी और इस श्रृंखला में नबाब भी बदलते रहे। इसका स्पष्ट प्रमाण बंगाल रहा जहाँ एक के बाद एक नबाब बदलते रहे। एक

---

14 दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, दि मैकमिलन ऑफ इण्डिया, 1977, पृष्ठ 156

अनुमान के अनुसार ईस्टइण्डिया कम्पनी ने 1757 से 1765 के बीच बंगाल में कई नबाबों को बदला और उनसे 60 लाख पौण्ड वसूल किए। जमींदारों की नियुक्ति में भी नकद राशि प्राप्त करते थे।

ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों का बड़ी बेरहमी के साथ विनाश किया गया। यहाँ तक कि भारतीय जुलाहों एवं कारीगरों के अँगूठे कटवा लिए गए। ऐसा कहा जाता है कि 18 वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय जुलाहों एवं कारीगरों के हड्डियों से भारत के मैदान सफेद हो गए तथा हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों को दफना कर उनकी कब्र पर इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े उद्योगों की नींव खड़ी की गई। कच्चे पदार्थों की आपूर्ति पर इंग्लैण्ड का पूरा-पूरा अधिकार हो गया था जिससे भारी कीमत वसूलते थे। भारतीय उद्यमियों को जहाँ एक ओर कच्चा पदार्थ ऊँची कीमत पर मिलता था वहीं दूसरी ओर तैयार माल नीचे मूल्यों पर बेचने की बाध्यता थी। ऐसी स्थिति में भारतीय कारीगरों एवं बुनकरों को अपना व्यवसाय जारी रख पाना असम्भव हो गया। औद्योगिक क्षेत्र की भौति ही कृषि क्षेत्र में भी शोषण की प्रक्रिया जारी रही किसानों को विवश होकर अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचना पड़ता था। अंग्रेजों ने चम्पारन में किसानों को एक निश्चित क्षेत्र पर नील की खेती के लिए बाध्य किया इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के कारिन्दे जमींदार भी किसानों का शोषण करते रहे। भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले मलमल एवं कपड़ों के आयात कर की दर 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 78 प्रतिशत

कर दी गयी थी। इस प्रकार ब्रिटेन में भारत से जाने वाले सामान पर भारी निरोधात्मक कर लगाये गये।

ब्रिटिश सरकार ने सरकारी खरीद एवं सरकारी सेवाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापक शोषण किया। सरकारी खरीद के रूप में सन् 1921-22 में और 1928-29 में क्रमशः 16.25 करोड़ रुपये और 10.10 करोड़ रुपये का सामान ब्रिटेन से आयात किया गया।<sup>15</sup> ब्रिटिश शासन काल में भारत में तैनात उच्च अधिकारी अंग्रेज थे तथा निम्न तबके के कर्मचारी एवं सैनिक ही भारतीय होते थे। जिससे उच्च अधिकारी बड़ी मात्रा में धनराशि वेतन एवं पेशन आदि के रूप में भारत से इंग्लैण्ड ले जाते थे। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वित्त का एक भारी बोझ पड़ता था। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति भी भारत के प्रतिकूल थी।

## भारतीय स्थिति एवं अतीत से विचलन :

अतः ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का अनेकों प्रकार से आर्थिक शोषण किया गया एवं भारत के धन एवं वैभव को लूट कर इंग्लैण्ड में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया त्वरित की गयी एवं औद्योगिक क्रान्ति की सजा दी गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व सध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था सक्रमण कालीन स्थित में थी एक ओर युद्ध से जर्जर तथा दूसरी ओर विभाजन से प्रभावित थी। जिसे पुनर्निर्मित व

---

15 त्रिपाठी, डा० बद्री विशाल, भारतीय अर्थव्यवस्था—नियोजन एवं विकास किताब  
महल, 1997 पृष्ठ 45

पुनर्स्थापित करना था। 1948 में जब प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की तो उसमें भारत के औद्योगिक विकास की रूप रेखा निर्मित की गई तथा 1950 में संविधान की मूलभावना के आधार पर सामाजिक न्याय समता एवं शोषण विहीन समाज एवं अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गयी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अंगीकार करते हुए नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से चहुँमुखी विकास का मार्ग अपनाया गया वर्ष 1950-51 में इस बात पर बल दिया गया कि कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का संतुलित विकास करते हुए सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाय इसी क्रम में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के सुधार एवं विकास हेतु विभिन्न प्रयास प्रारम्भ किए गए। आज वर्तमान में पचास वर्षों की लम्बी यात्रा के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को कुछ मुख्य बिन्दुओं के अन्तर्गत विश्लेषित किया जा सकता है।

## 1. कृषि की स्थिति .

देश विभाजन के पश्चात् कृषि की दशा खराब हो गयी थी और भारत न केवल खाद्यान्नों का आयातक बल्कि कृषि आधारित उद्योगों के कच्चे माल का भी आयातक बन गया। कृषि गतिहीन अवस्था में बनी हुई थी, उत्पादन और उत्पादितता बहुत निम्न थी, देश के सामने खाद्यान्न संकट था जिसे आयात द्वारा पूरा किया जाता रहा। इसी लिए पहली योजना के प्रारम्भ में भूमि सुधारों के अन्तर्गत विभिन्न संस्थागत एवं संरचनात्मक कदम उठाए गए जिससे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण

क्षेत्र कृषि का विकास किया जा सके। भारत के खाद्य संकट पर फोर्ड फाउन्डेशन व्यक्ति की और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सघन कृषि कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। वर्ष 1966—67 में भारतीय कृषि संसाधन परिषद के वैज्ञानिकों ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के बीजों का अविष्कार कर कृषि विकास की नई प्रवृत्ति को जन्म दिया जिसे हरित क्रान्ति की संज्ञा दी गई। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था तथा भूमि उपयोग के अनुकूलतम प्रयोग के प्रयास अप्रार्याप्त थे। परन्तु विभिन्न योजनाओं में कृषि क्षेत्र के महत्व पर ध्यान दिया गया तथा सिंचाई सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 1950—51 में देश में कुल सिंचित क्षमता 12.9 मिलियन हेक्टेयर थी जो कि 1990 में बढ़कर 38 मिलियन हेक्टेयर हो गई इसी प्रकार खाद्यान्नों का देश में कुल उत्पादन 1950—51 में मात्र 54.9 मिलियन तथा जो वर्तमान समय में 1996—97 में बढ़कर 196.2 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार वर्तमान समय में खाद्यान्नों के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की है बल्कि निर्यात संभावनाएं भी निर्मित की हैं।

## 2. उद्योग की स्थिति .

स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय उद्योग के विकास की चेष्टा करना ही गलत धारणा को जन्म देना कहा जाता है। परन्तु कुछ कारणों से जैसे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस्पात उद्योग का विकास हुआ रेल उद्योग का विकास भारत को उपनिवेश बनाए रखने के लिए सैनिक आवागमन को तीव्रता प्रदान करने के

लिए किया गया। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय उद्योगों के विकास के लिए स्वदेशी सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों में विकास की गति तीव्र हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के बाद उद्योग को प्राथमिकता से लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की संचयी विकास दर से बढ़ा और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 39 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। यह वृद्धि यह दर्शाती है कि विभिन्न उद्योगों में स्थिति सतोषजनक रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 के औद्योगिक नीति के आधार पर औद्योगिककरण की रूपरेखा तैयार की गई, और राज्य द्वारा संगठित उद्योगों पर 870 करोड़ रुपये का विनियोग तथा निजी क्षेत्र द्वारा 675 करोड़ रुपये का विनियोग और राजकीय एवं निजी क्षेत्रों को मिलाकर 265 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया, इस प्रकार 1810 करोड़ रुपये का कुल विनियोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया यदि हम इस पंचवर्षीय योजना का कुल खर्च देखें तो लगभग एक तिहाई केवल उद्योगों पर खर्च हुआ जो 27 प्रतिशत था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को विस्तार करने के उद्देश्य से नई मशीन निर्माण और तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कौशल पर विशेष रुचि थी।

संगठित उद्योगों एवं खनन पर 3000 करोड़ रुपये व्यय हुआ जिसमें से 1700 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र एवं 1300 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में व्यय हुये कुल मिलाकर इस योजनाकाल में उद्योगों को विशेष रूप से विकास की गति को

प्रदान किया गया और विकास की गति 78 प्रतिशत की दर से बढ़ी जो लक्ष्य से आधी ही रही।

चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में विनियोग के लिए 5300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए जिसमें 3050 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र से 2250 करोड़ रुपये गैर सरकारी क्षेत्र से व्यय किए गए। इसके अलावा लघु एवं ग्रामोद्योग में 1086 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र से एवं 560 करोड़ रुपये गैर सरकारी क्षेत्र से विनियोग की व्यवस्था की गई। इस योजना का कुल विनियोग 267 प्रतिशत उद्योगों पर व्यय निश्चित किया गया। पंचवी पंचवर्षीय योजना में संगठित उद्योगों एवं खनन पर दस हजार दो सौ करोड़ परिव्यय निश्चित किया गया जिसमें से 553 करोड़ रुपये छोटे उद्योगों पर खर्च करने की व्यवस्था की गई। पंचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास की गति 55 प्रतिशत प्राप्त की गई जो 7 प्रतिशत के लक्ष्य से कम थी जिसे असन्तोष जनक कहा जा सकता है। छठी योजना में उद्योग एवं खनिज पर 13197 करोड़ रुपये प्रस्तावित व्यय के विपरीत चालू कीमतों पर सरकारी क्षेत्र में वास्तविक व्यय 15220 करोड़ रुपये हुआ इसके अतिरिक्त 15182 करोड़ रुपये का विनियोग गैर सरकारी क्षेत्रों में किया गया जो वास्तविक विनियोग से कहीं अधिक था। सातवी पंचवर्षीय योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े एवं मध्यम उद्योगों के लिए 19708 करोड़ रुपये विनियोग का लक्ष्य रखा गया, इसके अतिरिक्त ग्रामो एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए 2752 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जो कुल योजना परिव्यय का 12.5

प्रतिशत था, इस योजना का लक्ष्य 87 प्रतिशत वृद्धि करने का था। जबकि वास्तविक प्राप्ति वृद्धि दर 85 प्रतिशत ही रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनिज पर सार्वजनिक क्षेत्र में 40673 करोड़ रुपये परिव्यय किया गया, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र 35150 करोड़ रुपये और बाकी 5523 करोड़ रुपये राजकीय क्षेत्र द्वारा खर्च किए गये। आठवीं पंचवर्षीय योजना में खनन क्षेत्र में उत्पादन के सकल मूल्य में 89 प्रतिशत एवं विनिर्माण क्षेत्र में 82 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

1951 के बाद के दशकों में भारतीय आर्थिक विकास में भारतीय औद्योगीकरण की प्रकृति विशेष रूप से चित्रित होती है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया सन् 1948 से 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों के आधार पर भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में किए गये प्रयासों के कारण ही भारतीय औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई और विगत 50 वर्षों में या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् के पाँच दशकों में औद्योगिक उत्पादन पाँच गुना से अधिक हो गया और भारत ने विश्व औद्योगिक परिदृश्य में अग्रणी को स्थापित करते हुये दसवाँ स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत के औद्योगिक विकास की प्रगति को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि भारत के विदेशी व्यापार में निर्मित वस्तुओं के आयात में लगातार कमी हुई है। इसके विपरीत इंजीनियरिंग सामान में विशेषकर भारतीय निर्यात का सामान बढ़ा है। विगत दिनों में भारतीय औद्योगिक क्षमता को विशेष बल अपने महत्वपूर्ण उद्योगों से प्राप्त हुआ है, जिनमें अत्यधिक विनियोग के द्वारा विकास सम्भव हुआ तथा



तकनीकी एवं प्रबन्धकीय क्षमता में वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत हवाई जहाज के निर्माण से लेकर सैन्य क्षेत्र में मिसाइलों, पनडुब्बियों के निर्माण में भी विश्वसनीयता हासिल करते हुये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए हर सम्भव कोशिश करते हुये दृढ़ता से प्रवेश करके औद्योगिक विश्वसनीयता प्राप्त की है। भारतीय उद्योगों के विकास को जानने के लिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ आधारभूत व मूल उद्योगों का विश्लेषण करें।

- 1 भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय इस्पात एवं लोहा उद्योग का विकास तीव्र गति से हुआ, इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि 30 करोड़ रुपये का व्यय निश्चित किया गया 17 लाख टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 10 लाख टन क्षमता वाले तीन बड़े कारखानों के स्थापना से सम्बन्धित विदेशी समझौते किये गये। 1953 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई इस काल में स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का सविलन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग के निर्धारित क्षमता में 18 प्रतिशत एवं उत्पादन क्षमता में 35.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई 1955 में ही केन्द्र में अलग लोहा एवं इस्पात मंत्रालय की स्थापना हुई।<sup>16</sup> यदि इसकी तुलना 1996-97 तक के वास्तविक उत्पादन से की जाय तो ज्ञात होता है कि भारतीय इस्पात एवं लोहा उद्योग लगभग बारह गुना उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना रही

है। जिसमें से 28 लाख टन इस्पात निर्यात का लक्ष्य 1996-97 में रखा गया था।<sup>17</sup>

- 2 भारतीय उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सूती उद्योग रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती उद्योग की विकास गति भी तीव्र हुई है। इसकी जानकारी हमें 1950-51 के उत्पादन से मिलती है जहाँ मिल क्षेत्र के द्वारा 340 करोड़ मीटर एव विकेंद्रित क्षेत्र से 101 करोड़ मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ। यदि 1993-94 का उत्पादन देखा जाय तो जहाँ मिल क्षेत्र का उत्पादन घटकर 191 करोड़ मीटर रह गया वहीं विकेंद्रित क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर 1663 करोड़ मीटर हो गया है जो अपनी विकास की गति को प्रदर्शित करता है। 1996-97 में जहाँ मिल क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ा करके 350 करोड़ मीटर रखा गया वहीं विकेंद्रित क्षेत्र के उत्पादन को भी बढ़ाकर 2120 करोड़ मीटर किया गया।<sup>18</sup>

- 3 भारत के उद्योगों में तीसरा बड़ा चीनी उद्योग है जिसका विकास भी स्वतंत्रता पश्चात ही तीव्र गति से हुआ। 1956-57 में चीनी का उत्पादन 20.3 लाख टन हो गया था, 1960-61 में यह उत्पादन बढ़कर 29.81 लाख टन हो गया। 1991 तक 119 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जो 1960-61 की तुलना में लगभग साढ़े चार गुना वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें

---

17 वही पृष्ठ 620

18 वही, पृष्ठ 628

से 1996-97 में कुल 40 लाख टन चीनी निर्यात करने का लक्ष्य था।  
वर्तमान समय में कुल 414 चीनी कारखाने हैं जिनमें तीन लाख से अधिक  
श्रमिक कार्यरत हैं यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक की तुलना करें तो  
विदित होता है कि चीनी उद्योग का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ।

- 4 चीनी उद्योग के पश्चात भारतीय उद्योगों में जूट का महत्वपूर्ण स्थान रहा  
है, विश्व में स्थापित जूट क्षमता का उत्पादन 50 प्रतिशत भारत में निहित  
है। 1951 में भारत में 112 जूट कारखाने थे। जिनकी उत्पादन क्षमता 12  
लाख टन थी। 1950-51 में 33 लाख गॉंठे जूट का उत्पादन हुआ जो वर्ष  
1996-97 में बढ़करके 95 लाख गॉंठ हो गया। भारतीय उद्योगों द्वारा  
निर्मित जूट का निर्यात बढ़ा है तुलनात्मक दृष्टि से जहाँ पर 1950-51 में  
79 लाख टन का निर्यात हुआ वही 1993-94 में घटकर 2 लाख टन रह  
गया इससे यह प्रतीत होता है कि भारत में जूट उत्पादन की क्षमता तो  
बढ़ती रही है, परन्तु घरेलू उपभोग की मात्रा भी बढ़ी है, जिसके  
परिणामस्वरूप निर्यात घटा सन् 1996-97 में 16 लाख टन जूट निर्मित  
करने का लक्ष्य रखा गया था।<sup>19</sup>

जूट उद्योग के बाद भारतीय उद्योगों में सीमेन्ट उद्योग का भी महत्वपूर्ण  
स्थान रहा है। इस उद्योग में भी स्वतंत्रता के पश्चात उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।  
1950-51 में 33 लाख टन सीमेन्ट उत्पादन क्षमता थी परन्तु 82 प्रतिशत क्षमता का

उपभोग करते हुये 22 लाख टन उत्पादन हुआ। यदि हम 1996-97 के लक्ष्य से इसकी तुलना करे तो प्रतीत होता है कि भारतीय सीमेण्ट उद्योग में दीव प्रतीति से वृद्धि हुई है नौ सौ लाख टन उत्पादन क्षमता का 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग, प्रतिशत के आधार पर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, वर्तमान समय में देश में 103 बड़े सीमेण्ट उद्योग एवं 250 लघु उद्योग कार्यरत हैं।<sup>20</sup>

5 उर्वरक उद्योग में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेष ध्यान दिया गया है, 1951-52 के प्रारम्भ में जहाँ मात्र नाइट्रोजन उत्पादन करने वाले मात्र तीन कारखाने थे जिनकी उत्पाद क्षमता 9 लाख टन थी वही फास्फेट युक्त उर्वरक कारखानों की संख्या 12 एवं कुल उत्पादन 78 लाख टन था वही 1989-90 में कुल उत्पादन 45.4 लाख टन हो गया तथा 1996-97 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 128 लाख टन रखा गया।<sup>21</sup>

इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय उद्योगों की क्षमता में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तरोत्तर वृद्धि का सिलसिला आज तक जारी रहा है और विकास की गति में वृद्धि हुई है यदि हम भारतीय उद्योगों का विश्लेषण करते हैं तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जहाँ भारतीय उद्योग अपनी आवश्यक परक वस्तुओं के उत्पादन में सक्षम नहीं थे वही आज निर्यात परक वस्तुओं के उत्पादन करने में अपने सक्षमता को सिद्ध किया है, आज भारतीय उद्योगों के द्वारा

---

20 वही, पृष्ठ 642

21 वही, पृष्ठ 647

निर्मित वस्तुओं जैसे इजीनियरिंग के सामानों एवं सूती वस्त्रों आदि का बृहद रूप से निर्माण करके विदेशों को निर्यात किया जाता है। इसी कड़ी में आगे चीनी उद्योग के द्वारा भी भारतीय निर्यात में वृद्धि देखी जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। जो निश्चित रूप से भारतीय अर्थ व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है।

### 3 विदेशी व्यापार की स्थिति

किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार होता है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बिना विदेशी व्यापार का अध्ययन किए यह पता लगाना सम्भव नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान वास्तविक स्थिति कैसी है और विकास की गति कितनी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ व्यापार सतुलन भी प्रतिकूल दिशा में बढ़ता ही रहा। सन् 1950—51 में भारत का आयात 650 21 करोड़ रुपये और निर्यात मात्र 600 64 करोड़ का हुआ और भारतीय व्यापार इस समय व्यापार सतुलन की दृष्टि से 49 57 करोड़ रुपये ऋणात्मक रहा। परन्तु 1990—91 में भारत का आयात की तुलना में कम रहते हुये 32553 करोड़ रुपया रहा एवं व्यापार सतुलन ऋणात्मक रहते हुये बढ़कर 10640 करोड़ रुपये हो गया। 1994—95 में भारतीय आयात 63814 करोड़ रुपये तथा

निर्यात 57503 करोड रुपये का हुआ और ऋणात्मक व्यापार सतुलन रहते हुये घटकर 6311 करोड रुपये रह गया।<sup>22</sup>

## सेवा क्षेत्र :

किसी भी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र उस अर्थव्यवस्था का आधार बिन्दु होता है। बिना सेवा क्षेत्र के विकास के किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा अपना विकास करना सम्भव नहीं हो सकता इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सेवा क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि के प्रयास किये जाते रहे, जिसके परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्रों का वृहद रूप से विस्तार हुआ।

सेवा क्षेत्र में रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में स्थापित रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 1950—51 में जहाँ कुल रेलमार्गों की लम्बाई 53596 किमी, कुल इंजनों की संख्या 8209 थी, कुल सवारी डिब्बे 19628, कुल माल डिब्बे 205596 थे तथा 12840 लाख यात्री ले जाये गये एवं 930 लाख टन माल ढोया गया। वही वर्ष 1993—94 में कुल रेलमार्गों की लम्बाई बढ़कर 62462 किमी<sup>0</sup> इंजनों की संख्या घटकर 7810, सवारी डिब्बे की संख्या बढ़करके 43393, माल डिब्बे बढ़करके 3 लाख 38 हजार हो गये एवं 3587 लाख टन माल ढोया गया। रेल उद्योग के विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 423 72 करोड

रूपये निश्चित किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह व्यय बढ़कर 27207 करोड़ रुपये हो गया।<sup>23</sup>

भारतीय सेवा क्षेत्र में रेल उद्योग के बाद सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किसी भी देश विकास में सड़क परिवहन अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है जैरमी बैथम के अनुसार "सड़क किसी देश की रक्त वाहिनी धमनी एव शिराये होती है जिनसे होकर समस्त सुधार प्रवाहित होता है"।<sup>24</sup> स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सड़क परिवहन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 1951 में भारवाहनो की संख्या 82 हजार थी वहीं 1990 में 1289 हजार हो गई, तथा 1951 में 34 हजार बसें थी जो 1990 में बढ़कर 312 हजार हो गई, कार जीप एव टैक्सी की संख्या 159 हजार थी जो बढ़करके 1990 में 2733 हजार हो गयी। इसी प्रकार द्विपाहिया वाहनो की संख्या में 1951 में 27 हजार थी जो 1990 में बढ़कर 12525 हजार हो गयी। अन्य वाहन चार हजार थे जो बढ़कर 2364 हजार हो गये। इसी प्रकार यदि हम कुल वाहनो का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होता है कि 1951 में कुल वाहनो की संख्या 306 हजार थी जो 1990 में बढ़कर 19173 हजार हो गई।<sup>25</sup>

---

23 वही, पृष्ठ 763

24 वही, पृष्ठ 771

25 वही, पृष्ठ 779

## 5. जल परिवहन :

सेवा क्षेत्र में जल परिवहन अपना प्रमुख स्थान रखता है और आन्तरिक सेवाओं के साथ-साथ विदेशी सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है वर्ष 1950-51 में जहाँ भारतीय जहाजों द्वारा 19.2 मिलियन टन सामानों का आवागमन बदरगाहों से हुआ वहीं 1993-94 में 179.3 मिलियन टन और 1996-97 में 253.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया। प्रथम योजना काल में पोत परिवहन पर कुल वास्तविक व्यय 18.71 करोड़ रुपये किए गये एवं सात नये दीप घरों का निर्माण किया गया। जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जहाज रानी पर कुल 3668.9 करोड़ रुपये व्यय तथा बदरगाहों और प्रकाश गृहों पर 313.58 करोड़ रुपये व्यय का निर्धारण किया गया। वर्ष 1997 तक बदरगाहों की क्षमता का लक्ष्य 253.5 मिलियन टन आका गया।<sup>26</sup>

## 6. वायु परिवहन :

सेवा क्षेत्र में आधुनिक परिवहन के साधनों में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 11 हवाई अड्डों का निर्माण एवं कई पुराने हवाई अड्डों का सुधार किया गया इस योजना में 7.8 करोड़ रुपये वास्तविक व्यय के रूप में खर्च किये गये जो लक्ष्य से कम था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4083.26 करोड़ रुपये



का व्यय निर्धारित किया गया एव 1990 में भारत में 815 हवाई जहाज पंजीकृत थे इस समय भारत में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एव 91 राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

भारतीय सेवा क्षेत्र में कुछ और सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे बैंकिंग, बीमा, एव विद्युत सेवाएँ आदि। इन सेवाओं में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जहाँ पर तहसील एव जनपद स्तर तक ही लगभग बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध थीं वही आज छोटे-छोटे कस्बों एव गावों में भी बैंकिंग सेवाओं की प्रचुरता यह सिद्ध करती है कि तीव्रगामी विकास बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में हुआ है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में भी विकास की गति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र रूप से हुई है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति शहरों तक जहाँ सीमित रही वही आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी आपूर्ति प्रचुर मात्रा में हो रही है जो अपनी विकास की तीव्रता को सिद्ध करते हुये भारतीय आर्थिक विकास की गति की दृढ़ता को सिद्ध करती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संचार माध्यमों में तीव्रता से विकास हुआ जहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सीमित संचार माध्यम थे वही इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होकर भारतीय संचार माध्यमों का संचार गाँव घरों तक हुआ जहाँ 1950-51 में टेलीफोन वायरलेस दूरदर्शन रेडियो आम आदमी से दूर उच्च पदस्थ या कुछ प्रमुख लोगों तक ही सीमित था आज वही यह अपने विकास की कहानी स्वयं बता रहे हैं। आज सामान्य लोगों के उपभोग की वस्तुओं में इन संचार माध्यमों का उपभोग उपयोग हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहाँ संचार के माध्यम शहरों

तक ही कुछ व्यक्तियों तक सीमित था, आज यह दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँच रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जहाँ बीमा क्षेत्र बहुत ही सीमित था, आज उसमें तीव्रता से विकास हुआ और जन-जन को सुरक्षा देने की भावना से जीवन बीमा से लेकर के माल बीमा दुकान बीमा, मोटर वाहनो का बीमा, उद्योग बीमा, फसल बीमा आदि सुविधायें प्रदान कर रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास या वर्तमान स्थिति का आकलन राष्ट्रीय आय के द्वारा ही सत्य रूप में प्राप्त किया जा सकता है यदि हम 1950-51 की राष्ट्रीय आय देखें तो 8574 करोड़ रुपये थी, जो सन् 1995-96 में बढ़कर 858596 करोड़ रुपये हो गयी परन्तु यह वृद्धि 1951 में 229 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़कर 1995-96 में 9350 रुपये हो गई जो भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए यह चित्रित करता है।

## **भारत में उदारीकरण प्रक्रिया :**

जुलाई 1991 से भारत की आर्थिक नीतियों में व्यापक बदलाव आया है।

तीव्र उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को बाजार मुखी बनाने का प्रयास शुरू हुआ साथ ही इसे विश्वव्यापी आर्थिक ढाँचे में ढालने का भी प्रयास किया जाने लगा। यह प्रक्रिया बहुत ही साधारण ढंग से सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध में शुरू की गई। अस्सी के दशक के प्रारम्भ में इसे बेहतर बनाने का क्रम

शुरू हुआ और इसी दशक के मध्य आते-आते इसमें तेजी लाई गई। यद्यपि विकास के लिये निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया परन्तु बाजार एवं व्यापार पर विभिन्न प्रकार के निरोधक नियम जैसे कि आई0डी0आर0 एक्ट, एम0आर0टी0पी0 एवं 'फेरा' बने रहे साथ ही साथ अफसरशाही का नियंत्रण बढ़ता गया।

अस्सी के दशक में काफी विकास हुआ जिसमें 55 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से विकास हुआ। लेकिन नब्बे का दशक समस्याओं के साथ आरम्भ हुआ। सकल घरेलू उत्पाद सन् 1990-91 में 45 प्रतिशत तक गिर गया और सन् 1991-92 में तो यह 25 प्रतिशत तक पहुँच गया। जून 1991 के अंत तक विदेशी विनिमय संचय 3368 मिलियन डालर (57870 मिलियन रुपये) से घट कर मात्र 11 मिलियन डालर (23830 मिलियन रुपये) रह गया जो केवल दो सप्ताह के आयात की जरूरतों के लिये ही था।

इसका मुख्य कारण निर्यात विकास दर में गिरावट था जो कि सन् 1990-91 में 91 प्रतिशत (डालर के संबंध में) रहा जबकि पिछले तीन वर्षों में यह 19%, 15.6% तथा 24% रहा। इसके विपरीत आयात 91% से 132% तक ही रहा। इसकी वजह से वाहतूत ऋण सेवा में काफी बढ़ोत्तरी रही। अगस्त 1990 के उपरान्त खाड़ी समस्या ने भी इस संकटकालीन स्थिति को पैदा करने में मदद की।

इस समस्या की जड़े असन्तुलन में निहित थी, जिसकी वजह से वित्तीय घाटा बढ़ता ही गया। यह घाटा सन् 1980-81 में 88870 मिलियन रुपये से बढ़कर 1990-91 में 446500 मिलियन रुपये तक हो गया। कुल शेष आंतरिक ऋण 484510 मिलियन रुपये (जी०डी०पी० का 35.6%) से बढ़कर 2795280 मिलियन रु० (जी०डी०पी० का 52.8%) तक हो गया। बाकी वाह्य ऋण 134790 मिलियन रु० (जी०डी०पी० का 9.9%) से बढ़कर 660170 मिलियन (जी०डी०पी० का 12%) तक हो गया। सन् 1980-81 तथा सन् 1990-91 के मध्य ऋण की कुल देनदारी सरकार के कुल खर्च का 11.6% से बढ़कर 26.2% हो गयी।<sup>27</sup>

इस तरह की स्थिति को ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रखा जा सकता था। इस समस्या पर काबू पाना ही प्रथम लक्ष्य था और पिछले दो वर्षों में जो नीतियाँ बनाई गईं उनमें इसी बात को सर्वोपरि रखा गया। स्थायित्व के साथ सरचनात्मक सुधार तथा लम्बी आर्थिक व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई। दो चरणों में रुपये के 20% अवमूल्यन की योजना बनाई गई। सरचनात्मक व्यवस्थापना के कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों को भी समाहित किया गया ताकि आर्थिक सुधार में तीव्रता लाई जा सके। जुलाई 1991 में व्यापार नीति पर सुधार की घोषणा की गई। निर्यात की बढ़ोत्तरी के लिये अच्छा वातावरण बनाया जाये इस पर काफी जोर दिया गया। साथ ही निर्यात

उत्पादों को और मजबूती प्रदान करने के लिये भी प्रयास किये गए। पुनर्निर्मित व्यापार नीति में आयात एवं निर्यात को जोड़ा गया। नियंत्रण नियम एवं रूकावटों को काफी हद तक दूर किया गया। वित्तीय उत्पादों के आयात को और उदार बनाया गया।

उदारीकरण प्रक्रिया के तहत उद्योग नीति को और सुदृढ़ बनाया गया ताकि उद्योग का विकास हो, साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि आधुनिकीकरण एवं तकनीकीकरण को अपनाया जाये ताकि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कायम हो सके। सबसे मूलभूत बदलाव सीधे विदेशी निवेश में किया गया। प्रधान उद्योगों में 51% तक की भागीदारी की छूट दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास तेज किये गये, साथ में इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को भी आकर्षित करने की योजना बनाई गई।

नई उद्योग नीति के अंतर्गत, कुछ उद्योगों को छोड़कर लगभग शेष सभी पर लाइसेन्स प्रक्रिया को लगभग समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब काफी हद तक सीमा बाधित कर दिया गया। अब ये केवल आधारभूत क्षेत्र पर ही अधिक ध्यान देंगे। वित्तीय तथा आर्थिक सुधार का मुख्य लक्ष्य मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण तथा बकाया धन अदायगी में सुधार ही है।

पिछले तीन बजटो मे इस बात पर काफी जोर दिया गया कि कर नियमो मे सुधार किया जाय। राजा चैलैया समिति की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसमे निगम कर मे व्यापक परिवर्तन के लिये दिये गये सुझावो को स्वीकार कर धीरे-धीरे लागू करने का निर्णय किया गया। साथ ही सरकार ने नरसिम्हन समिति द्वारा सुझाये गये आर्थिक सुधारो को भी अगीकार कर लिया गया।

अत उक्त से स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय मे सतत् वृद्धिमान प्रवृत्ति पायी गयी, परन्तु राष्ट्रीय आय की तुलना मे प्रतिव्यक्ति आय मे अनुपातिक वृद्धि कम हुई है जिसका कारण तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसख्या है।

## અધ્યાય : 4

“ગૌટ”

"GATT"

## प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता:

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था सक्रमण कालीन स्थित में थी। युद्ध के अन्तिम चरण एवं युद्ध के तत्काल पश्चात सभी राष्ट्रों के समक्ष औद्योगीकरण एवं अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए विश्व के पटल पर वाणिज्य व्यापार औद्योगीकरण तथा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी शृंखला में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्वबैंक की स्थापना हुई। वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने एक सहमति व्यक्त की। जिसमें यह तय किया गया कि व्यापार का समुचित विकास में प्रशुल्क के अवरोध को समाप्त करना चाहिए। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न देशों के द्वारा आपसी विचार विमर्श किए गये एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित अनेक बिन्दुओं पर अपना विचार व्यक्त किया यथा प्रशुल्क प्राथमिकता, अभ्यश और लाइसेन्स प्रणाली अदृश्य संरक्षण अनुदान आदि।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लन्दन में वर्ष 1946 में तथा जेनेवा में 1947 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और रोजगार सम्बन्धी विषयों पर सम्मेलन हुए परन्तु आपसी मतभेद के कारण अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका। अन्ततः हवाना सम्मेलन के माध्यम से एक चार्टर तैयार किया गया जिसमें व्यापार प्रतिबन्धों में



शिथलीकरण की बात कही गयी और अन्ततः 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में 23 देशों ने (भारत सहित) हस्ताक्षर किए और प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते "गैट" का जन्म हुआ। इस प्रकार भारत इसके जन्म से ही इसका सदस्य रहा। गैट ने 1 जनवरी 1948 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। गैट मूलतः एक व्यापारिक समझौता है जिसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों की प्रशुल्क रियायतें द्विपक्षीय समझौतों से सम्बन्धित हैं। गैट स्वभावतः कई राष्ट्रों के बीच विधिक समझौता है एवं समझौता करने वाले राष्ट्रों के द्वारा प्रशासित एक संधि है।

### गैट के मुख्य उद्देश्य :

यद्यपि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक स्थाई समझौता है परन्तु इसके कुछ उद्देश्य हैं। प्रशुल्क दरो के अवरोधों को कम करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषमता को समाप्त करने के दृष्टिकोण से इसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं —

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार
- 2 सदस्य राष्ट्रों द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना और विश्व उत्पादन में वृद्धि करना।
- 3 विश्व ससाधनों का विकास तथा उनका पूर्ण उपयोग करना।
- 4 सम्पूर्ण विश्व समुदाय के रहन सहन के स्तर को उचा उठाना।

यद्यपि यह सभी उद्देश्य सामान्य स्वाभाव के हैं और गैट के प्रावधान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवस्था नहीं करते परन्तु स्वतंत्र तथा बहु पक्षीय व्यापार के प्रोत्साहन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। गैट में मात्रात्मक प्रतिबन्धों की भी व्यवस्था की गई, गैट के अन्तर्गत प्रशुल्क में कमी और भेदभाव की समाप्ति आपसी लाभ एवं सहमति के आधार पर की जाती है। वास्तव में गैट के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए।

### गैट के सिद्धान्त :

गैट के दर्शन या सिद्धान्त को समझाना बहुत कठिन है। पाल क्रुगमैन के अनुसार गैट का दर्शन है प्रकाशमयी व्यापारवाद और कोई अच्छा वाक्य न मिल पाने के कारण इसे “गैट थिक” से संबोधित करते हैं वे लिखते हैं “गैट थिक” व्यापारवादी है क्योंकि हर देश अपनी स्वेच्छा से निर्यात पर छूट प्रदान करेगा और आयात प्रतिबन्ध लगायेगा। परन्तु यह प्रकाशमयी या ज्ञानी इसलिये है क्योंकि इसके अन्तर्गत सभी देश व्यापार बढ़ाने के लिये एक दूसरे की आयातित वस्तुओं को बढ़ावा देंगे। उनके अनुसार वैसे तो देश संरक्षणवादी हो जाते हैं परन्तु सब मिलकर मुक्त व्यापार से लाभान्वित होते हैं। यद्यपि “गैट थिक” आर्थिक बकवास है। परन्तु जो कुछ हो रहा है यह उसका अच्छा उदाहरण है।

प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता द्वारा कुछ नियम निम्न मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर अंगीकार लिए गए हैं।<sup>1</sup> यथा

- 1 व्यापार गैर विभेदात्मक तरीके से किया जाना चाहिए ।
- 2 परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के प्रयोग को ध्यान में न रखा जाय ।
- 3 इन समझौतों को जिन पर सहमति न हो विचार विमर्श द्वारा हल किया जाना चाहिए ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गैट के सदस्य देश व्यापार बाधाओं और विभेदात्मक व्यापार को कम करने के लिए सहमत हैं जिससे कि बहुपक्षीय और स्वतन्त्र व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके और अंत में विश्व व्यापार को विस्तृत दिशा मिल सके ।

## गैट के प्रावधान :

सामान्य शर्तों के तहत सदस्य राष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि प्रशुल्क में कमी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभेद को समाप्त किया जाय तथा यह कार्य आदान प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर हो इस सम्बन्ध में गैट की कुछ धाराओं या अनुच्छेदों को देखा जा सकता है । यथा

---

1 इल्स वर्थ—पी० टी० दि इण्टरनेशनल इकोनॉमी (अंग्रेजी संस्करण) पृष्ठ 513

## 1 परम मित्र राष्ट्र (एम.एफ.एन.) वाक्य या धारा .

भेदभाव को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुच्छेद के तहत सभी आयात व निर्यात शुल्को को बिना शर्त परममित्र राष्ट्रों द्वारा अपनाना है। परममित्र राष्ट्र का नियम एक देश द्वारा दूसरे देश के लिए दी गई है प्रशुल्क अधिमान व्यापार सम्बन्ध रखने वाले अन्य सभी देशों पर लागू होती है। इस प्रकार परममित्र राष्ट्र का सिद्धान्त इस बात में निहित है कि प्रत्येक राष्ट्र को परममित्र राष्ट्र माना जाना चाहिए। वार्ता और अधिमान को द्विपक्षीय समझौते द्वारा समान आधार पर सभी सदस्य देशों पर विस्तारित किया जाना चाहिए जिससे की अधिमानों को बहुपक्षीय किया जा सके।

## 2 प्रशुल्क रियायते

प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता का महत्वपूर्ण घटक अनुबन्ध करने वाले देशों के बीच आपसी प्रशुल्क रियायतों का वार्ताकृत सतुलन है। वार्ताकृत निर्धारित प्रशुल्क दरों को परममित्र राष्ट्र के सिद्धान्त के माध्यम से सभी अनुबन्ध करने वाले देशों में सामान्य कृत किया जाता है। इस प्रकार अनुबन्ध करने वाले देश समझौते के अनुच्छेद ग्यारह (11) में वर्णित रियायतों की सारणियों में निर्धारित वार्ताकृत दरों से अधिक आयात सीमा शुल्क न लेने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।<sup>2</sup>

---

2 झिन्नान, एम.एल. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कोणार्क, 1996 पृष्ठ 489

### 3 मात्रात्मक प्रतिबन्धो का सामान्य उन्मूलन

प्रशुल्क एव व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता विभिन्न देशों को उनके आयात शुल्को पर न्यूनतम सभव स्तर पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकसित देशों ने अधिकतर निर्मित वस्तुओं पर करारों को काफी सीमा तक कम कर दिया और उन्हें आयात मूल्य के चार से दस प्रतिशत न्यूनतम स्तर पर निश्चित किया जाता है<sup>3</sup> इस बात का उल्लेख करार के ग्यारहवें अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।

### 4 आयात सरक्षण संहिता

इसके तहत एक राष्ट्र आयातों को रोकने के लिए प्रशुल्क या कोटा निर्धारित कर सकता है जो आयात घरेलू उत्पादकताओं को बहुत अधिक हानि पहुँचाते हैं या हानि पहुँचाने की सम्भावना रखते हैं इस प्रकार की व्यवस्था प्रशुल्क या व्यापार सम्बन्धी समझौता के उन्नीसवें (19) अनुच्छेद में वर्णित है।

---

3 वही, पृष्ठ 490

## 5 अपवाद

इसमे अनुबन्ध करने वाले राष्ट्रों द्वारा आयात कोटे पर रोक लगाने के लिए सामान्य और सुरक्षा अपवादों की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी समझौता के अनुच्छेद 20, 21 एवं 24 में व्यवस्था की गई है।

## 6 सहायिकी एवं प्रति इकाई शुल्कों के नियम :

यद्यपि इनको प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता के प्रारम्भ में अलग से नहीं रखा गया था लेकिन 1970 के टोकियो दौर में एक अलग नियमावली के तहत रखा गया। इसके तहत प्राथमिक वस्तुओं की निर्यात सहायिकी केवल इस शर्त के अनुसार है कि इसके अन्तर्गत वे देश विश्व निर्यात व्यापार के समान अंश से अधिक न प्राप्त कर सकें<sup>4</sup> इस समझौते में इस प्रकार की व्यवस्था है जिसके तहत आयातक देशों को व्यापार करने वाले उन देशों के विरुद्ध क्षतिपूर्क कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है जो आयातक देशों के बाजारों में राशिपातन वस्तुओं अथवा निर्यात सहायिकी के माध्यम से बढ़ी हुई कीमतों की वस्तुएँ सम्मिलित कर देते हैं।<sup>5</sup>

---

4 वही, पृष्ठ 491

5 वही, पृष्ठ 491

## प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता

### वार्ताओं के दौर:

गैट की स्थापना से अब तक विश्व व्यापार वार्ताओं के कई दौर सम्पन्न हुए। जिसके अन्तर्गत विश्व व्यापार को एक नई दिशा मिली एवं सदस्य राष्ट्रों के व्यापार में प्रगति हुई। कुल मिलाकर गैट के अन्तिम काल तक कुल आठ सम्मेलन या दौर आयोजित हुए। सभी सम्मेलनों में कुछ न कुछ प्रगति हुई। कुल मिलाकर गैट में प्रगतिशील परिवर्तन दिखाई पड़े।

गैट का प्रथम सम्मेलन 1947 में जेनेवा में आयोजित हुआ यह सम्मेलन विश्व व्यापार की दिशा में एक प्रगतिशील प्रयास था जिससे सदस्य राष्ट्रों विशेष कर उन राष्ट्रों जो चालीस के दशक में दूसरा सम्मेलन सन् 1949 में एन्नेक्सी नामक स्थान पर फ्रांस में आयोजित हुआ इसी प्रकार गैट का तीसरा सम्मेलन 1950-51 में इंग्लैंड में, चतुर्थ सम्मेलन स्वीटजरलैंड के जेनेवा में 1955-56 में सम्पन्न हुआ। गैट का छठा सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। जिसे कनैडी दौर कहा जाता है इसमें राजधानी टोकियो में 1973-79 के बीच आयोजित किया गया इसके बाद सर्वाधिक

महत्वपूर्ण एव क्रांतिकारी दौर आठवे सम्मेलन पुण्टाडेल ऐस्टे (उरुग्वे दौर) 1986 मे हुआ।

### तालिका न० (1)

#### गैट के व्यापार के दौर :

| वर्ष | स्थान      | समझौते की प्रकृति  | भाग लेने वाले देश की संख्या |
|------|------------|--|-----------------------------|
| 1947 | जेनेवा     | तटकर   | 23                          |
| 1949 | एन्नेसी    | तटकर   | 13                          |
| 1951 | टोरक       | तटकर   | 38                          |
| 1956 | जेनेवा     | तटकर   | 26                          |
| 1960 | जेनेवा     | तटकर   | 26                          |
| 1964 | जेनेवा     | तटकर और कम मूल्य पर न बेचने सम्बन्धी उपाय  | 62                          |
| 1967 | कनेडी दौर  | तटकर और कम मूल्य पर न बेचने सम्बन्धी उपाय  | 62                          |
| 1973 | जेनेवा     | प्रशुल्क, गैट प्रशुल्क एव 'ढाचा' सबन्धित समझौते  | 102                         |
| 1979 | टोकियो     | प्रशुल्क एव गैर प्रशुल्क उपाय नियम सेवाए   | 102                         |
| 1986 | जेनेवा     | बौद्धिक सम्पदा सबन्धी अधिकार विवाद निपटाना कपडा कृषि तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आदि। | 123                         |
| 1993 | उरुग्वेदौर | बौद्धिक सम्पदा सबन्धी अधिकार विवाद निपटाना कपडा कृषि तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आदि। | 123                         |



उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1947 से 1993 तक गैट सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये और इन सम्मेलनो मे कई देशो ने भाग लिया तथा भाग लेने वाले देशो की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। वर्ष 1947 से 1960 तक के दौर जो कि मुख्यत जेनेवा मे आयोजित हुए और मुख्य मुद्दा प्रशुल्क एव कम मूल्य पर न बेचने (एन्टी डम्पिंग) से सम्बन्धित रहा जिसमे लगभग 62 देशो ने भाग लिया जो अभी तक हुए दौर मे सर्वाधिक सख्या रही। इसके पश्चात 1973 प्रशुल्क के साथ साथ ढाचागत समझौते हुए।

वर्ष 1986 मे गैट की दिशा मे कुछ विचलन की स्थिति आयी जिसमे प्रशुल्क एव गैर प्रशुल्क उपाय के अतिरिक्त नियमन सेवाएँ बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी अधिकार, विवादो का निपटारा, कपडा, कृषि तथा विश्व व्यापार सगठन की स्थापना सम्बन्धी आदि महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित किये गये। जिसमे 123 देशो ने भाग लिया तथा विवादास्पद स्थिति प्रारम्भ हुई जिसकी पुनरावृत्ति 1993 मे हुई जो उरुग्वे दौर से भी चर्चित हुआ।

## कनैडी दौर:

गैट के अन्तर्गत जो भी सम्मेलन आयोजित किये गये वे सभी प्राय (टैरिफ) प्रशुल्क कटौती से सम्बन्धित रहे है तथा द्विपक्षीय रूप मे उभरे। यद्यपि की इन सम्मेलनो की प्रगति मन्द रही परन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन से अमेरिका के

व्यापार में हानि की स्थिति परिलक्षित हुयी थी। इस प्रकार की स्थिति से उबरने के लिये तत्कालीन कनैडी प्रशासन ने 1962 में एक अधिनियम के तहत अमेरिका को सभी वस्तुओं पर 50% प्रशुल्क कटौती लगाने का अधिकार दिया गया। परिणाम स्वरूप 1964 में जेनेवा में व्यापार वार्ताओं के कनैडी दौर के प्रारम्भ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ<sup>6</sup> इस प्रकार की प्रशुल्क कटौतियों को व्यवहार रूप में 37 देशों ने विश्व व्यापार करार में भाग लिया जिसमें विश्व व्यापार के लगभग 80% व्यापार को शामिल किया गया। इसके तहत कुछ मुख्य औद्योगिक देशों तथा ब्रिटेन, जापान और कनाडा ने उस सीमा तक लागू किया जहाँ तक अमेरिका ने अपने शुल्क योग्य आयातों को 40% किया। परन्तु ये प्रशुल्क रियायते विकसित देशों द्वारा निर्मित वस्तुओं के दायरे में ही सीमित थी।

## टोकियो दौर :

प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते का सातवाँ दौर जापान के राजधानी टोकियो में 1973-79 के बीच सम्पन्न हुआ। इस दौर की शुरुआत सितम्बर 1973 से शुरू की गयी। चूँकि यह टोकियो में ही घोषणा की गयी थी इसलिये इसे टोकियो दौर कहा जाता है। टोकियो घोषणा में प्रमुखता 6 क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम बनाये गये थे जिनका प्रभाव दूरगामी था। यथा

---

6 झिगन एम एल अन्तरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कोणार्क, 1996 पृष्ठ 492

- 1 प्रशुल्क कटौतिया
- 2 गैर प्रशुल्क अवरोधो मे कटौती
- 3 चयनित क्षेत्रो मे समस्त व्यापार अवरोधो मे कमी ।
- 4 बहुपक्षीय सुरक्षा पर वार्ता ।
- 5 कृषि क्षेत्र मे महत्वपूर्ण पहलुओ को विशेषकर समस्याओ एव विशेषताओ को मद्दे नजर रखते हुए व्यापार मे उदारीकरण ।
- 6 उष्ण कटिबंधीय उत्पादो को मुख्य रूप से उपचारित करना ।

इस दौर की घोषणा मे इस बात पर भी जोर डाला गया है कि बहुपक्षीय वार्ता मे विकासशील व पिछड़े हुये देशो की अभिरुचि और उनकी कठिनाइयो को भी ध्यान मे रखा जाये टोकियो दौर के अन्तिम दौर या इस दौर की समाप्ती पर विशेष गैट प्रशुल्क उपायो और कृषि जन्म उत्पादो पर बहुत से समझौतो पर सहमति व्यक्त की गयी और उनको 1980 के प्रारम्भ से ही लागू कर दिया गया जिनमे मुख्य रूप से —

- 1 डेरी उत्पादो से सम्बन्धित समझौतो — जिसमे मक्खन, दूध, पनीर आदि सम्मिलित है ।
- 2 विद्यमान व्यापार की अनावश्यक तकनीकी अवरोधो से सम्बन्धित समझौते — इसमे वैधानिक तौर पर बाध्य नियमो का भी प्रावधान किया गया ।

- 3 सहायिकी एवं प्रतिकार शुल्क सम्बन्धी करार— इसके तहत कृषि, मत्स्य पालन, वनों उत्पादन आदि के विवादों से सम्बन्धी निपटारे को सम्मिलित किया गया।
- 4 आयात अनुज्ञा सम्बन्धी समझौते — इसमें स्वतः अनुमोदन, कोटे के सम्बन्ध में विवादों पर सलाह एवं निपटारे को सम्मिलित किया गया।
- 5 उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकारी वसूली एवं नागरिक उड्डयन व्यापार सम्बन्धी समझौते सम्मिलित किये गये।

तालिका न० 2

### टोकियो दौर में प्रशुल्क परिवर्तन

| प्रशुल्क (प्रतिशत)  |              |                |               |
|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| वस्तुएं             | पूर्व—टोकियो | टोकियो पश्चात् | कमी (प्रतिशत) |
| सकल औद्योगिक उत्पाद | 7.2          | 4.9            | 33            |
| कच्चा माल           | 0.8          | 0.4            | 42            |
| अर्द्धनिर्मित       | 5.8          | 4.1            | 30            |
| तैयार माल           | 10.3         | 6.9            | 33            |

**स्रोत** गैट (1971) पृ० 120, बी० सोडरस्टन एवं जी० रीड इन्टर नेशनल, इकोनॉमिक्स 1994 मैकमिलन द्वारा उद्धित।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि टोकियो दौर के पूर्व और पश्चात प्रशुल्क दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। सकल औद्योगिक उत्पाद की प्रशुल्क

दरो मे 33% की कमी आयी जब कि कच्चे मालो की प्रशुल्क दरो मे 52% की कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार टोकियो दौर के पूर्व सकल औद्योगिक उत्पाद की प्रशुल्क दरे 72 प्रतिशत जो कि टोकियो दौर के पश्चात घट कर 49% रह गयी। कच्चे माल की प्रशुल्क दर टोकियो दौर के पूर्व 8% थी जो कि टोकियो दौर मे 4% रह गयी।

कई क्षेत्रो मे टोकियो दौर का मिला जुला असर रहा। कृषि व्यापार की मौलिक समस्याओ से निपटने मे यह कारगर नही हो सका। फिर भी गैर प्रशुल्क अवरोधो पर कई समझौते हुए, कुछ मामलो मे यह गैट नियमो का अनुपालन करके कुछ मे पूर्णता नये तरीको को अपनाकर। अधिकतर स्थितियो मे इन समझौतो पर अमल केवल कुछ औद्योगिक देशो ने ही किया। इसी कारण से इन्हे अकसर सहिता से सम्बोधित किया गया है। इसके अन्तर्गन निम्न समझौते आते है। यथा

सहायिकी और क्षतिपूर्ति के उपाय— गैट के अनुच्छेद VI, XVI, XXIII का अनुपालन।

व्यापार पर तकनीकी अडचन— जिन्हे कभी—कभी “मानक सहिता” कहा जाता है।

## आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियार्ये :

### सरकारी खरीद :

कस्टम मूल्याकन — अनुच्छेद VII

एन्टी डम्पिंग अनुच्छेद VI

## गोमांस व्यवस्था :

### 1 अन्तरराष्ट्रीय डेरी व्यवस्था

### 2 सिविल एयर क्राफ्ट मे व्यापार

इनमे से कई कोडो का उरुग्वे दौर मे सशोधन एव विस्तारीकरण किया गया । सहायिकी और क्षतिपूर्ति के उपाय, व्यापार पर तकनीकी अडचन, आयात लाइसेंसिंग कस्टम मूल्यांक और एन्टी डम्पिंग अब बहुपक्षीय वचन वद्धता है जो विश्व व्यापार संगठन समझौते के अन्तर्गत आते है दूसरे शब्दो मे सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य इनसे बाध्य है । जबकि सरकारी खरीद, गोमांस, डेरी उत्पाद और सिविल एयर क्राफ्ट बहुददेशीय समझौते है । गैट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एव विवादास्पद उरुग्वे दौर रहा है । जिसका विस्तृत विवरण अगले अध्याय मे है ।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गैट ने अपने उद्देश्यो मे कहा तक सफलता प्राप्त की । यदि हम गैट के विगत 47 वर्षों की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करते है तो इसकी सफलता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है ।

गैट के द्वारा प्रशुल्क दरो को कम कर विश्व व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने मे वाछित सफलता नही प्राप्त की जा सकी है । परन्तु इसके बावजूद यह तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गैट की भूमिका को नकारा नही जा सकता । इसलिये

गैट प्रारम्भिक अवस्था में प्रशुल्क दरों को कम कराने में काफी सीमा तक सफल रहा है।

दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति में गैट की सफलता का आकलन सदस्य देशों के द्वारा अपने यहाँ के उद्योगों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति को कम करने का रहा। गैट की सफलता को जानने के लिये भी आवश्यक है कि क्या सदस्य देश अपने यहाँ लगने वाले प्रशुल्क दरों को कम करते हुए अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिबन्धों को वास्तविक रूप में अन्य प्रकार के विश्व व्यापार को हतोत्साहित करने वाले प्रतिबन्धों को समाप्त करने का दावा करना तो हास्यस्पद होगा। परन्तु यह सत्य है कि इस दिशा में वे अपने यहाँ व्यापार अन्य क्षेत्रों में सहायिकी को कम करें जिससे विश्व व्यापार विकास के साथ-साथ निष्पक्षता का प्रादुर्भाव हो सके। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि गैट आंशिक रूप में ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।

विश्व स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए विश्व व्यापार के प्रोत्साहन द्वारा रोजगार अवसरों का सृजन करना भी एक उद्देश्य रहा है, जिसमें कुछ सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई है बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात् इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि गैट के द्वारा बेरोजगारी को कम करने के अपने दृष्टिकोण में सफलता सामान्य रही।

## અધ્યાય : 5

*ડંકલ પ્રસ્તાવ : ઝરુઘ્વે ઢૌર*



## पृष्ठभूमि :

प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते का आठवॉं एवं महत्वपूर्ण दौर उरुग्वे की राजधानी पुन्तादेल अस्त में 20 सितम्बर 1986 को प्रारम्भ हुआ। यह दौर टोकियो दौर के बाद का दौर था। टोकियो दौर के दौरान विश्वव्यापी अवसाद एवं तीन मुख्य व्यापारिक समूहों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी थी, यथा संयुक्त राज्य, यूरोपीय समुदाय एवं जापान। संयुक्त राज्य एवं यूरोपीय समुदाय का विवाद अधिकांशतः कृषि मामलों पर केन्द्रित था। उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात का प्रयास कर रहा था कि जापान अपने घरेलू बाजार को विदेशी सामानों के लिए खोल दे जबकि दूसरी ओर यूरोपीय समुदाय इस बात का प्रयास कर रहा था कि जापान के निर्यात व्यापार को सीमित किया जाय। जापान इस बात के पक्ष में था कि एक नया दौर बहुपक्षीय हो इसी प्रकार अन्य देश भी प्रायः इन सब से सम्बन्धित नये दौर के पक्ष में थे।

वर्ष 1985 में एक समिति का गठन किया गया जिसका कार्य होने वाले दौर के उद्देश्य एवं विषय वस्तु के सम्बन्ध में निश्चय करना था। अन्ततः 1986 में वांछित उरुग्वे दौर प्रारम्भ हुआ जिसमें कुल मिलाकर 120 देशों ने भाग लिया इसमें बहुत से बैठके हुईं और यह सर्वाधिक विवादास्पद दौर रहा। गैट के तत्कालीन महासचिव आर्थर डकल ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रारूप

सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। वास्तविक रूप में इस दौर में सभी स्तरों की बैठकों में कभी भी सहमति नहीं रही और परिणाम यह हुआ कि सधि— पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो सके यद्यपि इस दौर में कुछ तो परम्परागत मुद्दे रहे यथा—तटकर दरों में कटौती, गैर तटकर प्रतिबन्धों में कटौती आदि सम्मिलित थे इसके अतिरिक्त कुछ नये प्रस्ताव रखे गये जिसमें बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धित व्यापार विनियोग तथा उद्योग सम्बन्धी व्यापार तथा सेवाओं सम्बन्धी व्यापार। यह दौर गैट का आठवों दौर था। डकल प्रस्ताव में 'ले लो या छोड़ दो' को आधार बनाया। डकल प्रस्ताव एक विधिक एवं तकनीकी दस्तावेज है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके अतिरिक्त दूरगामी तरीकों से आलिप्त करने वाले हैं। अतः इस का बहुत ही गौर से अध्ययन, विश्लेषण एवं विचार विमर्श करना आवश्यक है। इस प्रस्ताव पर अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, सरकारी संस्थाओं तथा अनेक विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया तथा टिप्पणियाँ की हैं। यह प्रस्ताव 28 खण्डों में विभाजित है।<sup>1</sup>

- 1 उरुग्वे दौर के सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से सम्बन्धित नियम।
- 2 अल्प विकसित राष्ट्रों के लिये उपाय।
- 3 उत्पादन में व्यापार।
- 4 मूल नियम।
- 5 जहाज पर लादने से पूर्व निरीक्षण।

- 6 प्रति राशिपातन ।
- 7 व्यापार पर तकनीकी रूकावटे ।
- 8 आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया ।
- 9 आर्थिक सहायता तथा प्रतिरोधक शुल्क ।
- 10 सीमा शुल्क मूल्यांकन ।
- 11 सरकारी वसूली ।
- 12 कृषि ।
- 13 स्वास्थ्य कर उपाय ।
- 14 व्यापार सबंधी निवेश के उपाय ।
- 15 वस्त्र ।
- 16 गैट के अनुच्छेद II 1 (b) में ।
- 17 गैट के अनुच्छेद XVII
- 18 गैट के अर्न्तगत बकाया भुगतान प्राविधान ।
- 19 विवाद निस्तारण सबंधी नियम व प्रक्रिया ।
- 20 संपूर्ण विवाद निस्तारण व्यवस्था ।
- 21 छूट का समापन ।
- 22 गैट के अनुच्छेद XXIV
- 23 गैट के अनुच्छेद XXVII
- 24 गैट के अनुच्छेद XXXV

- 25 गैट की कार्य प्रणाली ।
- 26 सेवा में व्यापार ।
- 27 व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार ।
- 28 बहुपक्षीय व्यापार संगठन की स्थापना ।

### उरुग्वे दौर के उद्देश्य :

इसके अन्तरगत रखी गयी वार्ताये विस्तृत आधार पर थी । इस दौर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रहे ।<sup>2</sup>

- 1 जीवन स्तर को उठाना ।
- 2 पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना ।
- 3 वास्तविक आय में वृद्धि सुनिश्चित करना ।
- 4 वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार का विस्तार ।
- 5 ससाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना ।
- 6 पर्यावरण बचाना एवं संरक्षित करना ।

ये सभी उद्देश्य आपसी लाभदायक व्यापार के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं, यथा

- (A) प्रशुल्कों को घटाकर,
- (B) अन्य व्यापार प्रतिबन्धों को हटाकर ।

ये बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था बहुत ही विस्तृत है, जिसमें निम्न समझौतों को सम्मिलित किया गया है

- (i) विश्व व्यापार संगठन का गठन,
- (ii) वस्तुओं में व्यापार
- (iii) कृषि

---

<sup>2</sup> शर्मा एंडी एवं गीतिका, किताब महल, गैट-डब्लू टी ओ 1995, पृष्ठ 8-9

- (iv) सफाई एव पौध सुरक्षा प्रावधान ।
- (vi) टेक्सटाइल एव कपडा ।
- (vi) व्यापार के तकनीकी अवरोध ।
- (vii) विनियोग तथा उद्योग सम्बन्धी व्यापार ।
- (viii) प्रति राशिपातन ।
- (ix) उदगम के नियम ।
- (x) सहायिकी एव प्रतिरोधी उपाय ।
- (xi) सेवाओं में व्यापार ।
- (xii) बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी व्यापार ।
- (xiii) एकीकृत विवाद निपटारा ।
- (xiv) व्यापार नीति पुनरसमीक्षा तत्र ।

### उरुग्वे दौर के वार्ता समूह :

उरुग्वे दौर की कार्यसूची बहुत ही जटिल है । वस्तु व्यापार पर वार्ता करने के लिए ही 15 समूह बनाये गये जबकि सेवा व्यापार के सदर्थ में अन्य समूह वार्ता करने के लिए गठित किए गये । उरुग्वे दौर में इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि अवाछित तिर्पक क्षेत्रीय माँग को बचाने के लिए सतुलित रियायतों की व्यवस्था की जाय ।<sup>3</sup>

अभी तक गैट की जितनी भी बैठके हुई थी उनमें से यह सबसे प्रभावी बैठक थी । पिछली सभी बैठकों को केवल औद्योगिक वस्तु व्यापार के उदारीकरण को लेकर ही चर्चा होती रही । परन्तु उरुग्वे बैठक में इनके साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न

---

3 साडस्टन वी ओ एव रीड, इन्टर नेशनल इकोनॉमिक्स, मैकमिलन 1994, पृष्ठ 367-368 ।

पहलुओ पर चर्चा हुई और गैट की परिधि में कुछ नवीन क्षेत्रों को लाने का प्रस्ताव किया गया। साथ ही नये क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सेवाएँ, बौद्धिक सम्पदा एवं व्यापार सम्बन्धी विनियोग प्रावधानों ट्रिप्स को भी वार्ता में लाया गया।

व्यापार समझौता समिति द्वारा समझौते के तहत निम्न विषयों पर बातचीत तय की गई<sup>4</sup>। 1 टैरिफ 2 नान टैरिफ उपाय 3 उष्णकटिबन्ध उत्पाद 4 नैसर्गिक सम्पदा उत्पाद 5 वस्त्र 6 कृषि 7 गैट सबधी वस्तुएँ 8 संरक्षण 9 बहुपक्षीय व्यापार समझौते और व्यवस्थाएँ। 10 आर्थिक सहायता 11 विवाद समझौते 12 ट्रिप्स 13 ट्रिप्स 14 गैट की कार्य प्रणाली 15 अन्य सेवाएँ।

सम्पूर्ण बातचीत के लिये एक व्यापार वार्ता समिति गठित की गई इस समिति में दो अध्यक्ष थे एक मंत्री स्तर का तथा दूसरा अनुसचिवीय स्तर का। इसी के पश्चात गैट के महानिदेशक आर्थर डकल को अनुसचिवीय स्तर पर टी एन सी का चेयरमैन बनाया गया। जो क्षेत्र वस्तुओं के वार्ता के दायरे में आते थे उनके लिये एक समूह बनाया गया और प्रत्येक 15 क्षेत्रों के लिये एक वार्ता समूह बनाया गया है जो कि जी एन श्री एवं टी एन सी के प्रति जवाब उत्तरदायी है। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों जैसे की भारत तथा ब्राजील के विरोध के कारण सेवा क्षेत्र के लिये एक अलग वार्ता समूह बनाया गया।

### उरुग्वे दौर के वार्ता समूह

| व्यापार प्रतिबन्ध एवं सम्बन्धित मुद्दे                                   | क्षेत्र विशेष   |
|--|---|
| सहायिकी एवं क्षतिपूरक उपाय   | कृषि  |
| गैर-तटकर उपाय  | प्राकृतिक ससाधन उत्पाद  |
| सुरक्षात्मक/बचाव के उपाय   | सेवाए   |
| तटकर   | कपडा, सम-शितोष्ण वस्तुए   |
| विधि/प्रक्रिया   | अन्य  |
| विवाद निपटारा गैट के अनुच्छेद गैट की कार्यशैली बहुपक्षीय व्यापार वार्ताए | बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी व्यापार, विनियोग तथा उद्योग सम्बन्धी व्यापार। |

यद्यपि आठवे चक्र की वार्ता को 1990 के अंत तक पूर्ण हो जाना था परन्तु अनुसचिवीय स्तर की बैठक जो कि दिसम्बर में ब्रसेल्स में हुई इसमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका क्योंकि कृषि को लेकर असमजस की स्थिति बरकरार थी। वार्ता कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गयी और 26 फरवरी 1991 में टी0एन0सी0 ने व्यापार वार्ता पुन प्रारम्भ करने का निर्णय किया। समझौता वार्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मूल 15 क्षेत्रों को 7 नये क्षेत्रों में समायोजित कर दिया गया। 1 कृषि 2 वस्त्र 3 सेवा 4 नियम निर्माण 5 ट्रिप्स तथा ट्रिप्स 6 विवाद सुलझाना 7 बाजार व्यवस्था की बढोत्तरी।<sup>5</sup>

इस समायोजक को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि मूल 15 क्षेत्रों को तीन प्रासंगिक समूहों में विभाजित किया जाये<sup>6</sup> प्रथम विशेष व्यापार प्रतिबन्धों पर कमी लाना तथा बाजार व्यवस्था की बढोत्तरी करना द्वितीय गैट सबधी दायरों को मजबूत करना। तृतीय सभी नये क्षेत्रों जैसे 'ट्रिप्स' 'ट्रिम्स' और सेवाएँ।

## गैट—1994

विश्व अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में और नए सिद्धान्तों के उदभव के साथ उरुग्वे दौर की वार्ता जो 1986 में शुरू हुई जिसे हम अन्तिम एक्ट या 'गैट 1994' के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा विश्व की व्यापार व्यवस्था में एक नया आयाम आया।

यह विदित है कि गैट स्वयं 1948 में शुरू किया गया था और यह अमरीका के आपसी व्यापार समझौता अधिनियम का निस्तारण था। मूलतः यह अमरीका तथा उसके व्यापारिक साथियों (देशों) के बीच आपसी बातचीत के लिये था जिसे राष्ट्रपति ट्रूमैन कई देशों पर लागू करना चाहते थे। यद्यपि गैट के लगभग 50 वर्ष जन्म लिये हो गए हैं परन्तु इसने अभी भी अपने जन्मगत स्वाभाव नहीं छोड़ा है। यह सत्य है कि जितनी भी आगामी गैट वार्ता के दौर हुए उन सभी में अमरीकी व्यापार अधिनियम, जो समय समय पर पारित होते रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपना प्रभाव डालते रहे हैं।



अन्तिम एक्ट एक भारी दस्तावेज है जिसमें व्यापार के लिये कई गैर पारम्परिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं पूरे विश्व में डकल प्रस्ताव और अब अन्तिम एक्ट पर जो प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की जा रही हैं वे भावनात्मक अधिक हैं जो कि प्राविधानों को पूरी तरह से न समझ पाने के कारण हैं। यह एक अर्धे द्वारा हाथी के विभिन्न हिस्सों को छूकर हर को हाथी ही समझने जैसा है। वर्तमान स्थिति में विश्व व्यापार में सेवा क्षेत्र का अत्यन्त तीव्रगति से विकास हो रहा है।

## **उरुग्वे दौर : डंकल प्रस्ताव के विभिन्न प्रावधान :**

गैट के पूर्व सम्मेलनों में औद्योगिक उत्पादों के व्यापार विस्तार हेतु प्रशुल्क को कम करने का प्रावधान था और कृषि एवं बागवानी क्षेत्र, गैट के प्राविधान में सम्मिलित नहीं थे। गैट प्राविधान लागू होने के पश्चात् सदस्य देश की कृषि को भी गैट व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित किया जा सकेगा।

विगत दो दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन आये हैं। हमने अपनी खाद्यान्न की समस्या का लगभग समाधान कर लिया है और कृषि क्षेत्र में एक स्थायित्व आया है यद्यपि कृषि उत्पादन में स्थिरता की स्थिति नहीं आई है फिर भी हम निर्यात करने की स्थिति में पहुँच गए हैं। आज इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि हम उच्च स्तर के कृषि उत्पादों का निर्यात करें और उससे जो विदेशी मुद्रा अर्जित हो उसे हम सस्ती वस्तुओं की खरीद के लिये उपयोग करें। कृषि उत्पादों के

निर्यात से जहाँ एक ओर हम देश के बकाया धनभुगतान की स्थिति को सुधारन क। नेय नगद मुद्रा अर्जित करते है वही दूसरी ओर कृषको को अधिक एव बहतर उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करते है।

भारतीय कृषि को विश्वव्यापी बनाने के पीछे मकसद है कि किसानों का बहतर लाभ मिले साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र को विकास के लिये जरूरी आर्थिक फायदा हो पर दुर्भाग्य से हम इन सब को पाने के लिये विश्व समुदाय का संरक्षण चाहते है। यदि कृषि को व्यापार मुखी बनाना है तो हमारे किसानों को भीतरी तथा बाहरी दोनों जगहों पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।

डकल प्रस्ताव पर आधारित गैट समझौते की आठव दोरे की वार्ता बहुत ही सही समय पर हुई है क्योंकि इसी समय भारत ने भी नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की है।

## डंकल प्रस्ताव में कृषि व्याख्या

**भाग (क)** कृषि पर उरुग्वे दौर की वार्ता

**भाग (ख)** सुधार कार्यक्रम पर विशेष बधीकरण प्रक्रिया पर समझौता।

**भाग (ग)** सफाई और पौध सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु समझौता करने वाली पार्टियों द्वारा निर्णय।

**भाग (घ)** पूर्ण खाद्य आयात करने वाले विकासशील देशों के सुधार कार्यक्रम पर पडने वाले सभावित नकारात्मक प्रभाव पर उपाय ।

## **भाग (क)**

**कृषि पर उरुग्वे दौर वार्ता मे कई निर्णय लिए गये<sup>7</sup>**

- 1 सभी भाग लेने वालो ने निर्णय लिया कि पुन्टाडेल ऐस्टेट घोषणा के अतरगत कृषि मे व्यापार पर सुधार प्रक्रिया चालू की जाय । इस बात पर ध्यान दिया जाये जिसमे दीर्घ कालीन उद्देश्यों के लिये मध्यावधि समीक्षा समझौता के अतर्गत एक साफ एव बाजार मुखी कृषि व्यापार प्रणाली तैयार की जाये और साथ ही एक सुधार कार्यक्रम चालू किया जाये जिसके अतर्गत गैट नियम एव कानूनो को अधिक प्रभावी सुदृढ, व्यापक और मजबूत बनाया जाय ।
- 2 इस बात पर भी ध्यान दिया जाय कि उपर्युक्त प्रस्तावित दीर्घ कालीन उद्देश्य मे एक सुनिश्चित समय मे कृषि पर सहायता एव सरक्षण के लिये प्रगतिशील कटौती की जाये ताकि विश्व कृषि मण्डियो मे जो उतार-चढाव है उसे समाप्त किया जाय ।
- 3 उद्देश्यो को प्राप्त करने हेतु प्रतिज्ञाबद्ध बाजार प्रवेश, स्वदेशी सहायता निर्यात प्रतिस्पर्धा और सेनेटरी तथा फाइटोसेनटरी मुद्दो पर समझौता करना ।

- 4 इस बात पर ध्यान दिया जाय कि सभी भाग लेने वालों के मध्य सुधार कार्यक्रम में बराबर की भागीदारी हो जिसमें गैर व्यापारिक बातों पर ध्यान दिया जाये जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण शामिल है और विकासशील देशों को विशेष ध्यान दिया जाय तथा पूर्ण खाद्य आयातित विकासशील देशों द्वारा सुधार कार्यक्रमों में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाय।

### विभिन्न पौधों को पेटेन्ट करना

विभिन्न प्रकार के पौधों को पेटेन्ट करना ट्रिप्स समझौते में एक प्रमुख दूरगामी प्रक्रिया है। विकासशील राष्ट्रों में कृषि कार्य, जीवन निर्वाह तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाये रखने का साधन है। अपने बीजों के प्रयोग के लिये किसानों के अधिकार की रक्षा करना और कीट नियंत्रक का इस्तेमाल, कृषि उत्पादन में वृद्धि का कारण है और इन राष्ट्रों के खाने के आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।<sup>8</sup>

पौधों के संरक्षण व पेटेन्ट के विषय में किसी देश के द्वारा प्रभावशाली पद्धति अपनाई जाती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानक से मेल खाती है और वह मानक (नये किस्म के पौधों के संरक्षण) के सम्मेलन में तय किया गया।

### उत्पाद विशिष्टता की वचनबद्धता :

---

<sup>8</sup> Dubey, Muchkund *An Unequal Treaty 1996*, Page 37

डकल प्रस्ताव के कृषि सम्बन्धी अध्याय एल के परिशिष्ट 8 में उत्पाद वर्णन की वचनबद्धता के सम्बन्ध में बताया गया है। जहाँ पर भी निर्यात के उत्पादों को सहायिकी परिशिष्ट 7 के पैराग्राफ 1(a) से 1(e) तक में बताया गया है कि उन सभी उत्पादों या उत्पाद समूहों के लिये उनका वर्णन और मात्रा भी निर्धारित की जायेगी<sup>9</sup> खास तौर पर 1 गेहूँ और आटा 2 मोटे अनाज 3 चावल 4 तिलहन 5 वनस्पति तेल 6 तेल केक 7 चीनी 8 मक्खन, घी 9 पाउडर दूध 10 पनीर 11 अन्य दुग्ध पदार्थ 12 ढोर मास 13 सुअर मास 14 पोलट्री मास 15 भेड़ मास 16 जिन्दा जानवर 17 अण्डे 18 वाइन 19 फल 20 सब्जी 21 तम्बाकू 22 कपास।

### सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपाय

सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी उपायों से संबंधित निर्णय में इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये कि ये निर्णय स्वास्थ्य तथा जीव-जन्तु हितों को हानि न पहुँचाये। हालांकि अधिकतर भाग लेने वालों का मानना था कि इस निर्णय के अंतर्गत केवल कुछ ही बातें स्वास्थ्य संबंधी हैं और अन्य उपभोक्ता बातों के साथ जीव हित के लिये अलग से प्रपत्र तैयार किये जा सकते हैं।

**सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायों के क्रियान्वन के लिये पार्टियों द्वारा निर्णय**

सभी सविदा करने वाली पार्टिया इस तथ्य को मानती है कि किसी को भी मानव, जैव एव वनस्पति जीवन और स्वास्थ्य के लिये आवश्यक उपाय अपनाने से नहीं रोका जायेगा परन्तु यह भी देखा जायेगा कि यदि समपरिस्थितिया हैं तो देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो रहा है या छिपे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रूकावट पैदा हो रही है।<sup>10</sup>

इस बात की अपेक्षा की जाती है कि सभी सविदा करने वाली पार्टियों के यहाँ मानव स्वास्थ्य, जैव स्वास्थ्य तथा फाइटोसेनेटरी स्थितियों में सुधार लाया जाय।

इसको ध्यान दिया जाये कि दो पक्षीय समझौते और प्रोटोकालों के आधार पर सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायों को लागू किया जाये।

अपेक्षा की जाती है कि सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायों का व्यापार में नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े इसके लिये बहुपक्षीय नियम एव कानून बनाये जाये।

इस सबध में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिशा निर्देश तथा सुझाव पर ध्यान देना<sup>11</sup> तथा अंतर्राष्ट्रीय एव क्षेत्रीय संगठन जो जो अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सुधार के अन्तर्गत कार्य

---

<sup>10</sup> वही, पृष्ठ L-35

<sup>11</sup> वही, पृष्ठ L-35

कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर सम्बन्धित पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भी सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायो को लयबद्ध तरीके से लागू करेंगे।

यह माना जाये कि विकासशील सविदा पार्टियों को सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपाय लागू करने में खास परेशानी होगी अतः इससे निपटने के लिये उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जाय।

सामान्य समझौता के प्राविधानों को लागू करने वाले नियमों जो सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायों से संबंधित हैं और खास तौर पर अनु० xx(b) के प्राविधानों से उन नियमों को आगे बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिए गये।

यह निर्णय उन सभी सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायों पर लागू होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं के सम्बन्ध में ऐसे उपाय किये जायेंगे जो निर्णय को लागू कर सकें। इस निर्णय के लिये ड्राफ्ट के परिशिष्ट 'A' में दी गई परिभाषाएँ लागू होंगी।

सभी परिशिष्ट इस निर्णय के आंतरिक हिस्से हैं।

यह निर्णय पक्षकारों के उन अधिकारों पर प्रभाव डालेगा जो व्यापार समझौते के तकनीकी अवरोध से सबधित हैं। इसमें मूलाधिकार एवं दायित्व के विषय में निम्न व्यवस्था की गयी है —<sup>12</sup>

- 1 इसमें अधिकार एवं दायित्व के विषय में भी निम्न सभी सविदा करने वाले पक्षकारों को अधिकार है कि जो मानव जैव, तथा वनस्पति जीवन या स्वास्थ्य के लिये सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपायों को अपनाये बशर्ते यह उपाय इस निर्णय के प्राविधानों से असंगत न हो।
- 2 सभी सविदा, पार्टियों को इस बात का ध्यान देना होगा कि सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपाय उसी सीमा तक लागू हो जहाँ तक मानव, जैव एवं वनस्पति जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हो और वे वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित हो तथा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के विरुद्ध न हो।
- 3 समपरिस्थितियों में सविदा करने वाली पार्टियों द्वारा सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपाय लागू करने में भेदभाव नहीं होना चाहिये और यह भी जरूरी है कि वे परोक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रूकावट नहीं डालें।



- 4 यह माना जायेगा कि इस निर्णय के अतर्गत सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपाय सभी सविदा पार्टियों के दायित्वों के आधार पर है जो कि सामान्य समझौता के प्राविधानों के अतर्गत आते हैं और जो सेनेटरी एव फाइटोसेनेटरी उपायों के उपयोग से सबधित है, मुख्यतः अनु० xx(b) में दिये गये प्राविधानों से।

## डंकल प्रस्ताव और बौद्धिक सम्पदा अधिकार :

बौद्धिक सम्पदा का आशय यह है कि किसी व्यक्ति या निगम के द्वारा आविष्कार करना और अधिकार से तात्पर्य यहाँ यह है कि आविष्कार का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या निगम के द्वारा प्रयोग करने के पूर्व में आविष्कारकर्ता से अनुमति प्राप्त करना तथा आविष्कारकर्ता को अनुमति प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में शुल्क प्राप्त करने के अधिकार से सुसज्जित करना है।

वर्ष 1980 के प्रारम्भ तक बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा को एक व्यापार व्यवस्था के पहलू के रूप में कभी नहीं सोचा गया था। दोनों विकसित और विकासशील राष्ट्र जानते थे कि नव परिवर्तन के लिये पारितोषिक और प्रोत्साहन के रूप में बौद्धिक सम्पदा का अधिकार खासकर पेटेन्ट के लिये भुगतान आवश्यक है। परिवर्तन और स्वदेशी तकनीकी के विकास में तथा औद्योगीकरण के उपकरण के रूप में साधन की तरह पेटेन्ट पर जोर दिया जाता था। जनता की रुचि ने भी स्थाई रूप से प्रमाणित किया और पेटेन्ट के उत्पादन की उचित दर पर आपूर्ति भी। इन्हीं कारणों से

कई राष्ट्रों ने पेटेन्ट के लिये कानून का निर्माण किया। जिसका उद्देश्य पेटेन्ट प्राप्त करता और जनता के बीच सन्तुलन बनाना है। पेटेन्ट का कार्य करने के लिये आवश्यक अधिकार का विधान समाहित था जैसे पेटेन्ट उत्पादन का स्थानीय निर्माण और केवल सवेदनशील आर्थिक क्षेत्रों में पेटेन्ट प्रक्रिया की स्वीकृति।<sup>13</sup>

भारत सहित कई विकासशील देश औद्योगिक सम्पदा की सुरक्षा (1967) के लिये पेरिस रिवाज पर दृढ़ नहीं रहे क्योंकि वह सोचते थे कि यह उनकी औद्योगिक नीति के रूप में आयेगी। भारत में कई बार सघीय मन्त्रिमण्डल के द्वारा विचार के लिये पेरिस रीति पर मूल्य निर्धारण का प्रश्न आया। प्रत्येक बार मन्त्रिमण्डल ने मूल्य निर्धारण के लिये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1970 के अन्त और 1980 के प्रारम्भ में अकटाड के शुरू में विकासशील देशों ने पेरिस रिवाज में परिवर्तन लाने की कोशिश किया विशेषतया पेटेन्ट के कार्यों को पेटेन्ट प्राप्त कर्ता के आधार के रूप में उनके विकास आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दिखाना।

यह भी सत्य है कि नव ज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्तमान में बड़ी तेजी से चारों ओर फैल रही है। नव ज्ञान पाने की क्षमता विश्व स्तर पर बढ़ गयी है बहुत से विकासशील राष्ट्रों ने नव ज्ञान और प्रौद्योगिकी को कुशलता पूर्वक बढ़ाने की क्षमता निर्मित की है।

## ट्रिप्स समझौता और भारत के पेटेन्ट अधिनियम 1970 के बीच तुलना

- 1 भारतीय अधिनियम बहिष्कृत करता है कि आणविक ऊर्जा कृषि, बागवानी और जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया और पेटेन्ट के उत्पादनो को । ट्रिप्स समझौता इन सारे तरीको और उत्पादनो को पेटेन्ट के योग्य बनाता है ।
- 2 भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक पेटेन्ट, दवाये, ड्रग्स व रासायनिक उत्पादो को स्वीकृत करता है । जब कि ट्रिप्स समझौता इन तमाम क्षेत्रो मे उत्पादक पेटेन्ट की स्वीकृत प्रदान करता है ।
- 3 भारतीय अधिनियम के अनुसार जहा प्रक्रियात्मक पेटेन्ट की अवधि मात्र 5—7 वर्षो तक उत्पादन के लिये तथा 14 वर्ष के लिये होती है वही ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत यह 20 वर्षो के लिये हो जायेगी ।
- 4 भारतीय पेटेन्ट अधिनियम मे प्रभावशाली प्रक्रियाये उपलब्ध है जिसे अनुज्ञा का अधिकार कहते है जब कि ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत आवश्यक अनुज्ञा अथवा अधिकार के अनुज्ञा अथवा पेटेन्ट के खण्डन के लिये कोई ऐसा खास विधान नही है ।

## बौद्धिक सम्पदा व्यापार सम्बन्धी अधिकार के प्रकार .

ट्रिप्स सात तरह की होती है। यथा कापीराइट ट्रेड मार्क व्यापार गोपनीयता, उद्योग डिजाइन, इन्टीग्रेटेड सर्किट्स, ज्योग्राफिकल इंडीकेशन्स और पेटेन्ट्स सिवाय पेटेन्ट्स के बाकी सभी के लिये हमारे यहा वही नीतिया, नियम और कानून है जो कि विश्व के अन्य देशो मे प्रचलित है। डकल प्रस्ताव मे बताए गए पैमाने भारतीय पेटेन्ट्स एक्ट 1970 से काफी भिन्न है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार उन वैज्ञानिको एव पौधे उगाने वालो के लिये वरदान है जो कि नई किस्म के पौधो के अनुसंधान मे लगे हुए है। इसमे कोई शक नही है कि यह तरीका हमारे देश के लिए नया है। परन्तु यूरोप मे सन् 1961 से पौधो के किस्मो के सरक्षण के लिये कई नियम है।

## बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्तन :

व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) पर विश्व व्यापार सगठन समझौता इस तथ्य को मानता है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सरक्षण तथा प्रवर्तन मे काफी भिन्नताए है तथा जाली वस्तुओ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक हेतु बहुपक्षीय कानूनों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सबधो मे तनाव बढता जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए यह समझौता गैट के उद्देश्यो को लागू करना चाहता है। समझौते का भाग 1 सामान्य प्रविधानो और मूल उद्देश्यो का वर्णन करता है खास तौर पर एक राष्ट्रीय प्रबध वादा जिसके अतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सरक्षण के

लिये विदेशी नागरिकों को वही सहूलियत प्रदान की जायेगी जैसी की एक राष्ट्र अपने नागरिकों को देता है। इसके अतर्गत परममित्र राष्ट्रों का उप-नियम आता है जिसके अतर्गत यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य देश के नागरिक को कोई खास लाभ देता है तो वैसी ही सहूलियत अन्य सदस्यों के नागरिकों को भी देनी होगी चाहे इस तरह का प्रबन्ध स्वदेशी नागरिकों की अपेक्षा विदेशियों के लिये अधिक ही क्यों न हो।

समझौते के भाग II में विभिन्न प्रकार के बौद्धिक सम्पदा अधिकार का वर्णन है। यह इस बात पर जोर देता है कि सभी सदस्य देशों में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ आरम्भिक बिन्दु विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के पूर्व चली आ रही परम्पराओं को माना गया, जैसे कि बौद्धिक सम्पदा संरक्षण हेतु जिन मुद्दों पर प्रचलित पेरिस सम्मेलन चुप है या पूर्ण नहीं है उन पर इस समझौते में नवीन उँचे स्तर के नियम जोड़ दिये गये हैं।

कापीराइट के विषय में यह समझौता मानता है कि कम्प्यूटर प्रोग्रामों को वर्न सम्मेलन के तहत साहित्यिक कार्य के रूप में संरक्षित किया जायेगा और यह भी बताया गया है कि कैसे डाटा बेसों को संरक्षित किया जाय।

काफी राइट के अंतर्राष्ट्रीय नियमों में एक खास पहल की गई है कि वह भाड़े या किराये के अधिकार का प्राविधान कम्प्यूटर प्रोग्रामों के रचयिता तथा ध्वनि संग्राहक को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी कृति को जनता के लिये व्यापारिक भाड़े पर

किसी को दे सकते हैं अथवा देने से मना कर सकते हैं। इसी प्रकार के अधिकार फिल्मों पर लागू होते हैं। साउण्ड रिकार्डिंग के प्रोड्यूसरों को अधिकार होना चाहिये कि अपनी रिकार्डिंग के पुनर्प्रोडक्सन पर 50 वर्षों तक के लिये प्रतिबंध लगा सके।

यह समझौता यह भी बताता है कि ट्रेडमार्क या सेवा मार्क के लिये कौन से चिन्ह सरक्षित किये गये हैं और उनके मालिकों के लिये न्यूनतम अधिकार कैसे होने चाहिये। जो मार्क किसी राष्ट्र में काफी प्रचलित हो चुके हैं उन्हें अतिरिक्त सरक्षण प्राप्त है। यह समझौता ट्रेडमार्क और सेवा मार्क के लिये कई दायित्वों का वर्णन करता है उनके सरक्षण की शर्तें तथा उनके लाइसेन्स देने के नियम। उदाहरण के लिये, सामान्य नियम के तहत विदेशी मार्क, लोकल मार्कों के साथ उपयोग नहीं किये जा सकते हैं।

भौगोलिक चिन्हों के संबंध में सदस्यों को चाहिये कि वे ऐसे चिन्हों के उपयोग को रोकें जिनसे वस्तु की उत्पत्ति को लेकर उपभोक्ता भ्रमित होता है और किसी भी प्रकार के उपयोग से गलत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। वाइन और स्प्रिट के भौगोलिक चिन्हों को उच्च स्तरीय सरक्षण प्राप्त है। कुछ अपवाद इसमें भी हैं। वाहन के भौगोलिक चिन्हों के लिये बहुपक्षीय प्रणाली हेतु भविष्य वार्ता का भी प्रबंध है।

समझौते के तहत औद्योगिक डिजाइनों को 10 वर्ष का सरक्षण प्राप्त है। सरक्षित डिजाइनों के स्वामियों को अधिकार प्राप्त कराया जाना चाहिये कि वे सरक्षित डिजाइन की प्रतिलिपि के उत्पादन बिक्री तथा आयात पर प्रतिबन्ध लगा सकें।

जहाँ तक पेटेन्टों का सबन्ध है, समझौते के तहत 20 वर्षीय सरक्षण सभी प्रकार की तकनीकों के सभी खोजों पर उपलब्ध कराया जाये। पेटेन्टीकरण से अविष्कारों को अलग रखा जा सकता है यदि जन आदेश या नैतिकता के कारणों से उनके वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक है। पेटेन्ट प्रक्रिया के लिये जो अधिकार दिये गये हैं वे उन उत्पादों पर भी सीधे लागू किये जाने चाहिये जो इस प्रक्रिया से प्राप्त किये गये हैं। कुछ दशाओं में न्यायालय इस बात की आज्ञा दे सकते हैं कि इसका प्रमाण किया जाये कि पेटेन्ट प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया है।

‘ले आउट डिजाइन्स आफ इन्टीग्रेटेड सर्किट्स’ के सरक्षण के सम्बन्ध में सदस्यों को चाहिये कि वे वाशिंगटन संधि जो बौद्धिक सम्पदा के इन्टीग्रेटेड सर्किट्स के सम्बन्ध में मई 1989 में की गयी के आधार पर सरक्षण प्रदान करें। इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जैसे— कम से कम 10 वर्ष का सरक्षण दिया जाना, उन सभी वस्तुओं पर ये अधिकार हों जो ‘इनफ्रिन्जिंग ले आउट डिजाइन्स’ को समाहित करते हैं, स्वार्थहीन इन्फ्रीजर्स को इस बात की छूट होनी चाहिये कि वे सारे

बचे माल का उपयोग कर सके या फिर उसे बेच सके पर इसके लिये उसे उपयुक्त रायलटी देनी होगी।

व्यापार गोपनीयता तथा जानकारी जिसका वाणिज्यिक महत्व है उसे विश्वास भग तथा अन्य कार्य जो सच्चे व्यापारिक प्रक्रिया के विरुद्ध हो सरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। औषधि एवं कृषि रसायनों पर हुये परीक्षण जो सरकारी मजूरी के लिये प्रेषित हो उन पर भी सरक्षण दिया गया है। सविदा लाइसेन्सों की गैर-प्रतियोगी प्रक्रिया के लिये सदस्यों को अधिकार प्राप्त है तथा सरकारों को भी छूट है कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार के गलत उपयोग पर रोक हेतु आपसी वार्ता कर सकते हैं।

समझौते का भाग III प्रवर्तन से संबंधित है इसमें कहा गया है कि सरकारों को चाहिये कि वे स्वदेशी नियमों के अन्तर्गत ऐसे उपाय तथा प्रक्रिया अपनाये जिसके द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकार को अच्छी तरह से लागू किया जा सके। ये प्रक्रिया सीधी, सस्ती तथा समय बचाने वाली हो।

व्यवहार तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तथा उपाय जो यहाँ बताए गए हैं उनके अंतर्गत साक्ष्य, तदर्थ उपाय, निर्देश, क्षतिपूर्ति और अन्य उपाय के प्राविधान आते हैं जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी प्रतिबंधित वस्तुओं के विक्रय या नष्टीकरण का आदेश दे सकते हैं साथ ही ट्रेडमार्क के गलत उपयोग या कापीराइट पाइरेसी पर सदस्यों को चाहिये कि वे दण्डात्मक नियम व कानून बनाये। इसके अतिरिक्त सदस्यों



को चाहिये कि अधिकार धारक के जाली तथा चुराये गये वस्तुओं के आयात पर कस्टम अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सके।

बीच के समय के लिये समझौते के अनुसार विकसित राष्ट्रों को अपने यहाँ के विधेयक तथा प्रक्रिया को समरूप बनाने हेतु एक वर्ष का समय दिया जाता है। विकासशील देशों के लिये पाच वर्ष तथा अल्प विकसित राष्ट्रों को 11 वर्ष का समय दिया गया है।

जिन विकासशील देशों के यहाँ उत्पादन पेटेन्ट संरक्षण की व्यवस्था नहीं है उन्हें 10 वर्ष का समय दिया गया है कि इसकी व्यवस्था वे इस अंतराल में कर लें। वस्तु, औषधि, एवं कृषि रसायनों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। यदि परिवर्तन के समय में किसी औषधि या कृषि रसायन के व्यापार के लिये अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो तो उक्त विकासशील राष्ट्र को चाहिये कि वह पाच वर्षों के लिये या जब तक उत्पाद का पेटेन्ट नहीं करा लिया जाता है, इन दोनों में से जो पहले पूर्ण होता है उसके लिये विशेष बिक्री अधिकार दिये जाने चाहिये।

कुछ विशेष प्रमुख अपवादों को छोड़कर सामान्यतः इस समझौते के दायित्व सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर लागू होगी और साथ ही नये पर भी लागू होंगे। सरकारों द्वारा अनुपालन और समझौते को लागू करने हेतु व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार परिषद का गठन किया गया है।

## बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार सबधित पहलू पर समझौता<sup>14</sup> .

**भाग I** सामान्य प्राविधान तथा मूलभूत सिद्धान्त ।

**भाग II** बौद्धिक सम्पदा अधिकार की उपलब्धता दायरा एव प्रयोग से सबधित स्तर ।

- 1 कापीराइट तथा सबधित अधिकार
- 2 व्यापार चिन्ह
- 3 भौगोलिक चिन्ह
- 4 औद्योगिक डिजाइन्स
- 5 पेटेन्ट्स
- 6 इन्टीग्रेटेड सर्किट्स के ले आउट डिजाइन
- 7 प्रकट न की गई सूचना का सरक्षण
- 8 प्रतियोगिता विरोधी कार्यो का नियत्रण

**भाग III** बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रवर्तन

**भाग IV** बौद्धिक सम्पदा अधिकार का ग्रहण एव रखरखाव और सबधित  
अन्त पक्षकार प्राविधान

**भाग V** विवाद निस्तारण और विवादो को रोकना

**भाग VI** परिवर्तन व्यवस्था

**भाग VII** सस्थाओ के सिद्धान्त सबधी व्यवस्था ।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अतर्गत सभी पक्षकार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूकावटों और कमियों को दूर करना चाहते हैं और जो इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं वे यह भी ध्यान देंगे कि वे स्वयं व्यापार में बाधा नहीं पहुँचाएँगे।

इस सम्बन्ध में वे सभी नियम और कानून को मान्यता है जो कि –

- (a) गैट के मूलभूत सिद्धान्तों और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा समझौते के अनुरूप लागू हो।
- (b) पूर्ण स्तरीय प्राविधान तथा व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सिद्धान्तों की उपलब्धता, दायरा एवं इस्तेमाल।
- (c) व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रवर्तन के लिये सही और कारगर प्राविधान साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के कानूनी प्रणालियों में भेद।
- (d) विभिन्न सरकारों के मध्य बहुपक्षीय विवादों पर रोक एवं उनके निस्तारण के तेज और कारगर प्राविधानों को बनाना है, और
- (e) वार्ता के परिणामों की पूर्ण भागीदारी के लिये परिवर्तन व्यवस्था को ध्यान में रखना— बहुपक्षीय सिद्धान्तों, नियमों और कानूनों जो कि जाली वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित हो उनके लिये एक ढाँचे को अभिस्वीकार करना।

— अभिस्वीकार करना कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार निजी अधिकार है ।

— बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय नियमों के तहत सामाजिक नीतियों को अभिस्वीकार करना जिसके अतर्गत विकासशील एवं तकनीकी उद्देश्य भी शामिल है ।

— एक अच्छे तकनीकी आधार हेतु ऐसे नियमों का प्रतिपादन जिससे अल्प विकसित देशों की खास आवश्यकताओं की पूर्ति को अभिस्वीकार करना ।

— व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विवादों के निस्तारण हेतु बहुपक्षीय प्रक्रियाओं को अपनाना जिससे आपसी तनाव कम हो ।

गैट तथा विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के साथ-साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य आपसी सहयोग की बढ़ोत्तरी के लिये प्रयास करना ।

### **वस्त्र एवं परिधान व्यापार समझौता :**

सन् 1960 के आरम्भिक वर्षों से ही वस्त्र एवं कपड़ा व्यापार को गैट के अतर्गत विशेष दर्जा दिया गया और विकसित राष्ट्रों को उद्योगों द्वारा झेली जा रही कठिनाईयों के कारण इसे विशेष नियमों के अतर्गत रखा गया । 1974 से यह बहुतन्तु समझौता परम मित्र राष्ट्र के अतर्गत शासित होता आ रहा है ।

विकसित राष्ट्रों ने परम मित्र राष्ट्र के आधार पर दो पक्षीय वार्ता द्वारा या स्वयं से ही वस्त्र एवं कपड़े के आयात पर प्रतिस्पर्धा वाले विकासशील देशों का कोटा निर्धारण कर दिया। इस क्षेत्र का विश्व व्यापार संगठन (गैट 1994) की मुख्य धारा में समाकलन के लिये उरुग्वे दौर में वार्ता की गई और इसे दस वर्ष के समय के अन्दर धीरे-धीरे लागू किया जायेगा। इसके लागू होने पर सूती रेशमी, एवं सिन्थेटिक वस्त्रों परिधान एवं तागो पर गैट के विधान लागू हो जायेगे। कई विकासशील देश यथा भारत, बांग्लादेश वस्त्र व्यापार में अग्रणी रहे यह सोचा गया कि इससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वस्त्र व्यापार का क्षेत्र विकसित होगा तथा वस्त्र व्यापार एवं अन्य वस्तुओं के व्यापार में पूर्ण समन्वय स्थापित हो सकेगा।

बहुतन्तु समझौता प्रतिबंध जो 31 दिसम्बर 1994 को थे वे नये समझौते में शामिल कर लिये गये और तब तक रहेगे जब तक वे धीरे-धीरे बाहर नहीं कर दिये जाते और वस्त्र एवं कपड़ा भी अन्य औद्योगिक उत्पादों की तरह गैट के नियम और कानून में समाहित हो जाता है। इस समाकलन कार्यक्रम के चार चरण हैं —

- 1 प्रत्येक पार्टी जो 1 जनवरी 1995 को विशेष सूची से अनुकूलित की गई है और जो अपने वस्त्र एवं कपड़ा आयात के कुल 16 प्रतिशत से कम न हो 1990 में।
- 2 1 जनवरी 1998 को 1990 के आधार पर आयातित उत्पाद जो 17 प्रतिशत से कम न हो वे अनुकूलित कर लिये गये।

- 3 1 जनवरी 2002 को 1990 के आधार पर आयातित उत्पाद जो 18 प्रतिशत से कम न हो उसे अनुकूलित कर लिया जायेगा।
- 4 1 जनवरी 2005 को सभी बाकी उत्पाद सम्मिलित कर लिये जायेगे।

प्रत्येक प्रथम तीन चरणों में निम्न श्रेणी में से उत्पाद चुने जायेगे सूती वस्त्र तथा परिधान और बाकी बचे उत्पादों के लिये किसी भी स्तर पर समझौते में एक फार्मूला दिया जा रहा है ताकि वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके। इस तरह प्रथम चरण (1995 से 1997 निहित) में परम मित्र राष्ट्र दो पक्षीय समझौते पर प्रत्येक प्रतिबंध पर 1994 के आधार पर सालाना वृद्धि 16 प्रतिशत से कम न हो। दूसरे चरण (1998 से 2001 निहित) में वार्षिक वृद्धि दर 25 प्रतिशत अधिक चरण 1 से होनी चाहिये। तीसरे चरण (2002 से 2004 निहित) में सालाना वृद्धि दर चरण दो से 27 प्रतिशत अधिक होनी चाहिये।

किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य द्वारा कोई गैर परम मित्र राष्ट्र प्रतिबंध रखा जा रहा है और जिसे गैट के अंतर्गत उचित नहीं माना गया है तो उसे 1996 तक गैट के अधीन लाया जायेगा या फिर धीरे-धीरे उसे 2005 तक समाप्त कर दिया जायेगा। एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था सदस्यों को प्रदान की गई है ताकि वे निर्यातक राष्ट्रों के विरुद्ध प्रतिबंध लगा सके पर वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे यह दिखा दे कि आयातित वस्तु जो अलग-अलग राष्ट्रों द्वारा की जा रही है वह स्वदेशी उद्योग को गम्भीर हानि पहुँचा सकती है।

कुछ राष्ट्रों के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है जैसे कि उन देशों के लिये जो 1986 से परम मित्र राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, जो बाजार में नये आये हैं तथा छोटे सप्लायर तथा अल्प विकसित राष्ट्र हैं। शेष सभी के लिये समझौते में ऐसे नियम व कानून बनाये। जो विश्व व्यापार संगठन को शक्ति प्रदान करते हैं तथा तन्तु एवं कपड़ा उत्पादों को बेहतर बाजार व्यवस्था कायम करने में सहायता प्रदान करते हैं।

## स्वास्थ्य तथा पौध सुरक्षा उपाय :

सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी उपायों सम्बन्धित समझौते के अन्तर्गत वे सभी प्रतिबन्ध आते हैं जो खाद्य सुरक्षा तथा जीव-जन्तु एवं पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं इस समझौते के अन्तर्गत सभी सरकारों को अधिकार है कि वे सेनेटरी एवं फाइटोसेनेटरी उपायों को लागू करें परन्तु ये विज्ञान पर आधारित होने चाहिये और इन्हें तभी तक लागू किया जाये जब तक ये मानव, जैव, वनस्पति जीवन एवं स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न डालें। साथ ही समपरिस्थितियों में सदस्यों को एक दूसरे के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये।

## सेवा में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)

सेवा व्यापार से अभिप्राय किसी देश द्वारा किसी सदस्य देश की सीमा में उत्पादन वितरण, विनियम और भण्डार की सुविधा जैसी सेवाएं प्रदान करने से है। इन सेवाओं के अन्तर्गत वित्तीय सेवाएँ, दूर संचार, यातायात और प्राविधिक सहयोग

आदि सम्मिलित है। गैट्स मूल रूप से एक बहुपक्षीय ढांचा है जो सिद्धांतों एवं नियमों, सेवा में व्यापार की पारदर्शिता और प्रगतिशील उदारता को प्रस्तुत करता है।

## सेवाओं में व्यापार विकास तथा निवेश के नियम :

गैट्स का अनु० (16) विदेशी बाजार के लिये विशिष्ट वादे करता है। इस अनु० में व्यवस्था है कि क्षेत्र या उपक्षेत्र में जहाँ बाजार आधिक्य के लिये कमिटमेंट हुआ है कोई सदस्य निम्न को न कायम रख सकता है और न तो प्राप्त कर सकता है।<sup>15</sup>

- 1 सेवा प्रदाता की संख्याओं पर सीमा निर्धारण।
- 2 सेवा प्रवर्तन के मूल्य पर सीमानिर्धारण।
- 3 कुल सेवा उत्पादन की मात्रा।
- 4 प्राकृतिक व्यक्तियों की संख्या जो किसी खास सेवा में लगे हैं।
- 5 विदेशी पूँजी सहभागिता की अधिकतम सीमा निर्धारण।



## सेवा में सामान्य समझौते:

जिस पर उरुग्वे दौर में चर्चा हुई वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवा पर लागू होने वाले नियम और कानून का प्रथम हिस्सा है जिस पर बहुपक्षीय सहमति है और यह कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है। इस समझौते में 3 मुख्य बातें हैं। 1 सामान्य नियम और कानून का ढांचा 2 प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपनियम तैयार करना एनेक्सेस 3 और बाजार प्रवेश हेतु राष्ट्रीय सूची तैयार करना है। जो इस समझौते के आंतरिक हिस्से हैं।

इस समझौते के अनुपालन के लिये सेवा में व्यापार के लिए परिषद बनायी गयी है। परिषद ढांचे के अंतर्गत 29 अनुच्छेद आते हैं— इस समझौते के दायरे में सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवा आती है चाहे जैसे भी प्रदान की जाये। समझौता चार प्रकार से सेवा प्रदान करने का जिक्र करता है एक सदस्य राष्ट्र से दूसरे सदस्य राष्ट्र को सेवा प्रदान करना जैसे—अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष सेवा। एक सदस्य के क्षेत्र में अन्य किसी को सेवा प्रदान करना जैसे पर्यटन, एक सदस्य के वाणिज्य व्यवस्था को अन्य किसी के लिये सेवा में देना जैसे—बैंकिंग। एक सदस्य के व्यक्तियों द्वारा अन्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करना जैसे—फैशन मॉडल या कन्सल्टेनसी।

## परम मित्र राष्ट्र (MFN) बन्दोबस्त :

एक सरकार को चाहिये कि वह अन्य सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवा के साथ कोई भेदभाव नहीं बर्ते यदि सरकारें अन्य राष्ट्रों को विशेष दर्जा कुछ खास सेवाओं के लिये देना चाहती हैं तो उन्हें एक बार का अवसर दिया गया कि वे ऐसा परम मित्र राष्ट्र छूट के द्वारा कर ले जो कि गैट्स के लागू होने के पूर्व था। इस प्रकार की छूट की लिस्ट पर प्रत्येक पांच वर्षों बाद पुनर्निरीक्षण किया जायेगा और इसका सामान्य कार्यकाल 10 वर्ष का होगा।

## पारदर्शिता :

इसके लिये आवश्यक है कि सभी जरूरी नियम व कानूनों का प्रकाशन हो। तटकरों की गैर मौजूदगी के कारण स्वदेशी कानून ही सेवा व्यापार पर सबसे अधिक प्रभाव एवं नियंत्रण प्रदान करते हैं। अतः समझौता यह चाहता है कि ऐसे सभी उपायों का क्रियावन्धन तर्कसंगत, उद्देश्यपूर्ण तथा बिना भेदभाव के किया जाये। सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा प्रदान करने संबंधित सभी प्रशासनिक निर्णयों के सिंहालोकन के लिये शीघ्र व्यवस्था कायम करें।

## मान्यता या अभिस्वीकार :

यदि दो सरकारें आपस में योग्यताओं के मान्यता पर आपसी समझौता करती हैं जैसे सेवा प्रदायीयों के लिये अनुज्ञा या प्रमाण-पत्र। तो इस समझौते के अंतर्गत

उन्हे समरूप समझौते के अतर्गत उन्हे समरूप समझौतो पर अन्य सदस्यों के साथ भी वैसे ही समझौते करने होंगे। अभिस्वीकारकरण भेदभाव पूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता है और न ही उसे इस तरह लागू किया जाये कि उसके द्वारा छिपे तौर पर व्यापार में बाधा पहुँचे।

### **अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तथा हस्तान्तरण :**

इस समझौते के तहत विशेष वादों से संबंधित चालू सौदों के लिये अंतर्राष्ट्रीय भुगतान एवं हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं होगी परन्तु यदि बकाया भुगतान में कठिनाइयाँ हैं तो ये एक रोक सीमित अल्प कालिक और शर्तों के तहत होगी।

### **बाजार प्रवेश और राष्ट्रीय प्रबंध :**

बाजार प्रवेश और राष्ट्रीय प्रबंध के वादे राष्ट्रीय सूची में दर्ज हैं। जिस सेवा या सेवा कार्य के लिये बाजार प्रवेश की गारंटी है उन्हें सूची में दर्ज किया गया है। यदि विदेशी सेवा प्रदाइयों पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है और उन्हें स्वदेशी प्रदाइयों से कम सहूलियत दी जाती है तो उसे सूची में दर्ज करना होगा। ये वादे बाध्यकारी हैं और उन्हें सशोधित या वापस तभी लिया जा सकता है जब प्रभावित देश से हानि पूर्ति के लिये वार्ता हो जाये। अतः यह ऐसी गारन्टीपूर्ण शर्तें प्रदान करता है जिसके अतर्गत विदेशी निवेशक तथा सेवाओं के निर्यातक एवं आयातक धन्या आराम से कर सकते हैं।

## व्यापार सम्बन्धी विनियोग उपाय (TRIMS) :-

विगत वर्षों में विदेशी विनियोग औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति में एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है विकसित देशों के विभिन्न निगम विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विनियोग कर रहे हैं विकासशील देश विनियोग कर्ताओं पर विनियोग हेतु कुछ शर्तें लगाते हैं इसी को हम विनियोग शर्तें कहते हैं। यह संरक्षणवादी प्रवृत्ति विनियोगकर्ता देश के द्वारा कही जाती है और इस समय इसको हटाने या कम करने की प्रक्रिया जारी है।

विदेशी पूँजी निवेश शताब्दियों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 18वीं और 19 शताब्दियों के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय शक्तियों और संयुक्त राज्य विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में समर्थ थे। जो अपने नागरिकों तथा कंपनियों के लिये बेहतर व्यवस्था करना चाहते थे उनके द्वारा थोपे गयी व्यवस्था के अनुसार मेजबान देश को विदेशी सम्पत्ति में हस्तक्षेप करने की मनाही थी। यह बातें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों की बातें थीं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात् बड़ी प्रमुख सम्पन्न शक्तियाँ उस समय भी विदेशी पूँजी निवेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा थीं। 1948 में हवाना के सम्मेलन में जिसपर बहस हुई थी। हवाना चार्टर्ड की बातचीत से संकेत मिले की

सरकारे अन्तर्राष्ट्रीय नियम कानूनो अपने निवेश नीति मे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे<sup>16</sup>

वास्तव मे प्रतिबधित व्यापार पर राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगो मे नियत्रण पर अधिक जोर था। नियत्रण एव नियमन हेतु 'बनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय कानून' मे सहृदयता नहीं थी। जो ऐसे निवेशो के लिये बनाये गये। यहा तक कि हवाना चार्टर्ड मे इसके लिये एक अलग अध्याय था।

वर्ष 1950 और 1960 के प्रारम्भ मे राष्ट्रीय सशाधनो पर स्थाई प्रभुत्व के लिये सयुक्त राष्ट्र सभा के सत्रो मे प्रस्ताव अगीकार किये गये। जिसमे यह व्यख्या की गयी कि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सम्पदा या सारे सशाधनो का उपयोग स्वतत्र रूप से कर सकता है। राष्ट्रीय हितो पर मेजबानो को सप्रभुता एव विदेशी उद्यमो के क्रिया कलापो एव अधीनस्थता को ध्यान मे रखते हुए 1974 मे एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसमे आचार्य सहिता एव तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे भी थे 1970 मे विदेशी उद्यम एव व्यापार व्यवहार अपनी चरम सीमा पर पहुच गया था परन्तु विकासशील राष्ट्र विदेशी प्रभाव एव ऋण के कारण 1980 के प्रारम्भ मे पुन विपरीत दिशा मे सोचने लगे और अपनी विकास योजनाओ के रूप मे सरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमो को लागू करने लगे इस बदली हुई परिस्थित का फायदा लेकर सयुक्त राज्य और इसके प्रमुख

विकसित देशों ने इस विषय को उरुग्वे दौर में इस विचार धारा के साथ प्रस्तुत किया कि—<sup>17</sup>

- (a) राष्ट्रीय ससाधनों पर स्थाई अधिकार एवं राष्ट्रीय दोहन/उपयोग के अधिकार के विपरीत दिशा में जाना।
- (b) आन्तरिक अवरोधों को कम करते हुए विकासशील देशों में विदेशी उद्योगों को स्थापित करना।
- (c) ऐसे उद्यमों के विशेषाधिकारों के लिये व्यवस्था कायम करना।

उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए संयुक्त राज्य में उरुग्वे दौर में ट्रिम्स से सम्बन्धित समझौते के कुछ विशेष उद्देश्य रखे—<sup>18</sup>

- (a) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये व्यापार अवरोध कम करना या समाप्त करना।
- (b) परम मित्रराष्ट्र और राष्ट्रीय सिद्धांतों के विदेशी निवेश हेतु विस्तार करना।
- (c) निश्चित व्यापार सम्बन्धी विनियोग, उपायों को पहचानना उनके निषेध की अनुमति प्राप्त करना।
- (d) सूचना प्रक्रिया द्वारा ऐसे उपायों में काफी सीमा तक पारदर्शिता प्रस्तुत करना।

---

17 Dubey, Muchkund *An Unequal Treaty*, 1996, Page 67

17 Dubey, Muchkund *An Unequal Treaty*, 1996, Page 67

- (e) एक ऐसी सस्था का निर्माण करना जो कि ट्रिम्स के प्रावधानों को लागू कर सके।

### ट्रिम्स सम्बन्धी प्रावधान :

डकल प्रस्ताव में इस बात पर विस्तृत चर्चा की गयी है, इसके अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं—

सविदा करने वाले पक्षकार इस बात को ध्यान में रखते हैं कि पुन्टाडेल स्टैट घोषणा में मिनिस्टर इस बात के लिये सहमत हुए कि गैट अनुच्छेदों से सबधित निवेश उपायों पर प्रतिबधित व्यापार के लिये आगे वार्ता का प्राविधान रखा जाये ताकि व्यापार पर विपरीत प्रभाव को रोका जा सके।

- 1 यह अपेक्षा की जाती है कि विश्व व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के लिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के लिये सम्पूर्ण प्रयास किये जाय ताकि सभी व्यापारिक वर्गों का विशेषरूप से विकासशील देशों का उन्नयन हो तथा जिसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा कायम रहे। इसमें यह भी व्यवस्था की गयी है कि विकासशील देशों खासतौर पर अल्पविकसित राष्ट्रों के व्यापार विकास तथा आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये इसके साथ ही साथ इस तथ्य

को भी ध्यान में रखा जाये कि कुछ निवेश उपाय व्यापार पर रूकावटें ला सकते हैं<sup>19</sup>।

डकल प्रस्ताव के भाग 'एन' के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि यह निर्णय केवल वस्तु व्यापार के निवेश उपायों पर लागू होगा। (इसे अब ट्रिम्स से संबोधित किया जायेगा) इसी श्रृंखला में अनुच्छेद 2 में राष्ट्रीय उपचार तथा गुणात्मक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत अन्य अधिकार एवं कर्तव्यों को बिना भेदभाव के कोई भी सविदा करने वाला पक्षकार किसी भी ट्रिम्स को लागू नहीं करेगा जो कि अनु० 3 या अनुच्छेद 11 में दिये गये प्राविधानों से भिन्न हों<sup>20</sup>।

2 एक व्याख्यात्मक ट्रिम्स की सूची जो कि अनु० III 4 में दिये गये राष्ट्रीय उपचार के कर्तव्यों से भिन्न है और अनुच्छेद XI 1 में दिये गये गुणात्मक प्रतिबन्धों के कर्तव्यों के लिये इस निर्णय के परिशिष्ट में दी जा रही है।

## सहायिकी पर समझौता और काउन्टरवेलिंग उपाय :

डकल के प्रस्ताव के वर्ग 1 भाग 'एन' के विभिन्न अनुच्छेदों में इस सदर्भ में व्यवस्था की गयी है।

---

19 डकल ड्राफ्ट, पृष्ठ एन-1

20 वही, पृष्ठ एन-1



## अनुच्छेद 1 सहायिकी की परिभाषा<sup>21</sup> :

1.1 इस समझौते के लिये सहायिकी का अर्थ है —

- (a) (1) इस समझौते में शामिल कोई भी सरकार या अन्य कोई सार्वजनिक संस्था द्वारा आर्थिक सहायता (जिसे अब सरकार कहा जायेगा) — जहाँ —
- (i) सरकार द्वारा सीधे फंड ट्रांसफर किये जाते हों (जैसे— अनुदान ऋण और समता) या दायित्वों का सीधा ट्रांसफर हो (जैसे लोन गारन्टी) ।,
- (ii) सरकारी कर जो बाकी हों उसे छोड़ दिया जाये या न जमा कराया जाये (जैसे— टैक्स, क्रेडिट)
- (iii) सरकार द्वारा सामान्य ढाँचे के अतिरिक्त माल या सेवा प्रदान किया जाना अथवा वह स्वयं माल खरीद ले ।
- (iv) कोष के लिये सरकार स्वयं पैसे दे या किसी निजी संस्था को निर्देश दे या उसे सौंप दे कि वह (i) से (iii) तक में दिये गये कार्यों का प्रतिपादन करे और यह प्रक्रिया लगभग सभी सरकारों द्वारा अपनाई जाती है या सहायिकी देने के निर्णय पर यदि यह सबपैराग्राफ लागू किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि सहायिकी देने वाले देश की आर्थिक गतिविधियों में कितनी विभिन्नता है साथ ही सहायिकी कितने लम्बे से दी जा रही है ।

2.2 एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी उद्यमों को दी जाने वाली सहायिकी विशिष्ट प्रकार की होगी चाहे उसे देने वाला कोई भी प्राधिकारी हो ।

---

<sup>21</sup> वही, पृष्ठ आई-1

23 कोई भी सहायिकी जो कि अनुच्छेद 3 के प्राविधानों के अतर्गत आये उसे विशिष्ट माना जायेगा।

24 इस अनुच्छेद के प्राविधानों के अतर्गत विशिष्टता के मानक निर्धारण के लिये सकारात्मक प्रमाणों को ही माना जायेगा।

## भाग II निषिद्ध सहायिकी अनुच्छेद 3 निषिद्ध सहायिकी<sup>22</sup>

31 निम्नलिखित सहायिकी जो कि अनु० 1 के अतर्गत आते हैं वे प्रतिषिद्ध हैं—

- (a) विधि या वास्तविकता में आकस्मिक सहायिकी चाहे अकेले अथवा अन्य स्थितियों, निर्यात पर और वे भी जिनका वर्णन परिशिष्ट एक में है।
- (b) आकस्मिक सहायिकी, चाहे अकेले अथवा एक या अनेक स्थितियों, आयातित वस्तुओं के ऊपर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग।

सभी हस्ताक्षरित राष्ट्र उन वस्तुओं पर न ही सहायिकी देगे ना ही रखेगे जिनका वर्णन पैरा 1 में किया गया है।

## भाग IV

### अनुच्छेद 8 गैट क्रियाशील सहायिकी को चिन्हित करना<sup>23</sup>

81 सभी हस्ताक्षरित राष्ट्र मानते हैं कि निम्न को गैटवादी सहायिकी माना जायेगा

---

<sup>22</sup> वही, पृष्ठ आई-3

<sup>23</sup> वही, पृष्ठ आई-9

- (a) उपरोक्त अनुच्छेद 2 के अतर्गत वे सहायिकी जो कि विशिष्ट नहीं है।
- (b) वे सहायिकी जो अनुच्छेद 2 के अतर्गत विशिष्ट है पर वे नीचे दिये गये पैरा 2(a) और 3(b) में वर्णित सभी शर्तें पूर्ण करते हो।

अनु० 82 समझौते के भाग III और V में दिये गए प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न सहायिकी जिन पर कार्यवाही नहीं हो सकती गैरवादी मानी जायेगी।

- (a) फर्मों द्वारा शोध कार्य में सहायता या उच्च शिक्षा या शोध संस्थापकों द्वारा सहायता अनुबन्ध के आधार पर औद्योगिक शोध में सहायता 50% से अधिक न हो या शोध में 25% राशि लगायी हो, और ऐसी सहायता सीमित हो।

(1) व्यक्तिगत धनराशि (शोधकर्ता, टेक्नीशियन और अन्य सहायक स्टाफ जो कि शोध कार्य के लिये विशेष तौर पर लगाये गये हो)।

### निर्यात की विवरणात्मक सूची<sup>24</sup> :

- (a) सरकार द्वारा किसी फर्म या उद्योग को उसके निर्यात कार्य पर सीधी सहायिकी का प्राविधान।
- (b) रोकड जमा स्कीम या अन्य इसी प्रकार के चलन जो निर्यात पर बोनस स्वरूप हो,
- (c) निर्यात पर किराया चार्ज और आंतरिक ट्रांसपोर्ट जिसे सरकारें स्वदेशी माल से अधिक लाभकारी सहायता प्रदान करे।

- (d) वे सरकारी या उसकी ऐजेन्सियों द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से दिये गए प्राविधान जो सरकारी स्कीमों द्वारा आयातित या स्वदेशी उत्पादों या सेवाओं के लिये जो निर्यात करने वाले वस्तुओं के उत्पादन के लिये हो और जो सीधे प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों या सेवा के लिये जिन्हें स्वदेशी उपयोग की वस्तुओं के लिये लिया गया हो और जिन के लिये लाभकारी शर्तें निर्यातकों को विश्व बाजार में वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध हो।
- (e) पूर्ण या आंशिक छूट, वापसी जो निर्यात सम्बन्धित हो और जिन पर सीधे कर या सामाजिक लाभ कर औद्योगिक या वाणिज्यिक सस्थानों द्वारा दिया जाये।
- (f) स्वदेशी उपयोग में दी जाने वाली छूट के ऊपर निर्यात पर विशेष कटौतियाँ जिनकी सीधे कर पर गणना की गई हो।
- (g) उन सभी वस्तुओं पर जिनका उत्पादन और वितरण स्वदेशी उपयोग के लिये होता हो और ऐसे ही उत्पाद निर्यात के लिये भी हो और उनके उत्पादन और वितरण पर छूट दी गयी हो।
- (h) उन सभी वस्तुओं पर जो निर्यात के लिये हो पर वे स्वदेश में भी बनाई और वितरित की जाती हो उनपर सम्मिलित कर में छूट या वापसी का प्राविधान। इस उपनियम का अर्थ एनेक्स में दिये गये उत्पादन प्रक्रिया के लिये प्रस्तावित मानकों के आधार पर ही होगा।

## प्रति राशिपातन उपाय :

गैट सदस्य राष्ट्रों को एन्टी-डम्पिंग उपाय लागू करने की अनुमति देता है। यह उपाय आयात पर लगाए जा सकते हैं यदि इस आयात से स्वदेशी उद्योग को हानि पहुँच रही है। टोकियो दौर में जो नियम आयातकों के शुल्कों अथवा दामों के लिये बनाए गए थे उन्हें उरुग्वे दौर में पुनः सशोधित किया गया।

विश्व व्यापार संगठन समझौता डम्प किये गए माल के लिए काफी साफ शब्दों में खुलासा करता है। डम्प किये गए उत्पाद से स्वदेशी उद्योग को जो क्षति पहुँची है उसके लिये अतिरिक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं। साथ ही एन्टी डम्पिंग अन्वेषण के लिए प्रारूप भी बताया गया है। एन्टी डम्पिंग उपायों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू करने तथा उनकी सीमा के बारे में भी इस समझौते को बताया गया है। इसके अतिरिक्त विवाद निस्तारण समितियों की भूमिका के बारे में भी टिप्पणी की गई है।

## गैट के अनुच्छेद VII को लागू करने हेतु समझौता :

### भाग I प्रति राशिपातन संहिता : अनुच्छेद I : सिद्धान्त

डकल प्रस्ताव में गैट से सम्बन्धित दिये गये प्रतिराशिपातन संहिता के कुछ सिद्धांत हैं प्रतिराशिपातन नियम गैट के अनुच्छेद VI के अंतर्गत ही लागू होंगे और निम्न प्राविधान अनु० VI पर लागू होते हैं।<sup>25</sup>

## अनुच्छेद II · राशिपातन की माप :

इस संहिता के लिये कोई भी उत्पाद डम्प तभी माना जायेगा जब उसे व्यापार हेतु दूसरे देश में उसकी सामान्य दर से कम में बेचा जाये और सामान्य व्यापार में उस उत्पाद का निर्यात मूल्य तुलनात्मक मूल्य से कम हो। स्वदेशी बाजार में यदि किसी उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही हो और ऐसी जिसकी बिक्री से तुलना नहीं की जा सकती हो तो डम्प वस्तु के मुनाफे को तुलनात्मक मूल्य से आका जायेगा।

**अनुच्छेद 9** प्रतिराशि पातन करो को लगाना एव इकट्ठा करना इसके अतर्गत निम्न बाते आती हैं<sup>26</sup> —

- 1    उन सभी स्थितियों में जहाँ कर लगाने हेतु सभी आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई हैं ऐसी स्थिति में एन्टी डम्पिंग कर लगाने का निर्णय आयात करने वाले देश के अधिकारी लगायेगे।
- 2    जब किसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रति राशिपातन कर लगाया जाता है तो उसे ठीक तरह से वसूल किया जाये और आयात की हुई उन वस्तुओं पर जो डम्प की गई हो या जो नुकसान पहुँचा रही हो उन पर बिना भेदभाव के कर लगाया जाये।

ऐसी वस्तुओं को सप्लाई करने वालों को अधिकारी चिन्हित करेंगे। यदि कई आपूर्तिकर्ता हैं और उन्हें पहचानना कठिन हो रहा है तो उस देश को ही चिन्हित किया जायेगा। यदि एक से अधिक देशों से आपूर्ति कर्ता हैं तो उन सभी के नाम लिये जायेंगे और यदि यह सम्भव नहीं है तो सभी आपूर्ति करने वाले देशों को गिना जायेगा।

3 अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि एन्टी डम्पिंग कर का मूल्य अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत वर्णित डम्प की मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये। पूर्ववर्ती तौर पर जब एन्टी डम्पिंग के मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो वह पूर्ण माना जायेगा और उसे शीघ्र से शीघ्र लागू किया जायेगा। सामान्यतः 12 माह के भीतर और किसी भी सूरत में 18 माह से अधिक नहीं। जो भी धन वापस किया जाना है उसे 90 दिनों के अन्दर ही वापस किया जाना चाहिये और यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिकारियों को उसके पीछे कारण बताना होगा।

जब एन्टी डम्पिंग शुल्क के मूल्य को आगे के लिये निर्धारित करना हो तो ऐसे प्राविधान बनाने चाहिये कि अधिक दिये गया शुल्क तुरन्त वापस हो। यह मूल्य वापसी 12 माह के भीतर ही होनी चाहिये और किसी भी सूरत में 18 माह से अधिक देर नहीं होनी चाहिये जो कि आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो। जो धन वापस करने के लिये अधिकृत किया जाये उसे 90 दिनों के अन्दर वापस करना चाहिये।

इसी अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि धन अदायगी कितनी और किस स्तर तक होगी जब निर्यात मूल्य को अनुच्छेद 23 के तहत किया गया हो तो अधिकारियों को सामान्य मूल्य में हुये किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखना होगा, आयात करने और पुन बिक्री के दरम्यान हुए मूल्य परिवर्तन और पुन बिक्री के मूल्य में हुए चलन को निर्यात मूल्य से गणना करनी चाहिये और यदि ठोस प्रमाण दिये गये हो तो किसी भी प्रकार की मूल्य कटौती एन्टी डम्पिंग शुल्क में से नहीं करनी चाहिये।

- 4 जब अधिकारियों ने अपने परीक्षण को अनुच्छेद 610 के दूसरे वाक्य के अनुसार सीमित कर लिया हो तो निर्यातको या उद्यमियों से किए गए आयात पर एन्टी डम्पिंग शुल्क जो कि लागू होगा और जिसे परीक्षण में शामिल नहीं किया गया हो उससे अधिक नहीं होना चाहिये –

(अ) चुने हुए निर्यातको या उद्यमियों के मापे गये डम्पिंग के औसत लान या

(ब) एन्टी डम्पिंग शुल्क अदायगी के दायित्व की गणना सामान्य मूल्य के आधार पर की गई हो, चुने हुए निर्यातको या उद्यमियों के मापे गये औसत सामान्य मूल्य के बीच अन्तर और उन निर्यातको या उद्यमियों जिनका व्यक्तिगत परीक्षण नहीं हुआ हो उनके निर्यात मूल्य यदि अधिकारी उक्त पैराग्राफ के लिये किसी भी शून्य एवं न्यूनतम लाभ और लाभ की अवज्ञा कर दे जिन्हे अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत प्रतिपादित किया गया हो तो



अधिकारी व्यक्तिगत शुल्क या सामान्य मूल्य उन आयातो पर लागू करेंगे जिन्हें किसी निर्यातक जैसा कि अनु० 6,10,2 में दिया गया हो।

- (5) किसी जाच के दौरान निर्यातक या उद्यमी यह सिद्ध कर देते हैं कि वे एन्टी डम्पिंग शुल्क के अंतर्गत किसी भी निर्यातक या उद्यमी से सम्बन्धित नहीं हैं तो अधिकारियों को चाहिये कि वे ऐसे व्यक्तियों के लिये शीघ्र निर्णय ले। यह निर्णय या पुनर्विचार तीव्रता से किया जाना चाहिये। जब तक यह पुनर्विचार चलता है तब तक कोई भी एन्टी डम्पिंग शुल्क आयातित वस्तुओं पर नहीं लगाया जायेगा।

## अनुच्छेद-11 एन्टी डम्पिंग शुल्क एवं मूल्यों की समयसीमा तथा पुनर्विचार

ड्राफ्ट के अनुच्छेद 11 में निम्न बातें वर्णित हैं<sup>27</sup> :

- 1 एन्टी डम्पिंग शुल्क उस समय तक लागू रहेगा जब तक डम्प की जाने वाली वस्तु से हानि होती है।
- 2 अधिकारी स्वयं अथवा किसी व्यक्ति के आग्रह पर शुल्क जारी रखने पर पुनर्विचार तभी करेंगे जब एन्टी डम्पिंग शुल्क लागू होने के पश्चात काफी समय हो चुका हो और व्यक्ति विशेष पुनर्विचार के लिये सकारात्मक सूचना

देता है। जिन पार्टियों का कोई स्वार्थ निहित हो वे पुनर्विचार के लिये आग्रह कर सकते हैं ताकि यह देखा जा सके यदि शुल्क जारी रहा अथवा हटा दिया गया तो क्या नुकसान भी होता रहेगा या समाप्त हो जायेगा। यदि हम इस पैराग्राफ के अतर्गत पुनर्विचार के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ऐन्टी डम्पिंग शुल्क की आगे आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरन्त ही समाप्त किया जायेगा।

- 3 पैराग्राफ 1 और 2 में दिये गये प्राविधानों के अतिरिक्त कोई भी ऐन्टी डम्पिंग शुल्क अपने लागू होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक के समय से पहले नहीं समाप्त होगी या सबसे नवीन पुनर्विचार की तारीख जो कि पैरा 2 के अतर्गत हो अथवा इस पैरा के अतर्गत हो। फिर भी यदि अधिकारी यह मानते हैं कि डम्प वस्तुओं द्वारा लगातार हानि हो रही है तो शुल्क लागू रखा जायेगा।
- 4 अनुच्छेद 6 में दिये प्राविधानों जो कि साक्ष्य एवं प्रक्रिया अपनाये जाने के बारे में बताता है कि वह इस अनुच्छेद के अतर्गत होने वाले किसी भी पुनर्विचार पर भी लागू होगा। इस तरह का कोई भी पुनर्विचार शीघ्रता से निबटाया जायेगा और 12 माह के अतर्गत उसे समाप्त किया जायेगा।
- 4.5 इस अनुच्छेद के प्राविधान जरूरी परिवर्तनों के साथ अनु० 8 में निहित मूल प्राविधानों पर भी लागू होगा।

## डम्पिंग के विरुद्ध कार्यवाही – प्रक्रिया एवं नियम :

अनु० VI, 1994 गैट के अतर्गत सदस्यों को एण्टी-डम्पिंग उपाय लागू करने की छूट दी गई है। ऐसे उपाय उन आयातित उत्पादों पर लगाये जा सकते हैं जिनका निर्यात मूल्य "सामान्य दर" से कम हो और यदि ये स्वदेशी उद्योग को नुकसान पहुँचाते हों। ऐसे उपायों को टोकियो दौर में विस्तृत चर्चा की गई और इसका उरुग्वे दौर में पुनर्मूल्यांकन किया गया।

जहाँ स्वदेशी बाजार से मूल्यों की सीधी तुलना संभव नहीं है वहाँ के लिये विश्व व्यापार संगठन समझौता डम्प किये गये उत्पाद के लिये नियम बताता है। डम्प वस्तु द्वारा स्वदेशी उद्योग को हानि होने पर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी और किस तरह से एण्टी डम्पिंग जाच की जाये यह भी बताया गया है। नियमों के अनुपालन की प्रक्रिया तथा एण्टी डम्पिंग उपायों की अवधि भी इस समझौते के हिस्से हैं। साथ ही विवाद निस्तारण प्रक्रिया पर भी यह प्रकाश डालता है।

इस समझौते के अतर्गत आयात करने वाले देश को साफ तौर पर सिद्ध करना होगा कि डम्प वस्तुओं द्वारा किस प्रकार से स्वदेशी उद्योग को हानि पहुँच रही है। इसके लिये सभी आर्थिक कारणों की परख होनी चाहिये जिसके द्वारा उक्त उद्योग को डम्प वस्तु से नुकसान हो रहा हो। कैसे एण्टी-डम्पिंग केसों को दायर किया जाय, किस प्रकार से उसकी जाच हो तथा सभी संबंधित पक्षकारों का साक्ष्य देने का समय

दिया जाये इन सभी प्रक्रियो पर साफ तौर पर प्रकाश डाला गया है। जिस तारीख से एण्टी डम्पिंग उपाय लागू हुए हैं तब से पाच वर्ष तक ये लागू रहेगे।

यदि जाच अधिकारी यह पाते हैं कि डम्पिंग का मारजिन 2% से कम हो तो ऐसी जाच तुरन्त बद कर दी जाये या डम्प आयातित वस्तु का कुल मान लगभग नगण्य हो तो भी जाच समाप्त कर दी जायेगी।

सभी आरम्भिक तथा अतिम कार्यवाही की पूर्ण जानकारी प्रतिराशि पातन व्यवहार समिति को देना अनिवार्य है। इस समझौते से सबधित किसी भी मुद्दे को लागू करने के लिये सभी सदस्यो को पूरा अवसर दिया जायेगा।

## सहायिकी पर सीमा और काउन्टरवेलिंग उपाय :

सहायिकी और काउन्टरवेलिंग उपाय (Subsidies And Counter Vailing Measures) पर समझौता गैट के VI, XVI, और XXIII के मायने तथा उनके अनुपालन की प्रकिया को बतलाता है जिस पर टोकियो दौर मे वार्ता हुई थी। इसमे सहायिकी की परिभाषा दी गई है और ये विशिष्ट सहायिकी के बारे मे व्यख्या की गई है।

जो समझौता गैर कृषि उत्पादो पर लागू होता है वह तीन प्रकार की सहायिकी के बारे मे बताता है — वे जो प्रतिबधित हैं, वे जिन पर कार्यवाही हो सकती है और वे जिन पर कार्यवाही नहीं हो सकती है।

सामान्यतः प्रतिबधित सहायिकी वे हैं जिनको निर्यात के आधार पर दिया जाये या फिर विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर आधारित हो। ये सहायिकी विवाद निस्तारण प्रक्रिया के तहत आती है। यदि पाया जाता है कि सहायिकी वास्तव में प्रतिबधित है तो उसे तुरन्त वापस ले लिया जाता है।

कार्यवाही वाली सहायिकी के तहत यह माना गया है कि विश्व व्यापार संगठन के किसी भी सदस्य को सहायिकी के उपयोग से दूसरे सदस्यों के हितों की हानि नहीं करनी चाहिए। जो सदस्य इस सहायिकी से हानि उठाते हैं वे विवाद निस्तारण समिति के समक्ष यह मुद्दा रख सकते हैं। यदि यह पाया जाता है कि इसके द्वारा कुप्रभाव पड़ रहे हैं तो उसे तुरन्त वापस लिया जाना चाहिये।

इस समझौते के तहत क्षतिपूर्ति के उपायो काउन्टरवेलिंग उपाय का प्राविधान भी है। यह ऐसे नियमों का प्राविधान है जो सभी पक्ष सूचना और जानकारी दे सकते हैं और अपने तर्क रख सकते हैं। स्वदेशी उद्योग को हुए नुकसान के आधार पर सहायिकी का मूल्यांकन किया जाता है। सभी क्षतिपूर्ति शुल्क लागू होने के पांच साल बाद समाप्त कर दिये जाते हैं यदि अधिकारी यह दिखा दे कि इसके उपरांत भी हानि होती रहेगी तो ये जारी रखा जा सकता है।

विकासशील देशों में सहायिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और केन्द्रशासित अर्थ व्यवस्थाओं को बाजार व्यवस्था में परिवर्तन में सहायक हो सकती

है। अल्प विकसित देश और वे देश जिनकी सकल प्रति व्यक्ति उत्पाद 1000 डालर से कम है उन्हें प्रतिबन्धित सहायिकी से प्रतिबन्धित सहायिकी पर समय बन्धित छूट प्रदान की गई है। अन्य विकासशील देशों के लिए निर्यात सहायिकी प्रतिबन्ध सन् 2003 से लागू होगा। यदि सहायिकी का पूर्ण स्तर 2% से अधिक नहीं होता है तो विकासशील देशों के यहाँ क्षतिपूर्ति जाच समाप्त कर दी जायेगी। परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं के यहाँ प्रतिबन्धित सहायिकी सन् 2002 तक हटा दी जायेगी।

### **निवेश उपाय— व्यापारिक खामियों को कम करना :**

यह समझौता वस्तुओं के व्यापार पर निवेश उपायों पर ही लागू होता है। यह मानता है कि कुछ निवेश उपाय ट्रिम्स व्यापार को खराब और प्रतिबन्धित कर सकते हैं। कोई भी सदस्य गैट के अनु० III और XI के विपरीत किसी भी प्रकार का ट्रिम्स नहीं लगा सकता है। इसके लिये ऐसी एक सूची इस समझौते के साथ ही जोड़ी गयी है।

सभी प्रकार के ट्रिम्स विकसित राष्ट्रों द्वारा 2 वर्षों में विकासशील देशों द्वारा 5 वर्षों के भीतर और अल्पविकसित देशों द्वारा 7 वर्षों के भीतर समाप्त कर दिये जायेंगे। इसके लिये एक निरीक्षण समिति गठित की जायेगी। इस पर विचार के लिये 1 जनवरी 2000 निश्चित की गई है।

## समन्वित विवाद निस्तारण प्रक्रिया के तत्त्व<sup>28</sup>

### विवाद निस्तारण समिति :—

- 1 इसमें आपसी समझौते के सदस्य इस बात के लिये सहमत हैं कि समझौते के सभी नियम व प्रक्रिया उन सभी विवादों पर लागू होगी जो स्वीकार पत्र के एनेक्सर 1 में दिये गये हैं और ये सब कोई भी विशेष या अतिरिक्त प्राविधान विवाद निस्तारण का जो इस समझौते में रखे गये हैं, उनके अधीन हों।
- 2 सदस्य इसके साथ ही एक विवाद निस्तारण समिति का गठन करते हैं जिसके पास सामान्य परिषद है और परिषद तथा समितियों की शक्ति होगी कि वह उन सभी विवादों के निस्तारण के लिये जो इस सामान्य समझौते के तहत आते हैं, इस समझौते के नियम व प्रक्रिया के अतर्गत सुलझाये। इसके पास इसका भी अधिकार होगा कि वह पैनलों का गठन करे पैनल समिति के रिपोर्ट को माने नज़ीरो और सस्तुतियों को लागू करने के लिये निरीक्षण करे, तथा इस सहमति पत्र के अतर्गत आने वाली छूट एवं अन्य कर्तव्यों को निरस्त कर सके।
- 3 इस विवाद निस्तारण समिति की सदस्यता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिये खुली है। विवाद निस्तारण में जो भी प्रगति होगी उसकी परिषदों एवं समितियों को पूरी सूचना दी जायेगी।

- 4 जहाँ इस समझौते के तहत यह दिया गया है कि नियम और प्रक्रिया के अतर्गत विवाद निस्तारण समिति कोई निर्णय ले सकती है तो वह ऐसा एकमत होकर ही ऐसा कर सकती है।
- 5 विवाद निस्तारण समिति इस समझौते में दी गई प्रक्रिया को ही मानेगी परन्तु जहाँ विशेष या अतिरिक्त प्रक्रिया बताई गयी हो वहाँ उसे माना जायेगा। ऐसे विशेष एवं अतिरिक्त प्रक्रिया डकल प्रस्ताव के परिशिष्ट में बतायी गई है। जहाँ विवाद में एक से अधिक प्राविधान लागू हो रहे हों और जहाँ विशेष या अतिरिक्त प्रक्रिया में विवाद हो तथा विवादित पार्टियाँ पैनल गठन के 20 दिनों के अंदर प्रक्रिया अपनाये जाने पर सहमत नहीं हो तो विवाद निस्तारण समिति का अध्यक्ष सभी विवादित पार्टियों से विचार विमर्श के बाद 10 दिनों के भीतर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर निर्णय लेगा। अध्यक्ष इस तथ्य को मानेगा कि जहाँ संभव हो वहाँ विशेष एवं अतिरिक्त प्रक्रिया ही मानी जाये और इस समझौते में वर्णित प्रक्रिया विवाद को समाप्त करने के लिये उपयोग किया जाये।

## पैनल की संदर्भित शर्तें :

### पैनल निम्न शर्तें एवं सदस्य मानेंगे :

- 1 यदि विवादित पार्टियाँ 20 दिनों के भीतर किसी अन्य पर सहमति नहीं बतलाती है। "विवादित पार्टियों द्वारा घोषित समझौते संबंधित प्राविधान की



रोशनी में निरीक्षण किया जायेगा कि विवादित मुद्दा जो समिति के समक्ष रखा गया है उसे पार्टी के नाम में दस्तावेज है।

- 2 विवादित पार्टियों द्वारा घोषित आवश्यक प्रविधानों को पैनल अपने ध्यान में रखेगा।

## विवाद निस्तारण पर अनुसचिवीय निर्णय<sup>29</sup>

अनुसचिवों के निर्णय के अनुसार नीचे दिये गए निर्णय को 'गैट्स' अपनी प्रथम बैठक में अपनायेगा।

### विवाद निस्तारण पैनल :

समझौते के खास दायित्वों एवं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए तथा सेवा में व्यापार संबंधित अनुच्छेद XXII एवं XXIII के अंतर्गत विवाद निस्तारण के लिये निम्न निर्णय लिए गए हैं

- 1 पैनल के चुनाव में सहायता हेतु पैनलिस्टों के एक रोलर का गठन।
- 2 इसके लिये पक्षों, उन पक्षों एवं व्यक्तियों का नाम सुझायेगी जो नीचे दिये गए पैरा-3 के अनुसार सभी अहर्ताएँ पूरी करते हों और इसके साथ ही ऐसे

व्यक्तियों की योग्यताओं के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता के बारे में जानकारी भी दी जायेगी।

- 3      पैनल में ऐसे लोग रखे जाये जो पूरी तरह से योग्य हो वे सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें गैट्स या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवा से संबंधित अनुभव प्राप्त हो। ये सभी व्यक्ति जो पैनल में शामिल होंगे वे व्यक्तिगत तौर पर कार्य करेंगे न कि किसी सरकार या संगठन के प्रतिनिधि के रूप में।
- 4      खास मुद्दों के विवादों के लिये जो पैनल गठित होंगे वे जरूरी योग्यताओं और बातों से पूर्ण होंगे।
- 5      रोस्टर सचिवालय के अधीन कार्य करेगा और उसके प्रशासन के लिये निर्णय अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करके लिया जायेगा।

### **डंकल प्रस्ताव में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां एवं परिभाषाएं:**

डंकल प्रस्ताव के अनुच्छेद XXXIV में कुछ परिभाषाएँ दी गयी हैं<sup>30</sup> —

- (क) “परिभाषा” का अर्थ है किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी नियम कानून प्रक्रिया निर्णय प्रशासनिक कार्य या अन्य कोई तरीके को इस्तेमाल में लाना।

- (ख) "सेवा प्रदान करने" के अतरगत सेवा का उत्पादन वितरण बिक्री, खरीददारी आती है।
- (ग) पार्टियों द्वारा व्यापार में सेवा का अर्थ है वे सभी उपाय जो कि –
- (i) खरीद, देनदारी या सेवा के इस्तेमाल।
  - (ii) सेवा देने के लिये प्रवेश और इस्तेमाल में।
  - 1 वितरण एवं परिवहन व्यवस्था।
  - 2 पब्लिक टेलीकम्यूनिकेशन्स परिवहन नेटवर्क एवं सेवा।
  - (iii) उपस्थिति, जिसमें वाणिज्यिक उपस्थिति निहित है जहाँ एक पार्टी दूसरे क्षेत्र में लोगों को सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करता है।
- (घ) "वाणिज्यिक उपस्थिति" का मतलब है व्यापार या व्यवसायिक प्रतिस्थापन जिसके अतर्गत –
- (i) न्यायिक व्यक्ति की स्थापना, अपनाना या ध्यान रखना है, या
  - (ii) किसी भी ब्रांच या प्रतिनिध कार्यालय के निर्माण एवं पोषण निहित है।
- (च) "सेवा प्रदान करने" वाले का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे किसी पार्टी ने सेवा के लिये दिया हो,
- (छ) "सेवा लेनेवाले" का अर्थ वह व्यक्ति जो किसी भी पार्टी द्वारा सेवा लेता हो।
- (ज) "व्यक्ति" का अभिप्राय है प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति,

(झ) "प्राकृतिक व्यक्ति" किसी भी पार्टी का हो उससे अभिप्राय है —

(1) एक प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी पार्टी में नियमित उस देश का वासी हो, या।

(11) जिन पार्टियों में कोई भी देशवासी नहीं होते हैं वहां पार्टी के नियमों के अन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्ति के पक्के तौर पर रहने का अधिकार प्राप्त है, और जो उस पार्टी या अन्य पार्टी के क्षेत्र में रहता है

(ग) अन्य पार्टी का "न्यायिक व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी निगम, साझेदारी, संयुक्त उपक्रम सम्पूर्ण स्वामित्व एवं समूह जो कि लाभ या अन्य किसी प्रयोजन के लिये गठित किये गए हो और जो कि निजी या सरकारी तरीके के हो, जो कि

(1) पार्टी के नियमों के तहत गठित हो और जो उस पार्टी के क्षेत्र में या अन्य पार्टी के क्षेत्र में व्यापार में सलग्न हो। या

(11) जिसका नियंत्रण या स्वामित्व।

(1) उस पार्टी के प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा हो, या

(2) उस पार्टी के न्यायिक व्यक्तियों जिनका पैरा (1) के अन्तर्गत विवरण है।

(त) न्यायिक व्यक्ति का मतलब है —

(i) यदि 50% प्रतिशत से अधिक का हिस्सा उस पार्टी के व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिये हो तो वे व्यक्ति उस पार्टी के मालिक होंगे।

(ii) "नियंत्रण" का अर्थ है यदि पार्टी के व्यक्तियों के पास अधिकांश निर्देशकों की नियुक्ति करने की शक्ति हो या वे कानूनी तौर पर पार्टी के क्रियाकलापों को दिशा देते हों,

(iii) अन्य व्यक्ति से जुड़ने का अर्थ है यदि वह व्यक्ति उसे नियंत्रण करता हो या वह और अन्य व्यक्ति दोनों ही उसी व्यक्ति के नियंत्रण में हों।

## **डंकल प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया : भारतीय संदर्भ में:**

डंकल प्रस्ताव पर लगातार मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती रही है। जिनमें कुछ तो सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू की ओर संकेत करती हैं। जिनको इस शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

## **प्रतिक्रिया :**

डंकल प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है तथा अप्रैल 1994 इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है यह दस्तावेज बहुत ही विस्तृत और विवादास्पद है परन्तु हमारे देश में इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। दुर्भाग्य से 400 पृष्ठों वाला यह दस्तावेज कुछ 'सौभाग्यशाली' शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को ही उपलब्ध

है। कृषक समुदाय को इसके विषय में कुछ नेताओं के भाषणों से ही जानकारी उपलब्ध है।

भारत सभी वार्ता चक्रों में शामिल रहा है और अपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से ही सभी पूर्व समझौतों में विशेष दर्जा प्राप्त करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सदस्य देशों के बीच आठवें दौर की वार्ता के कुछ अनुच्छेदों पर गहरे मतभेद रहे हैं फिर भी कोई राष्ट्र इस वार्ता से वंचित नहीं रह सकता है क्योंकि गैट राष्ट्रों के विश्व व्यापार के लगभग 90% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। आठवें दौर की वार्ता के सफल होने से विश्व बैंक तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने अनुमान लगाया है कि विश्व व्यापी मुनाफे में डालर 217 230 में बिलियन की बढ़ोत्तरी होगी। इस बढ़ते व्यापार में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के हिस्से में 46 बिलियन डालर की बढ़ोत्तरी होगी।

भारत में गैट का विरोध आर्थिक कारणों से कम बल्कि बदलाव प्रक्रिया में शामिल न होना ही अधिक है। पूर्व गैट वार्ताओं में विकासशील देशों को विशेष सहूलियतें प्रदान की जाती थी। उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे विकसित राष्ट्रों द्वारा प्रदान की जानी वाली मदद के बदले कुछ दें। यह भी जरूरी नहीं था कि विकासशील देश अपने बाजार बड़े राष्ट्रों के लिये खोले। आठवें चक्र में भी विकासशील देशों को कुछ पृथक् प्रतिबन्धों की छूट दी गई है। किन्तु हम इन छूटों से

संतुष्ट नहीं है। अभी तक भारत को विश्व समुदाय से विशेष सहूलियते मिलती रही है क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं। हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा का भी कोई अनुभव नहीं रहा है।

पिछले 50 वर्षों में भारत सरक्षित बच्चे की तरह बड़ा हुआ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं मित्र राष्ट्रों से हमेशा उदार ऋण एवं अनुदान मिलते रहे हैं। और हम विकास के लिये पर्याप्त ससाधनों को जुटाने में असफल रहे हैं। जिसके कारण प्रति व्यक्ति ऋण 3000 रुपये का हो गया है। हमने सोना बंधक रखकर अपनी इज्जत बचाई। अब हमारे सामने यह चिन्ता है कि हम किस प्रकार से सरक्षण के दायरे से बाहर आये यह बड़ी बिडम्बना की बात है कि हम विश्व में एक बड़ी अर्थ शक्ति के रूप में उभरना भी चाहते हैं और साथ ही विश्व समुदाय से विशेष दर्जा एवं सहूलियते भी प्राप्त करते रहना चाहते हैं।

यदि हमें अपने कृषि उत्पादन में तेजी लानी है तो हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। यथा 1 विनियोग स्तर में बढ़ोत्तरी 2 भूधारण अधिकार विवादों का निष्पादन 3 ऋण उपलब्धता में बढ़ोत्तरी 4 सही मूल्य नीतियों की स्थापना 5 उत्पादन बढ़ाने के लिये नई तकनीकों को अपनाना 6 सरकारी छूट 7 कृषि में बढ़ोत्तरी के लिये प्रशुल्क नीतियाँ।

ऐसी मूल्य नीतियां बनाई जानी चाहिये जो कि किसानों को सही प्रतिफल दे सकें। यह सही है कि एक सीमा तक ही सरकारी छूट को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है। इस संबंध में यह बताना जरूरी है कि जो उच्च दर्जे का संरक्षण पहले उद्योग को दिया गया था उसी तरह का संरक्षण कृषि को भी देना होगा। आज जो असंतुलन है उसे हम ठीक कर सकते हैं यदि हम उद्योगों की दिये जाने वाले संरक्षण में कमी लायें और कृषि उत्पादों विशेषकर निर्मित कृषि उत्पादन को निर्यात का प्रश्रय दें आज कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं न केवल किसानों के हितों के लिये बल्कि बकाया धन अदायगी को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत सरकार ने 1993-94 में 3000 करोड़ रूपयों की खाद्यान्न एवं उर्वरक आर्थिक सहायता प्रदान की। 1990-91 में कृषि उत्पादन 176.40 मिलियन टन था जो कि 1992-97 में बढ़कर 196.20 मिलियन टन हो गया। यद्यपि यह उन्नति का सूचक है फिर भी यह विश्व व्यापी आर्थिक विकास की तुलना में काफी कम है।

उदारीकरण के अंतर्गत यह भी जरूरी है कि देश के आंतरिक बाजार की जरूरतों पर कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी अवरोध के आने जाने दिया जाये। घरेलू सरकारी सहायता पर कटौती हेतु डकल प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रत्येक सरकार को (Aggregate Measure of Support) ए०एम०एस० की गणना करना होगा। आर्थिक सहायता को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है —



गैर उत्पाद विशिष्ट एन०पी०एस० (Non Product Specific) और उत्पाद विशिष्ट एन०पी०एस० (Non Product Specific) के अतर्गत पानी (सिचाई), बिजली, खाद/उर्वरक, बीज, ऋण कीटनाशक आदि तथा सभी प्रकार की फसले न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अन्य प्रति फसल आर्थिक सहायता को पी०एस० की श्रेणी में रखा गया है। 22 प्रकार के कृषि उत्पादों— गेहूँ, धान, गन्ना, दाल, खद्यान तेल, आदि पी०एस० के अतर्गत आते हैं जिन पर भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। पी०एस० क्षेत्र में ए०एम०एस० की बहुत से उत्पादों में नकारात्मक गणना की गई है और एक या दो उत्पादों पर सकारात्मक किन्तु 10% से कम आकी गई है यह भी संभव है कि यदि इन उत्पादों पर छूट दी गई तो ये 10% से अधिक हो जायेंगे। भारत की घरेलू समर्थन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाए रखने के लिये अतिरिक्त लोचपन की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में कई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जैसे क्या गैट 1994 के लागू हो जाने के पश्चात् विश्व व्यापार व्यवस्था और भी मुक्त एवं सुदृढ़ हो जायेगा? क्या अब विश्व में न्यायोचित व्यापार व्यवस्था होगी, जिसमें कमजोर राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा? क्या नई व्यवस्था अमरीका और अन्य आर्थिक शक्तियों के एकाधिकार को समाप्त कर सकेगी? विश्व में टेक्नोलॉजी बाजार में और विकासशील देशों में तकनीक वृद्धि पर क्या असर होगा? उत्तर संभव नहीं है।

अप्रैल 1994 तक लगभग सभी देशो ने गैट 1994 का अनुमोदन दिया है और इसकी सस्थागत इकाई विश्व व्यापार सगठन जुलाई 1995 से इसका स्थान ले लिया है। गैट 1994 के बाद से निम्न सभावनाए व्यक्त की गयी है यथा –

- 1 सभी देश आज से अधिक बेहतर स्थिति मे होंगे।
- 2 कुछ राष्ट्र अन्य से मजबूत स्थिति मे होंगे।
- 3 कुछ देशो की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी या
- 4 सभी देश खराब स्थिति मे होंगे।

अतिम परिणाम (2) और (3) परिदृष्यो के मध्य कही स्थित होगा। यदि आज की खराब स्थिति वाले देश बेहतर स्थिति मे नही पहुँच जाते है तो स्थिति और बिगड सकती है सभी सूचक इस बात की ओर इगित करते है कि अतिम परिणाम कुछ मिले जुले असर वाले होंगे।

यह अनुमान किया जाता है कि वस्तुओ का व्यापार और उदार होगा परन्तु इसकी सापेक्षिक लाभ या हानि के बारे मे तभी पता चलेगा जब विभिन्न देशो की उदारीकरण प्रक्रिया चालू होगी। उपलब्ध आर्थिक टिप्पणियो के अनुसार आगामी दस वर्षो मे गैट 1994 के लागू हो जाने के बाद विश्व व्यापार मे लगभग 200 बिलियन डालर तक की वृद्धि होगी। इसमे भारत तथा अन्य देशो की कितनी भागीदारी होगी इसकी परिकल्पना करना सभव नही है।

टोकियो दौर की गैट वार्ता के बाद 'बेला बेलासा' द्वारा बताये गए तुलनात्मक परिणामों के बारे में हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। सभी नीतियों की जांच के बाद उन्होंने पाया कि विकसित राष्ट्रों में सुरक्षा की दरों में वृद्धि उन क्षेत्रों में हुई है जिन पर टैरिफ में टोकियो दौर के बाद कटौती की गई है और जो कि विकासशील देशों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसकी वजह से विदेशी प्रदायक को स्वदेशी प्रदायक की तुलना में बाजार में प्रवेश में विशेष लाभ की संभावना नहीं है। इस व्यापार खेल में स्वदेशी प्रदायक का पलड़ा ही भारी है। अतः गैट 1994 के परिणामों के लिये हमें अभी 2004 तक और इन्तजार करना होगा जिसका सेवा क्षेत्र, वस्त्र, कृषि, ट्रिप्स और ट्रिप्स समझौते पर व्यापक असर पड़ेगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रशासन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आपसी संबंध होना स्वाभाविक है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार को बहुराष्ट्रीय निगम अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ओ एल आई (स्वामित्व स्थान निर्धारण एवं अन्तर्राष्ट्रीयवाद) ढांचे में है। बहुराष्ट्रीय निगम उत्पादन क्रिया को अपनी सुविधानुसार अपने देश में या बाहरी क्षेत्रों में करना चाहेंगे क्या अपने पेटेंटों के लिए एम एन सी एस अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करना चाहेंगे और इसके बदले में रायल्टी लेना चाहेंगे? वे विभिन्न देशों में अपने अपने क्षेत्र सुरक्षित करके फर्मों के लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकार को रजिस्टर्ड करालेंगे जिससे भौगोलिक प्रतिस्पर्धा घटे जो आई पी आर प्रशासन फाइनल एक्ट में प्रस्तावित है उसमें एम एन सी एस को सभी तरह की

अपनी इच्छाओं के लिए विकल्प मौजूद है। ट्रिप्स समझौते के प्रस्तावना में साफ तौर पर स्वीकारा गया है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार निजी अधिकार हैं। इसमें राष्ट्रीय व्यवहार और परममित्र राष्ट्र (एम एफ एन) व्यवहार के प्राविधान हैं। औषधियों और कृषि केमिकल के लिए पांच वर्षीय सम्पूर्ण बाजार अधिकार का प्राविधान है। यहाँ तक कि वे देश जैसे कि भारत जहाँ उत्पाद पेटेन्ट प्रशासन नहीं है उन्हें दस वर्षों का समय दिया गया है ताकि वे अपने यहाँ नए प्रशासन को लागू कर सकें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्राविधान हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय विपदा के समय या गैर वाणिज्य इस्तेमाल के लिये अधिकार धारक की स्वीकृत के बिना ही पेटेन्टों का उपयोग किया जा सकता है। इस अपवाद के अंतर्गत पेटेन्ट अधिकार धारक को बाद में ठीक तरह से उसका पर्याप्त प्रतिफल चुकाना पड़ेगा। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय विपदा, गैर वाणिज्य उपयोग पर्याप्त प्रतिफल आदि का क्या अर्थ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिप्स में पेटेन्ट धारकों के अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया गया है और उनके कर्तव्यों पर कम विवाद निपटारा सहमति के प्राविधानों के अंतर्गत सेवा और वस्तु के प्रतिकार पर किसी भी प्रकार के निलम्बन या छूट की वापसी की जा सकती है और यह यू०एस० व्यापार अधिनियम की धाराएँ 301, सुपर 301 या स्पेशल 301 का ही प्रतिरूप हैं।

## અધ્યાય : 6

*વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન*

## स्थापना:

विश्व व्यापार संगठन (W T O) की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। 15 दिसम्बर 1993 को उरुग्वे दौर की वार्ता सम्पन्न हुई और विश्व के विभिन्न देशों के मंत्रियों ने अप्रैल 1994 में मराक्केश, मोराक्को में हस्ताक्षर करके इस राजनैतिक संरक्षण प्रदान किया। 15 अप्रैल 1994 को हुए मराक्केश घोषणा के अनुसार उरुग्वे दौर के नतीजों से विश्व अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और इसकी वजह से अधिक व्यापार, निवेश रोजगार तथा आय स्रोत में विश्वव्यापी वृद्धि होगी। विश्व व्यापार संगठन उरुग्वे दौर की वार्ता का नतीजा है और गैट का उत्तराधिकारी भी है। उरुग्वे दौर के दौरान लिये गये निर्णय व उसके परिणाम को लागू करने के लिये विश्व व्यापार संगठन को आवश्यक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया जो सस्थागत ढाँचा है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अनुच्छेद (2) और प्रस्तावना में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से सम्बन्धित समझौते में भारत इसके स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक है। इसकी सदस्यता से भारत को क्या लाभ होगा इसकी चर्चा हम प्रभाव वाले अध्याय में करेंगे।

## विश्व व्यापार संगठन के कार्य एवं सिद्धान्त

विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय जेनेवा, स्वीटजरलैंड में स्थित है इसके निम्न कार्य हैं —

- 1 बहुपक्षीय एव बहुउद्देश्यीय व्यापारिक समझौते को प्रभावित एव परिचालित करना ।
- 2 बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना ।
- 3 व्यापार विवादों का निस्तारण करना ।
- 4 राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देख-रेख करना ।
- 5 विश्व की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जो विश्व आर्थिक नीतियों का बनाती हैं उनके साथ मिलकर कार्य में सहयोग करना ।

विश्व व्यापार संगठन जैसा कि अनुच्छेद 3 में परिभाषित है उसका एक कार्य यह भी है कि (आर्थिक नीति निर्णय में विश्व स्तर पर अधिकतर सौहार्द कायम करना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक तथा इससे सम्बद्ध अभिकरणों के साथ सहयोग कायम करना है) विश्व आर्थिक नीति निर्णयन में अधिकतर सौहार्द कायम करने के सम्बन्ध में मराक्केस समिति ने एक विस्तृत उद्घोषणा की। परन्तु विश्व आर्थिक नीति निर्णयन वर्तमान सन्दर्भ में दुर्भाग्य से इसके परिणाम विश्व बैंक एवम् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुकूल नहीं थे ।

### **व्यापार प्रणाली के सिद्धान्त :**

विश्व व्यापार संगठन समझौते के अर्न्तगत 21 विधिक अध्याय हैं जिनके अर्न्तगत कृषि एव वस्त्र, सेवा एव सरकारी खरीद तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार

समिलित है। इसके अतिरिक्त 25 और अनुसचवीय घोषणा/निर्णय तथा समझौते की भी चर्चा की गयी है।

## भेद—भाव रहित व्यापार

पूर्व गैट और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य भेद—भाव रहित व्यापार की स्थापना है। लगभग 50 वर्षों तक गैट के प्राविधान भेद—भाव को मिटाने में लगे थे। साथ ही सदस्य देशों के निर्यात एवं स्वदेशी उत्पादों में भेद—भाव को दूर करने के उद्देश्य से कार्यरत थे। अनुच्छेद (1) के अनुसार अति मित्र राष्ट्र (M F N) के उपनियम के अन्तर्गत सदस्य देश इस बात के लिए बाधित थे कि वे अन्य सदस्य देशों के उत्पादों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वे विश्व के किसी अन्य देश के उत्पाद के साथ करते हैं। दूसरे तरीके के अन्तर्गत जिसे राष्ट्रीय नीति कहते हैं यह जरूरी है कि एक बार उत्पाद बाजार में आ जाय तो उन्हें स्वदेशी उत्पादों के समरूप ही मानना होगा। यह गैट का अनुच्छेद (3) है। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन समझौते में बहुत से ऐसे प्राविधान हैं जो कि परम मित्र राष्ट्र तथा राष्ट्रीय व्यवहार नीति से सम्बन्धित हैं सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता गैट के अन्तर्गत सदस्यों के अन्य सदस्यों की सेवाओं के लिए परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार करना होगा।

सशोधित गैट (जिसे गैट 1994 कहते हैं) के अतिरिक्त कई अन्य विश्व व्यापार संगठन के समझौते परमित्र राष्ट्र और राष्ट्रीय उपचार से सबधित प्राविधान रखते हैं



कुछ अपवादों को छोड़कर ट्रिप्स में विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित परम मित्र राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार गैट्स की आवश्यकताओं का प्राविधान भी है। गैट्स के अंतर्गत सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अन्य सदस्यों की सेवाओं और सेवा प्रदायियों को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करें। परन्तु इसमें कुछ छूट भी प्रदान की गई है जिसके लिये शुरुवात में सदस्य ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं है। जहाँ ऐसी छूट दी गयी है उसपर पांच वर्ष बाद पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा और किसी भी सूरत में उसे 10 वर्षों से अधिक नहीं रखा जायेगा। सक्रिय व्यवहार गैट्स के अन्तर्गत ही आता है जिसे सदस्य खास तौर पर सेवा या कार्य हेतु बनाते हैं। इसका अर्थ है कि सक्रिय व्यवहार सदस्यों के आपसी बात चीत का परिणाम है।

विश्व व्यापार संगठन समझौते के अन्य भेद भाव प्राविधानों के अन्तर्गत—आरम्भ (Origin) के नियम, माल लादने के पूर्व की जाच, व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय, और सिनेटरी एव फाइटो सेनेटरी उपाय।

गैट/विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक है, जो कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा। सभी देश जिनमें गरीब भी सम्मिलित हैं उनके पास मानव, उद्योग, प्राकृतिक सम्पदा तथा आर्थिक सम्पत्ति होती है जिसे वे वस्तु उत्पादन में तथा स्वदेशी बाजार के लिए सेवा में लगा सकते हैं। तुलनात्मक लाभ का अर्थ है कि देश अपने यहां की सम्पत्ति को पूर्ण लाभ हेतु सबसे अच्छे उत्पादन के लिये लगा सकते हैं। बड़े बाजार, स्वदेशी तथा विदेशी इन देशों को लाभ पहुंचाने में सहायक

होगे। व्यापार की उदार नीतिया वस्तुओं के आदान-प्रदान में कोई भी रुकावट नहीं आने देती है तथा सेवा के लिये विस्तृत व्यापार पेश करती है।

## विश्व व्यापार संगठन तथा गैट:

सामान्य आवधारणा के विपरीत विश्व व्यापार संगठन मुक्त व्यापार सस्था नहीं है। इसके अन्तर्गत सीमित दायरे में ही प्रशुल्क एवं अन्य तरीके के सरक्षण का प्राविधान है। यह नियमों की वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत खुला साफ तथा बिना बिगड़े हुए प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था है। न केवल विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता गैट से अधिक है (128 देश 1994 के अंत में), बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी इसका दायरा बहुत विस्तृत है। जहाँ गैट केवल व्यापारिक वस्तुओं पर ही लागू होता था वहीं विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं का यथा व्यापार, सेवाएँ तथा “विचारों के व्यापार” या बौद्धिक सम्पदा भी आते हैं।

गैट/विश्व व्यापार संगठन का सीधा विस्तार नहीं है बल्कि पूरी तरह से यह बदला हुआ स्वरूप है। गैट तथा विश्व व्यापार संगठन में मुख्य अंतर इस प्रकार है

- 1 गैट कोई स्थायी सस्था नहीं है यह केवल एक नियमों का जत्था है, एक बहुराष्ट्रीय समझौता है। इसकी उत्पत्ति 1940 के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सस्था पर आधारित थी, जबकि विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी सस्था है जिसका अपना सचिवालय है।

- 2 गैट को गैर स्थायी रूप में स्थापित किया गया था। यद्यपि 40 वर्ष बाद सरकारें इसे स्थाई रूप में लेती हैं। विश्व व्यापार संगठन की वचनबद्धता पूर्ण तथा स्थाई है।
- 3 गैट के नियम व्यापारिक वस्तुओं पर लागू थे जबकि विश्व व्यापार संगठन इसके अतिरिक्त सेवा तथा बौद्धिक सम्पदा के व्यापार सम्बन्धित क्षेत्रों पर लागू होता है।
- 4 यद्यपि गैट बहुराष्ट्रीय व्यवस्था की ओर 1980 आते-आते इसमें अनेक नवीन समझौते जोड़ दिये गये इसके विपरीत विश्व व्यापार संगठन के समस्त समझौते बहुपक्षीय हैं और ये सभी सदस्यों पर लागू होते हैं।
- 5 विश्व व्यापार संगठन की विवाद निस्तारण व्यवस्था अधिक तीव्र तथा स्वचालित होने की वृत्ति से इसमें व्यवधान कम उत्पन्न होते हैं जबकि गैट में ऐसा नहीं था।

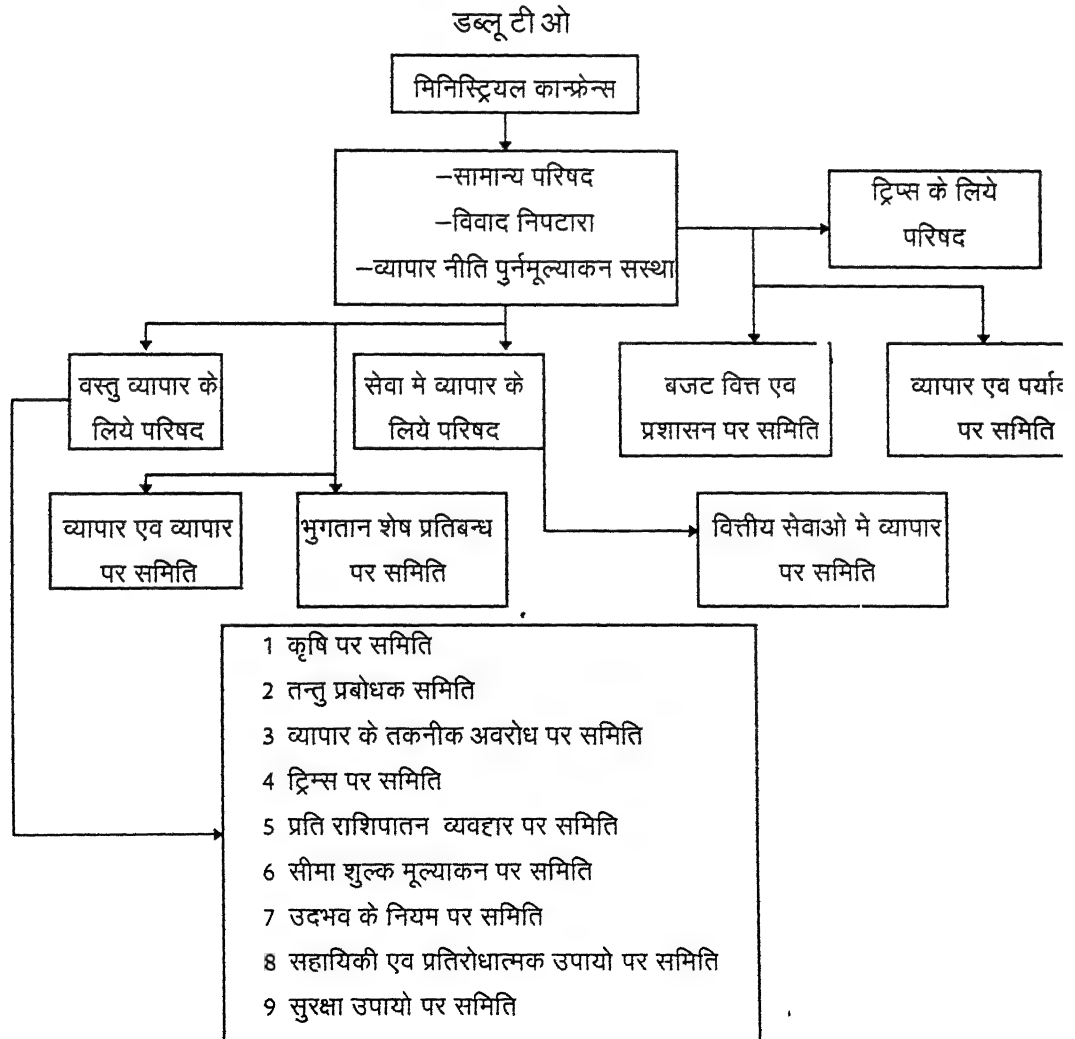
गैट का उरुग्वे दौर साफ तौर पर वार्ता के दौरान गरीब राष्ट्रों पर अमीर देशों की विजय को दर्शाता है। परन्तु गैट का नया अवतार विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार व्यवस्था को नियम बद्ध करके उसे और सुदृढ़ता प्रदान करता है।

## विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विश्व व्यापार संगठन भाग लेते हैं और ये अनुसचचीय बैठक के अन्तर्गत कार्य करते हैं। इसकी प्रत्येक दो वर्षों में एक बार बैठक होती है, और यह सभी बहुराष्ट्रीय

व्यापार समझौते के तहत मुद्दों पर निर्णय लेने के लिये अधिकारी हैं। इसका दैनिक कार्य छोटी-छोटी समितियाँ देखती हैं मुख्यतः जनरल कौंसिल जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। और यह अनुसचयीय समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। जनरल कौंसिल की दो मुख्य उपसमितियाँ हैं— (1) विवाद निस्तारण (2) व्यापार नीति पुनर्परीक्षण इसके अतिरिक्त तीन अन्य और समितियाँ हैं— वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार तथा बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी व्यापार।

### विश्व व्यापार संगठन का संगठनात्मक ढाँचा



## विश्व व्यापार संगठन सचिवालय और बजट :

विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय जेनेवा में स्थित है। इसमें 450 कर्मचारी हैं जिनका प्रमुख महानिदेशक और इनके चार उप-महानिदेशक हैं। इसका कार्य है समझौतों को लागू करना और वार्ता हेतु प्रारूप तैयार करना। इसका प्रमुख कर्तव्य विकासशील देशों के तकनीकी सहायता प्रदान करना है खास तौर पर अल्प विकसित देशों को विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्री तथा सांख्यिकी व्यापार निष्पादक और व्यापार नीतियों का आकलन करते हैं। जबकि इसका विधि कार्यालय व्यापार विवादों के निस्तारण में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नये सदस्यों के प्रवेश हेतु वार्ता का माहौल तैयार करना तथा जो सरकारें सदस्यता ग्रहण करना चाहती हैं उन्हें सलाह प्रदान करना है।

## विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली :

### निस्तारण प्रक्रिया:

विश्व व्यापार संगठन में निर्णय मतदान की अपेक्षा आपसी सहमति से लिया जाता है ताकि सदस्यों के हितों पर पूरी तरह से विचार हो सके। यदि सहमति नहीं हो सकी तो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसी परिस्थितियों में बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाता है जिसमें एक देश एक मत का प्राविधान है।

विश्व व्यापार संगठन समझौते में चार प्रकार की खास मा'दान स्थितियों का वर्णन है। प्रथम, तीन चौथाई बहुमत से सदस्य किसी बहुपक्षीय व्यापार समझौते की व्याख्या को अपना सकते हैं। द्वितीय, इसी बहुमत से किसी खास सदस्य पर बहुपक्षीय समझौते के अतर्गत लागू किसी दायित्व को हटाया जा सकता है। तृतीय, बहुपक्षीय समझौते में सशोधन या तो सभी सदस्यों की सहमति से किया जा सकता है या फिर दो-तिहाई बहुमत के आधार पर यह प्राविधान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। किन्तु यह केवल उन सदस्यों पर लागू होगा जो उसे मानेंगे। अन्तिम, नये सदस्य के प्रवेश का निर्णय दो-तिहाई बहुमत के आधार पर होगा।

### विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने की प्रक्रिया:

अधिकतर विश्व व्यापार संगठन सदस्य वे हैं जो पूर्व में गैट सदस्य थे जिन्होंने उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट में हस्ताक्षर किया था तथा मराक्केश बैठक 1994 में जिन्होंने वस्तुओं और सेवाओं के लिये अपने बाजार प्रवेश वार्ता का सम्पादन किया था। कुछ सदस्य जिन्होंने 1994 के बाद में गैट की सदस्यता ली थी वे भी वस्तु तथा सेवा वार्ता को समाप्त कर, अन्तिम एक्ट में हस्ताक्षर करके विश्व व्यापार संगठन सदस्य बन गए। अन्य देश जिन्होंने उरुग्वे दौर वार्ता में भाग लिया उन्होंने अपने-अपने यहां अनुसमर्थन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त 1995 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की।

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त जो कि "मूल" सदस्यों से सम्बंधित है कोई भी राज्य या 'कस्टम टैरीटरी' जिसके पास अपनी व्यापार नीतियों की पूर्ण स्वायत्तता है वह विश्व व्यापार संगठन सदस्यों की शर्तों पर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम स्तर पर इच्छुक सरकार को अपने व्यापार तथा आर्थिक नीतियों का एक ज्ञापन विश्व व्यापार संगठन को देना होता है। यही ज्ञापन प्रवेश के लिये जाच का आधार बनता है।

इसके साथ ही प्रार्थी सरकार संबंधित सदस्य सरकारों से आपसी वार्ता कर वस्तुओं पर छूट एवं बाध्यता तथा सेवाओं के लिये वचन बद्धता स्थापित करती है। प्रार्थी के व्यापारिक ढांचे और बाजार प्रवेश वार्ता की पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश हेतु मूलभूत शर्तें तैयार की जाती हैं।

अतः कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर प्रवेश हेतु एक ड्राफ्ट प्रोटोकाल तथा आपसी वार्ता के आधार पर सहमति सूची को सामान्य सभा या मिनिस्ट्रियल सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि विश्व व्यापार संगठन की सदस्य दो-तिहाई बहुमत से इसे पारित करते हैं तो प्रार्थी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने के लिये स्वतंत्र हैं और संगठन में आ सकते हैं।

## बाजार में प्रवेश:

सरकारों तथा बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली द्वारा निवेशकों, मालिकों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के लिये ऐसा व्यापारिक वातावरण प्रदान करना है जो व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा दे। ऐसे वातावरण को स्थिर एवं स्थायी होना जरूरी है, खासतौर पर व्यापार की बढ़ोत्तरी और उन्नति के लिये। सुरक्षित तथा स्थायी बाजार प्रवेश टैरिफ एवं कस्टम शुल्क द्वारा ही बनाये रखा जा सकता है। जहाँ कोटे को गैट कानूनी घोषित कर दिया गया है वही विश्व व्यापार संगठन में टैरिफ को कानूनी माना गया है जिसके द्वारा सरकारें अपने स्वदेशी उत्पादों और उद्योगों को सुरक्षित करती हैं तथा अपनी आय में वृद्धि भी लाती हैं। किन्तु इन पर कुछ प्रतिबन्ध भी हैं, जैसे आयात में यह भेदभाव नहीं बरत सकती है। अतः किसी उत्पाद पर जो टैरिफ स्तर बनाया गया है उसे कोई सदस्य स्वतः नहीं बढ़ा सकता है। ऐसा करने पर उसे अपने प्रमुख व्यापारिक पक्षों को मुआवजा देना होगा।

1948 में गैट की स्थापना के बाद जो सात व्यापार दौर हुये उनसे बड़े ही नाटकीय तरीके से प्रशुल्क (टैरिफ) स्तर नीचे गिरे। उरुग्वे दौर ने इसमें बढ़ोत्तरी की और प्रशुल्क स्तर कहीं-कहीं पर शून्य हो गया इसके विपरीत अधिगत प्रशुल्क का स्तर ऊँचा उठ गया।



प्रशुल्क कटौती, जो पाच वर्ष में पूर्ण होगी उसके कारण विकसित राष्ट्रों के औद्योगिक उत्पादों में 40 प्रतिशत की कटौती होगी जिसका औषत 63 प्रतिशत 38 प्रतिशत होगा और आयातित औद्योगिक उत्पादों में जो विकसित राष्ट्रों में शुल्क मुक्त हैं उन में 22 से 44 प्रतिशत तक उछाल आयेगा। प्रशुल्क ढाँचे में अन्ततः विकसित राष्ट्रों के सभी स्रोतों से हो रहे आयात जिन पर 15 प्रतिशत से ऊपर प्रशुल्क लगता है वे 7 से 5 प्रतिशत तक गिर जायेंगे और विकासशील देशों से होने वाले आयात में 1 से 5 प्रतिशत की कमी आयेगी।

उरुग्वे दौर ने सीमित उत्पादों में बढोत्तरी का प्रतिशत विकसित राष्ट्रों के लिये 78 से 99 प्रतिशत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये 2 से 73 प्रतिशत और परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये 73 से 98 प्रतिशत कर दिया है। यह ऐसे परिणाम हैं जो कि उच्च स्तर की बाजार सुरक्षा व्यापारियों तथा निवेशकों को प्रदान कर रहे हैं।

कृषि उत्पादों के सभी गैर-प्रशुल्क आयात प्रतिबन्धों के प्रशुल्कीकरण से कृषि उत्पादों बाजार स्थिरता का स्तर काफी ऊँचा हुआ है। पहले लगभग 30 प्रतिशत कृषि उत्पादों पर कोटा या आयात प्रतिबन्ध थे। ये सभी अब प्रशुल्क में परिवर्तित कर दिए गये हैं जिससे इन्हें पूर्ववर्ती गैर-प्रशुल्क संरक्षण का स्तर तो मिला ही है साथ ही उरुग्वे दौर के कृषि समझौते के अनुसार छ वर्षों के भीतर कम कर दिया जायेगा।

कुछ उत्पादों पर पूर्व में जो प्रतिबंध थे वे कृषि पर बाजार प्रवेश द्वारा समाप्त हो जायेंगे।

कई अन्य विश्व व्यापार संगठन समझौते इस बात की व्यवस्था करते हैं। कि सरकारें अपनी स्वेच्छा से नियम नहीं बदल सकी जिसके फल स्वरूप निवेश और व्यापार का भविष्य स्थिर रह सके। लगभग सभी नीतियों में इस बात का ध्यान दिया गया है कि विद्वेषपूर्ण, भेदभावपूर्ण और अपने उत्पादों को संरक्षण की नीतियों पर विश्व व्यापार संगठन रोक लगा सकता है।

स्वदेशी नियमों, कानूनों और आचार पर पारदर्शिता के द्वारा स्थित व्यापार का भविष्य तैयार किया जा सकता है। कई विश्व व्यापार संगठन समझौते पारदर्शिता प्राविधानों के बारे में बतलाते हैं जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों की घोषणा करना आवश्यक है। इन घोषणाओं के पुनर्मूल्यांकन का कार्य विश्व व्यापार संगठन की संस्थाओं पर है। राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का पुनरावलोकन (Trade Policy Review) स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

### **स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना :**

विश्व व्यापार संगठन "मुक्त" व्यापार संस्था नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो खुले, स्वच्छ और सीधी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

गैर भेदभाव के नियम इस प्रकार से बनाये गये हैं ताकि वे स्वच्छ और साफ माहौल में व्यापार हो सकें और इसी प्रकार के नियम डम्पिंग और ग्राहिकी के नियम भी बनाये हैं। पूर्व गैट नियम जिनके आधार पर सरकारें इन दो तरह की 'अनुचित प्रतिस्पर्धा' पर क्षतिपूर्ति शुल्क लगाती थी उन्हें विश्व व्यापार संगठन समझौते में और विस्तृत तथा साफ किया गया है।

कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता कृषि व्यापार में और सुधार लायेगा। विचार और खोज को बौद्धिक संपदा तथा सेवा में व्यापार को गेट्स इस प्रकार से संरक्षित करेंगे। सरकारी खरीद पर बहुपक्षीय समझौते प्रतिस्पर्धा नियमों को हजारों वस्तुओं की खरीद पर कई राष्ट्रों में लागू होंगे।

## विकास एवं आर्थिक सुधार को बढ़ावा:

तीन-चौथाई से अधिक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य विकासशील देश हैं या वे राष्ट्र हैं जहाँ आर्थिक सुधार के कार्यक्रम चालू हैं क्योंकि पहले यहाँ बाजार व्यवस्था की प्रणाली नहीं थी। उरुग्वे दौर के सात वर्षों में 1986 से 1993 के मध्य 60 से अधिक राष्ट्रों ने व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू किये। उरुग्वे दौर में विकासशील देशों ने और परिवर्तनशील अर्थ व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ कर और प्रभावी रूप में हिस्सा लिया।

इससे यह साफ जाहिर होता है कि व्यापार व्यवस्था औद्योगिक राष्ट्रों के लिये नहीं होती अपितु सभी के लिये होती है। इसने इस बात में भी परिवर्तन ला दिया जहाँ विकासशील देशों को कुछ गैट प्राविधानों और समझौतों में छूट मिल जाती थी। उरुग्वे दौर की समाप्ति के बाद विकासशील देशों ने दिखा दिया कि वे उन दायित्वों को उठाने के लिये तैयार हैं जो कि विकसित राष्ट्रों द्वारा उठाये जा रहे हैं। उन्हें नये और कठिन विश्व व्यापार संगठन प्राविधानों को अपने यहाँ ढालने के लिये परिवर्तन का समय दिया गया, खास तौर पर गरीब और अल्प विकसित देशों को। इन राष्ट्रों को हर प्रकार की सहायता, जिसके अन्तर्गत तकनीकी सहायता में बढ़ोत्तरी प्रमुख है, प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। जहाँ तक विकास के मूल्य की बात है तो खुली बाजारमुखी नीतियाँ, जो विश्व व्यापार संगठन सिद्धांतों पर आधारित हैं उन्हें अपनाया गया है। परन्तु इन नीतियों को लागू करने के लिये लचीलेपन पर भी जोर दिया गया है।

### **निर्यात बढ़ोत्तरी हेतु विशेष सहायता:**

अपने निर्यात को बढ़ाने हेतु, विकासशील देशों के आग्रह पर गैट ने 1964 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (International Trade Centre) की स्थापना की। यह विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्रों, दोनों के द्वारा साथ-साथ चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इसे अकटाड के माध्यम से देखता है।

केन्द्र विकासशील देशों के आग्रह पर उन्हें निर्यात उन्नति कार्यक्रमों को लागू करने हेतु सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही आयात प्रक्रिया और तकनीकी देने में भी सहायता करता है। यह निर्यात बाजार और बाजार तकनीकों पर सूचना तथा सलाह भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निर्यात वृद्धि और बाजार सेवाओं में सहायता प्रदान करता है। साथ ही इन सेवाओं के लिये प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अल्पविकसित देशों के लिये केन्द्र निशुल्क सहायता प्रदान करता है।

### **अन्य प्रावधान :**

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 301 को वैधानिक एवं सार्वजनिक बनाया गया है। अब प्रत्येक विकसित देश अन्तर प्रतिशोधात्मक विवाद निस्तारण हेतु धारा 301 को विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से अपनायेगा। संयुक्त राष्ट्र अब भी उन व्यापारिक क्षेत्रों में जो विश्व व्यापार संगठन की परिधि में नहीं हैं धारा 301 को लागू करेगा। विश्व व्यापार संगठन 14(4) यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक सदस्य इसके नियमों, प्रतिबन्धों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिये सुनिश्चित करेगा जो कि इसके परिधि में आते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के सम्बन्ध में अब स्थित यह है कि या तो कोई भी देश बिना आरक्षण के इसके सभी प्रावधानों को स्वीकार करे या तो विश्व व्यापार की धारा

से अलग हो जाये। इसके अतिरिक्त जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है वह 'गैट' का भी सदस्य नहीं हो सकता क्योंकि उरुग्वे दौर के समय यह तय हो गया था कि 'गैट' विश्व व्यापार संगठन में समाहित है।

विकासशील देशों को किसी भ्रांति के अन्दर नहीं रहना चाहिए जिसमें वे विश्व व्यापार संगठन के अन्तर सम्बन्धों का प्रयोग कर सकें। अपने आर्थिक विकास के निम्नतर स्थिति और विकास प्रक्रिया को बनाये रखने के लिये विकसित देशों से आयात की निर्भरता तथा आवश्यकताओं के साथ जो विकसित कमजोर, सौदेबाजी की शक्ति के कारण विकासशील देश कदाचित गैट के अनुच्छेद (23) के अन्तर्गत बदला लेने के योग्य होते थे यह वास्तव में सुविचार है कि वे अब साधारणतया बदला लेने में समर्थ हैं क्योंकि इस समय बदला के लिये तमाम वैकल्पिक क्षेत्र हैं।

### संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व व्यापार संगठन :

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में जो लोग अग्रणी रहे उनका दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र एवं गैट के बीच स्थापित सम्बन्धों का चित्रण करना था। गैट और संयुक्त राष्ट्र के बीच कभी भी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ। क्योंकि गैट का स्वाभाव एक अंतरिम व्यवस्था तक सीमित था न कि पूर्ण रूपेण अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और गैट के महानिदेशक के बीच पत्रों का आदान प्रदान गैट सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्धों की ओर संकेत करता है।

उपर्युक्त वर्णित पत्रों की श्रृंखला में गैट व्यावहारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र विशिष्टीकृत अभिकरण माना जाता है। यद्यपि गैट वास्तविक रूप से संयुक्त राष्ट्र की अधिक विशिष्टीकृत अभिकरण के रूप में कार्य नहीं किया, न तो अन्य माध्यमों से ही सभी उद्देश्यों के लिये गैट एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के बाहर कार्य करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व व्यापार संगठन के आगमन से कोई लेना देना नहीं है, विश्व व्यापार संगठन समझौता महानिदेशक (विश्व व्यापार संगठन) के साथ होगा न कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ।<sup>1</sup>

विश्व व्यापार संगठन समझौते में संयुक्त राष्ट्र के विषय में अलग से कुछ भी नहीं वर्णित है जो कि "अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों" के वर्गीकरण में आता है। विश्व व्यापार संगठन का अनु० 5(1) व्यवस्था करता है कि "विश्व व्यापार संगठन" की सामान्य परिषद के अन्तर्गत सरकारी संगठनों जो कि विश्व व्यापार संगठन के दायित्व से सम्बन्धित हैं उनके साथ सहयोग के लिये उचित कदम उठायेगा।<sup>2</sup> वर्ष 1994 के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने गैट के महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व व्यापार संगठन के सम्बन्धों के प्रश्न पर एक पत्र लिखा था। महासचिव ने अपने 30 मार्च 1994 के पत्र में यह संकेत दिया था कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विश्व

---

1 Dubey, Muchkund An Unequal Treaty, 1996, Page 111

2 वही, पृष्ठ 112

व्यापार सगठन एक महत्वपूर्ण दूरी को कम करेगा और सयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदार जुड़ेगा।<sup>3</sup> परन्तु इसके बाद की प्रगति इस बात का संकेत करती है कि बड़ी आर्थिक शक्तियां तथा विश्व व्यापार सगठन के सदस्य विश्व व्यापार सगठन को सयुक्त राष्ट्र व्यवस्था से जोड़ने में रूचि नहीं रखते।

सयुक्त राष्ट्र का अनु० 57 विश्व व्यापार सगठन जैसे सगठनों के लिये सयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बन्धों को स्वैच्छिक बताता है।<sup>4</sup>

### विश्व व्यापार संगठन एवं अंकटाड :

गैट एव अंकटाड को विश्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन (विश्व व्यापार सगठन) को आंशिक प्रतिक्रिया थी जो कि अस्तित्व में नहीं आ सकता। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सगठन स्थापित किया गया होता तो गैट इसका एक भाग होता। अंकटाड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन का स्वतः अनुमानित हिस्सा होता। वर्ष 1964 में अंकटाड के प्रथम सत्र में विकासशील देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन को स्थापित करना चाहते थे परन्तु उस पर आम सहमति नहीं हो सकी और अंकटाड को स्थापित करने पर ही सतोष करना पड़ा। अंकटाड, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन के विशिष्ट अभिकरण के रूप में नहीं स्थापित किया जा सका जैसा कि सोचा गया था अंकटाड

---

3 Dubey, Muchnd Unequal Treaty, 1996 Page 112

4 Ibid, Page 113



महा सभा के प्राधिकृत काम करता है। गैट की तरह विश्व व्यापार संगठन भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन नहीं है जैसा कि उसकी घोषण में कहा गया था।<sup>5</sup>

### विश्व व्यापार संगठन का भारत एवं विकासशील देशों पर प्रभाव.

विश्व व्यापार संगठन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विकासशील देशों के दृष्टिकोण से अन्तर सम्बन्धों की विकृति को अनुमति देना है। विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटारे की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 22(3) के अनुसार "सामान्य सिद्धांत यह है कि शिकायत करने वाले पक्षकार को पहले उस क्षेत्र की रियायत को स्थगित करना होगा।" और यदि यह समझता है कि "यह व्यवहारिक या प्रभावी नहीं है" तो "तुसी समझौते के तहत अन्य क्षेत्रों में भी रियायत या छूट स्थगित कर दी जायेगी। भारत उन 76 अन्य देशों में से एक है जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के प्रथम दिवस पर ही उसके सदस्य बन गये थे। इसके साथ ही इसके समर्थन एवं विपक्ष में लोगो ने विचार प्रकट किये हैं—

### समर्थन :

- 1 हम उन कुछ विकासशील देशों में से एक हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उदारीकरण कार्यक्रम लागू किया है। विश्व व्यापार संगठन सदस्यों में तीन-चौथाई के ऊपर विकासशील देश हैं जहाँ आर्थिक सुधार कार्यक्रम चालू

है। इन सभी देशों ने काफी विचार विमर्श के बाद ही विश्व व्यापार सगठन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। अतः यह स्पष्ट है कि उन्हें सदस्य बनने से आर्थिक लाभ होने की आशा होगी। भारत को इसमें अपवाद नहीं होना चाहिये।

- 2 विश्व व्यापार सगठन मात्र औद्योगिक राष्ट्रों के लिये है, यह आलोचना तर्क सगत नहीं है। 1986 से 1993 के सात वर्षों के दौरान उरुग्वे दौर में साठ से अधिक विकासशील राष्ट्रों ने उदारीकरण कार्यक्रमों को लागू किया है। कुछ ने गैट वार्ता में प्रवेश के लिये तो कुछ ने स्वतः ही ऐसा किया है। इस दौरान विकासशील देश तथा आर्थिक परिवर्तनशील देशों ने उरुग्वे दौर की वार्ता में खुल कर एवं प्रभावी रूप में भाग लिया।
- 3 उरुग्वे दौर की समाप्ति के बाद विकासशील देश उन सभी दायित्वों के निर्वाह के लिये तैयार हो जाओ कि विकसित राष्ट्रों के जिम्मे थे। जो अति गरीब राष्ट्र के जिम्मे थे जो अति गरीब राष्ट्र हैं उन्हें इस बीच के समय में समाहित होने के लिये ताकि वे विश्व व्यापार सगठन के कठिन एवं नये प्राविधानों को ठीक से समझ सकें इस लिये उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन राष्ट्रों को विश्व व्यापार सगठन समझौते के अंतर्गत हर प्रकार की आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान कराई जायेगी। अतः विश्व व्यापार सगठन के

सिद्धांतों पर आधारित खुले बाजार की नीतियों का व्यापक तौर पर स्वागत किया गया है। इस लिये यह आवश्यक है कि इन नीतियों को अमल में लाने के लिये विकासशील राष्ट्र अपनी नीतियों में कुछ लचीलापन लाये।

- 4 भारत के लिये विश्व व्यापार संगठन का असली महत्व इसके द्वारा राष्ट्र के विकास में आयात उद्योग को बढ़ावा मिलने से है। तकनीकी विकास एवं रोजगार उपलब्धि हेतु आवश्यक है कि अन्य राष्ट्रों के लिये भारत अपने पट खोले। अर्द्ध-आर्थिक स्वतंत्रता की प्रणाली जो पूर्व में हमने अपनाई थी उससे स्वदेशी उद्योग तथा कृषि के विकास में काफी सहायता मिली। परन्तु इसमें आंतरिक सक्रियता की कमी थी। सक्षिप्त में यह एक बंद प्रणाली थी जहाँ विकास एवं विस्तार के लिये कोई रास्ता नहीं था। आगे बढ़ने के लिये उद्योग को बाह्य व्यापार तथा निर्यात बाजार में भागीदारी से ही प्राप्त होगा।
- 5 एक और कारण है जिसकी वजह से भारत को विदेशी बाजार की आवश्यकता है। काफी लम्बे समय से हम यह मानते चले आ रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वतः पूर्ण हैं। किन्तु सत्य यह है कि पेट्रोलियम, उर्वरक, पूँजी उत्पाद, कच्चे माल एवं जीवन दायनी दवाओं के लिये भारतीय अर्थ व्यवस्था काफी हद तक आयात पर निर्भर है। जब तक हम आयात पर निर्भर रहेंगे तक तक हमें इन आयातों की देनदारी के लिये निर्यात करने की जरूरत रहेगी।

6 भारत को जब तक आयात-निर्यात की आवश्यकता है हम बहुराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से बाहर नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि चीन, जो कि विश्व का आखिरी बड़ा समाजवादी देश बचा है, वह भी विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश पाने के लिये प्रायासरत है।

7 भारत यदि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, जो कि विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित है, उसका लाभ उठा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, गैट द्वारा 1964 में विकासशील राष्ट्रों के आग्रह पर स्थापित किया गया था ताकि उनके आयात को बढ़ावा मिल सके।

यह केन्द्र विकासशील देशों को निर्यात विकास के लिये हर प्रकार की मदद करता है। यह निर्यात बाजार एवं बाजार तकनीक के बारे में भी हर प्रकार की सूचना प्रदान करता है ताकि पिछड़े राष्ट्रों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिले।

8 विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा गैट सचिवालय के अनुमान के अनुसार उरुग्वे दौर वार्ता के लागू हो जाने के पश्चात विश्व आयात में प्रति वर्ष 213 से 274 मिलियन यू०एस० डालर की वृद्धि होगी। गैट सचिवालय के अनुसार सन् 2005 में व्यापारिक वस्तुओं के सम्पूर्ण व्यापार में

745 बिलियन यू०एस० डालर की वृद्धि होगी। गैट सचिवालय यह भी बताता है कि सबसे अधिक वृद्धि कपड़ा 60 प्रतिशत कृषि, वन सम्पदा तथा मत्स्य उत्पादों 20 प्रतिशत की होगी। चूंकि भारत का वर्तमान में ओर भविष्य में भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक निर्यात होगा अतः यह तथ्य सत्य है कि भारत इसमें अधिक लाभ उठा सकेगा। यदि यह मान लिया जाये कि विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 0.5 प्रतिशत से बढ़ कर 1 प्रतिशत की हो जाती है और हम जो भी अवसर मिलता है उसका लाभ उठा लेते हैं तो हमारे व्यापार में प्रति वर्ष 2.7 बिलियन यू०एस० डालर की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यदि हम थोड़ा उदार अनुमान मानते हैं तो 3.5 से 7 बिलियन यू०एस० डालर तक निर्यात में वृद्धि होगी।

- 9 विश्व व्यापार संगठन सदस्यता का एक अन्य लाभ यह भी है कि भारत (या किसी भी देश) को दो पक्षीय व्यापार वार्ता एवं समझौते नहीं करने पड़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने से हम सभी अन्य सदस्य देशों के साथ सीधे व्यापार पर सकते हैं बिना किसी अन्य समझौते के इस सदस्यता में विश्व व्यापार संगठन को हम एक टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में देख सकते हैं।

- 10 उरुग्वे दौर पैकेज मे कई ऐसे क्षेत्र है जो कि बाजार मे प्रवेश से सबन्धित है ।  
इनमे से प्रमुख प्रशुल्क, वस्त्र तथा कृषि, भारत इन सभी मे क्षेत्रो मे लाभ की स्थिति मे है और सारे प्राविधान देश के हित मे है ।

### सदस्यता के विरोध में तर्क :

- 1 भारत तथा अन्य विकासशील देशो मे आख मूद कर विकसित राष्ट्रों द्वारा बिछाये गये जाल मे पदार्पण कर लिया । अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के साथ मिल कर विश्व व्यापार सगठन केवल विकसित राष्ट्रों के हितो के लिये बनाया गया है । चाहे जितनी भी बातें की जाये विश्व व्यापार सगठन कभी भी विकासशील देशो के उत्पादो के लिये खुले व्यापार की व्यवस्था नहीं करेगा । यह ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिसमे पूँजीवादी देशो के प्रभुत्व एव प्रधानता ही सर्वोपरि हो । असलियत मे उरुग्वे दौर की वार्ता को अमरीका तथा पश्चिम यूरोप के दशो ने ही चालू करवाया ताकि उनके यहा के उद्योगो को नये बाजार मिल सके मुख्यता सेवा एव वित्तीय क्षेत्रो मे ।
- 2 यद्यपि उरुग्वे दौर पैकेज मे दर्शाये गये क्षेत्र देखने मे भारत के लिये काफी हितकारी लगते है । परन्तु जो भी लाभ टैरिफ छूट एव कोटो के हटने से मिलेगे वे सब नये नियम एव कानून तथा व्यापार मे होने वाले व्यवधानो मे ही खो कर रह जायेगे ।

3 समझौते में जो भी वर्णित है और हकीकत में जो भी क्रियान्वित होता है उसमें काफी अंतर है। उदाहरण के लिये विवाद निस्तारण प्रक्रिया। विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार विश्व व्यापार संगठन सदस्य किसी भी व्यापार विवाद के आपस में नहीं सुलझायेगे बल्कि बहुपक्षीय विवाद समझौता प्रणाली के अंतरगत अपने विवादों को सुलझायेगे और उसके निर्णय को मानेंगे।

परन्तु हाल ही में जापान और अमरीका के मध्य कार सघर्ष में प्रतिपादित प्रणाली का खुला उल्लंघन हुआ। कारों की बिक्री एवं कल पुर्जों पर हुए जापान और अमरीकी समझौते वाशिंगटन द्वारा प्रतिबन्धों की आड़ में कराये गये।

जो विवाद निस्तारण प्रक्रिया में हुआ वह अन्य प्राविधानों में भी हो सकता है। अमरीका अपने हितकारी व्यापार उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी विकासशील देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता जो कि विश्व व्यापार संगठन समझौते का खुला उल्लंघन है। आज यह जापान के खिलाफ हुआ है कल यह भारत, पाकिस्तान या बंगला देश पर हो सकता है।

### **विश्व व्यापार संगठन की पराजय :**

अमरीका और जापानी वार्ताकारों द्वारा जेनेवा में जो समझौता अमरीका द्वारा जापानी कारों पर प्रतिबंध लगाये जाने के कुछ घंटों पूर्व हुआ वह बड़े जापानी कार बनाने वाली कंपनियों द्वारा 'स्वेच्छा' से क्रय प्लान के अंतरगत हुआ।

अमरीका द्वारा सुझाये गये व्यवस्था के अतर्गत जापान की पाच प्रमुख कार बनाने वाली कंपनियों को अमरीका में 1998 तक अपने कार उत्पादन को 21 मिलियन से बढ़कर 265 मिलियन तक करना होगा। इस वृद्धि से अमरीका में निर्मित कारों के कलपुर्जों में 675 मिलियन यू०एस० डालर की बढ़ोत्तरी होगी साथ ही 1998 तक जापान उत्तरी अमरीका में निर्मित पुर्जों में 56 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगा। जापान में बनाई जाने वाली कारों के प्रमुख निर्माताओं 6 विलियन यू०एस० डालर के विदेशी पुर्जों को खरीदना होगा। इस व्यवस्था के लिये अमरीका ने जापानी सरकार से गारण्टी मागी थी जिसे जापान ने अस्वीकार कर दिया। जापान को इस वार्ता में कुछ सीमित लाभ अवश्य, हुआ परन्तु समझौते पर सारी निगरानी अमरीकी आटो इन्डस्ट्री अपनी सरकार के साथ मिलकर रखेगी। यदि जापानी कार उद्योगपति समझौते का उल्लंघन करते हैं तो धारा 301 के अतर्गत उन पर पुनः कार्यवाही हो सकती है।

- 4 सबसे अधिक क्रय जो विश्व व्यापार संगठन के सबंध में व्यक्त किया जा रहा है वह है दवाओं और कृषि से संबंधित सामान के दामों में व्यापक वृद्धि।

## निष्कर्ष :

सभी बातों को विचारने के बाद हम यह कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन सदस्यता हमारे लिये हितकारी होगी क्योंकि इसका लाभ उठाने के लिये हमें अपने



उत्पादों एवं सेवाओं में सुधार लाना होगा ताकि हम विश्व बाजार में बेहतर स्थिति में हों।

### व्यापार समूह :

गैट द्वारा खुले विश्व व्यापार की स्थापना में असफल होने के कारण से व्यापारिक समूह का उदय हुआ। अब गैट विश्व व्यापार संगठन के रूप में पुनर्जीवित हो गया है। जिसके सदस्यों की संख्या काफी है। आशा की जाती है कि विश्व व्यापार संगठन तथा व्यापार के हित आपस में नहीं टकराएंगे। यहां पर कुछ व्यापार समूहों का विवरण दिया जा रहा है।

| क्र० | व्यापारिक समूह का नाम                     | सदस्य राष्ट्र  | स्थापना वर्ष |
|------|---|--|--------------|
| 1    | यूरोपियन कम्युनिटी (EC)                   | बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लक्सम्बर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन और यू० के० | 1957         |
| 2    | यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA)       | ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लिचटेन, स्वीडन, नार्वे, स्वीडन और स्वीटजरलैंड         | 1960         |
| 3    | नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट        | यू० एस० ए०, कनाडा, मैक्सिको  | 1989         |
| 4    | लैटिन अमेरिकन इन्टीग्रेशन एसोसिएशन (LAIA) | मैक्सिको, परगुए, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला  | 1980         |
| 5    | सदर्नकोन, कॉमन मार्केट (MERCOSUL)         | अर्जेन्टीना, ब्राजील, परगुए, उरुग्वे   | 1991         |
| 6    | एनडियन कॉमन मार्केट (ANCOM)               | बोलिविया, कोलम्बिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला                                       | 1969         |
| 7    | सेन्ट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट (CACM)      | कास्टा रिका, एलसेलेवेडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होन्डुरास                           | 1960         |

|    |   |   |       |
|----|---|---|-------|
| 8  | केरेबियन कामन मार्केट (CARICOM)                                     | एनटिगुआ और बरमुडा बहामास बारबेडोस बिलेज, डोमनिका गेनेडा गुआना, जमैका, मानटेसेरेट सेटकिट्स नेविस सेट लूसिया सेट विनसेट, त्रिनाद                            | 1973  |
| 9  | ओरगेनाइजेशन ऑफ इस्टर्न केरेबियन स्टेट्स (OECS)                      | एनटिगुआ और बरमुडा, डोमनिका ग्रनेडा, मानटेसेरे सत किट्स नेविस सेट लूसिया, सेट विनसेट ग्रेनेडीस तथा वरजिने आइलैण्ड्स  | 1981  |
| 10 | गल्फ कोआपरेशन कौंसिल (GCC)  | बहरीन कुवैत ओमान, कतर, सऊदी अरबिया यू०ए०ई०  | 1981  |
| 11 | अरब कामन मार्केट (ACM)  | मिश्र, इराक, जार्डन, लेबनान लीबिया, सीरिया मारिटानिया   | 1964  |
| 12 | अरब महारेल यूनियन (AMU)   | अलजीरिया, लीबिया, मारिटानिया, मोरक्को, टूनिसिया   | 1989  |
| 13 | साउदर्न अफ्रीकी कष्टमस यूनियन (SACU)                                | बोपूथातसवाना, बोस्तवाना, सिसकी, लेगोथो, नामाबिया दक्षिणी अफ्रीका, स्वीटरजरलैण्ड, ट्रासिकी, वेनडा  | 1969  |
| 14 | इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS)                | बेनिन, बुरकीना फासो, केप वेरडे, कोटे डी आइवरे, गैम्बिया, घाना, गिनिया बिसाउ, लाइबीरिया, माली, मारीटानिया, नाइजर, टोगो नाइजेरिया, सेनेगल, सिएरालोन,        | 1975, |
| 15 | प्रिफिसियल ट्रेड एरिया फार इस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रीकन स्टेट्स (PTA) | बुरुन्डी, बुरकीना फासो, काम्फ्रेस, डीजीबूती, इथोपिया, केनिया, लेसेथो मलावी, मारीशियस, मोजाम्बीक, रवाडा, सोमाली, स्वाजीलैंड, तन्जानिया, यूगाडा, जिम्बाब्वे | 1981  |
| 16 | इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स (CEEAC)               | बुरुन्डी, कैमीरून, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कान्गो, इक्योटोरियल, गीनिया, गोबोन रवाडा सावटोन जैरे, 1981   | 1981  |

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 17 | वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्यूनिटी (CEAO)  | लेनिन बुरकीना फासो कोटेजी<br>आइवरे माली मारिटानिया लाइजर<br>सेनेगल             | 1959 |
| 18 | इकोनॉमिक एण्ड कस्टम्स एण्ड<br>यूनियन आफ सेन्ट्रल अफ्रीका<br>(UADEC)                        | कोमेरोन चार्ड कोन्गो, सेन्ट्रल<br>अफ्रीकन रिपब्लिक इक्यूटोरियल<br>गीनिया गेबोन | 1964 |
| 19 | मानो रिवर यूनियन (MRU)   | गीनिया लाइबेरिया सिएरालोन  | 1973 |
| 20 | एशोसिएशन ऑफ साउथ ईष्ट<br>एशियन नेशनस<br>(ASEAN/AFTA)                                       | बुरुनेई इन्डोनेशिया मलेशिया<br>फिलीपीन्स, सिंगापुर थाईलैण्ड                    | 1967 |
| 21 | बैकाक एग्रीनेन्ट (BA)  | बंगला देश, भारत लावोस दक्षिणी<br>कोरिया, श्रीलंका                              | 1976 |
| 22 | आस्ट्रेलिया, नियुजीलैण्ड,<br>क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशनस<br>एण्ड ट्रेड एग्रीमेन्ट<br>(ANZCERT) | आस्ट्रेलिया नियुजीलैण्ड  | 1983 |
| 23 | साउथ एशियन प्रिफिन्सियल<br>ट्रेडिंग एग्रीमेन्ट्स (SAPTA)                                   | सार्क राष्ट्र  | 1993 |
|    |  |  |      |

यद्यपि अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक संगठनों का भारत सदस्य है परन्तु इन सबके बावजूद विश्व व्यापार संगठन से भारत को तुलनात्मक अधिक लाभ की संकल्पना की गयी है। भारत ने प्रमुख व्यापारिक समूहों की सदस्यता ग्रहण न करके बुद्धिमत्ता ही की है। क्योंकि अब विश्व व्यापार संगठन के उपरान्त विश्व व्यापार एवं बाजार में प्रवेश आसान हो गया है।

## अध्याय :7

गैट, डंकल एवं विश्व व्यापार संगठन  
का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं एवं  
भारत पर प्रभाव

जब भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य एवं व्यापारिक समझौते या नियमावली में परिवर्तन किये जाते हैं तो निश्चित रूप से सम्बन्धित देशों पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान दशक में डकल प्रतिवेदन छाया रहा है गेट के पूर्व महासचिव आर्थर डकल के द्वारा तैयार की गयी नियमावली को आधार मानकर ही वर्तमान समय में गेट को परिवर्तित करके विश्व व्यापार संगठन स्थापित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव विश्व भर में पड़ना निश्चित है। मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव तीन क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है। परन्तु इसका स्पष्ट प्रभाव 2005 ई० तक दिखाई पड़ेगा। डकल प्रस्ताव का प्रभाव भारत एवं विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं के कृषि व्यापार, उद्योग, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ेगा जिससे सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक जन जीवन अवश्य ही प्रभावित होगा और जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

## **सामाजिक प्रभाव :**

डकल के प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसके आर्थिक पहलू पर पड़ने वाला प्रभाव है। जब भी किसी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो उसका आर्थिक ढाँचा कभी न कभी अवश्य प्रभावित होता है। इसी क्रम में डकल प्रस्ताव के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती प्रतीत हो रही है। यदि हम केवल विकासशील अर्थव्यवस्था को अलग करके देखें तो हमें स्पष्टतः यह प्रतीत हो रहा है कि विकसित

अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा विकासशील अर्थव्यवस्था इससे कहीं अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुई है सामान्यतः यह प्रतीत होता है कि विकासशील राष्ट्रों के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था को एक बाजार में परिवर्तित कर इन बाजारों में अपने उत्पादों को भरने की साजिश के तहत डकल प्रस्ताव को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है। इस ब्रह्मास्त्र का घातक स्वरूप वर्तमान में दिखाई पड़ने लगा है। वासमती चावल, हल्दी एवं नीम के पेटेन्ट की प्रक्रिया को लेने की कोशिश के रूप में। राईश टेक कम्पनी के द्वारा वासमती चावल का पेटेन्ट करा लेना जिसको सारा विश्व जानता है कि इस पर भारत का मौलिक अधिकार बनता है। यह सर्वथा अनुचित कार्य था और इसको अमेरिका द्वारा पेटेन्ट देना अपने कम्पनी को, बिना जांच पड़ताल किये, इसके असली स्वरूप को प्रकट करता है। विश्व व्यापार संगठन, के द्वारा विश्व व्यापार को प्रोत्साहन मिलना निश्चित है विश्व व्यापार पर से प्रतिबन्धों को कम करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकासशील अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कहा तक प्रभावित करेगा अभी यह कह पाना कठिन है, परन्तु भविष्य में इसके प्रभाव दूरगामी होंगे। प्रत्येक देश का सामाजिक ढांचा वहाँ के रीति रिवाजों के साथ-साथ वहाँ के भौगोलिक वातावरण के द्वारा व्यवस्थित होता है। विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली से देश के सामाजिक क्रिया-कलापों में असंतुलन पैदा हो जाने की सम्भावना विद्यमान है। जब किसी देश के साथ व्यापारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू होती है तब वहाँ का सामाजिक

परिदृश्य भी प्रभावित होता है। लोग अपने सांस्कृतिक रहन सहन को प्रभावित होने से नहीं रोक सकते हैं। व्यक्ति सदैव दूसरों के रहन सहन को देखकर उसी प्रकार अपने क्रिया कलापो में परिवर्तन की कोशिश करता है। जो उसके भौगोलिक वातावरण से मेल नहीं खाता इससे सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे कई प्रकार से देखा जा सकता है।

## 1 रहन सहन:

विश्व व्यापार से न केवल व्यापारिक जगत में परिवर्तन आता है बल्कि रहन-सहन भी प्रभावित होता है। भारत के लोगों पर यूरोप के रहन-सहन की छाप पड़ने लगी है। यहां के लोगों का पहनावा कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ है। लोग यूरोप के पहनावे को अपनाने में गर्व का अनुभव करते हैं जो वास्तव में उनके लिये हानिकारक होता है। हमारे यहां लड़के एवं लड़कियों का वस्त्र पूर्ण एवं व्यवस्थित हुआ करता था परन्तु आज वह लुप्त होता जा रहा है और बदन दिखाऊ कपड़े धारण करते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति जो अपने को सभ्य कहते हैं अर्द्धनग्न रहते हैं जो पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर भारत को प्रभावित कर रही है यदि कम कपड़े सभ्यता का परिचय देते हैं तो लोगों को कम कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है? वे वस्त्र धारण ही न करें निर्वस्त्र ही रहे ज्यादा सभ्य कहे जायेंगे। इस देश का अपना एक पारिवारिक ढांचा रहा है, जो इस समय चरमरा रहा है। भारतीय गांवों में तो यह संस्कृति विद्यमान दिखाई

पडती है परन्तु शहरो मे पूर्ण रामाप्ति की ओर अग्रसर है। यदि विज्ञापनो को हम देखे तो हमे अर्द्धनग्न महिला दिखाई पडेगी। जैसे स्वय को निमन्त्रण दे रही है इसका उपयोग करिये और मेरी तरह भोगवादी सस्कृति को अपनाइये। यूरोप की आवश्यकता होगी भौगोलिक परिदृष्य के अनुसार परन्तु भारतीय परिदृष्य इसको स्वीकार नही करता है। क्यो कि यहा गर्मी अधिक पडती है यहा कपडे पहनना आवश्यक है यहा के लोग अर्द्धनग्न महिला देखने के आदी नही है। यदि इरा शदी के अन्तिम दशक पर नजर डाले तो स्पष्ट दिखाई पडता है कि अपराध बढे है। इसमे बलात्कार भी बडी तेजी से बढे है लोग अपने पारिवारिक रिश्ते भूलना शुरू कर दिय है। धीरे धीरे पति - पत्नी के सम्बन्ध परमेश्वर से हटकर लाइफ पार्टनर की रीमा पर आ गया है।

विश्व व्यापार सगठन के परिणाम स्वरूप ही देखा जा रहा है कि लोग अपना खान पान भी परिवर्तित करते जा रहे है लोगो को मास मदिरा के साथ-साथ सुन्दरियो की आवश्यकता पडनी शुरू हो गयी है। हमारे देश के भौगोलिक वातावरण को पहाडी क्षेत्रो को छोड कर देखे तो साफ दिखाई पडता है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है परन्तु हम सेवन न करे तो असभ्य कहे जायेगे। हम भूल जाते है कि यूरोप के भौगोलिक वातावरण की आवश्यकता है शराब, क्योकि वहा सर्दी ज्यादा पडती है।



## पारिवारिक एवं सामाजिक विभाजन:

वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के तहत मुक्त व्यापार नीति के द्वारा आर्थिक क्रिया कलापो का दौर चल रहा है। इन आर्थिक क्रिया कलापो के साथ-साथ सामाजिक क्रिया कलापो का एक दूसरे देश के साथ आदान प्रदान भी हो रहा है। जिसका प्रभाव हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक ढांचे पर निरन्तर पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक देशों की अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक क्रिया विधि रही है परन्तु वर्तमान समय में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ जाने के कारण देश के पारिवारिक ढांचे टूटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि हम अपने पूर्व पारिवारिक ढांचे को देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि संयुक्त परिवार की परम्परा विद्यमान रही है। परिवार के कुछ सदस्य या एक सदस्य द्वारा आर्थिक स्रोत होने पर भी पूरे परिवार को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की क्षमता की विद्यमानता रही है। परन्तु वर्तमान समय में मुक्त व्यापार नीति के द्वारा विदेशी संस्कृति के आगमन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का आर्थिक खर्च असीमित हो रहा है जिससे पारिवारिक कलह तीव्रता से दिखाई पड़ रही है इसी कारण भाई-बहनें को लोग भूलते जा रहे हैं और हर एक परिवार विघटन की ओर बढ़ रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के द्वारा संचालित विश्व आर्थिक परिदृश्य साफ-साफ दिखाई पड़ता है आज का व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से दूर हटते हुए केवल

आर्थिक क्रिया कलापो में व्यस्त रहा है जिससे व्यक्ति आर्थिक दिमाग का हो गया है। अभी तक आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियाँ व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित की जाती रही हैं जिससे समाज की संरचना सम्पादित करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता था परन्तु व्यक्ति आर्थिक दिमाग के होने के कारण स्वार्थी प्रवृत्ति के विचार से ओत प्रोत होता जा रहा है। जिसका सामाजिक ढाँचे पर दूरगामी परिणाम पड़ना निश्चित है। इससे सामाजिक ढाँचे को छिन्न भिन्न होने की आशंका पूर्ण दिखाई पड़ रही है। परन्तु पारिवारिक एवं सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से देखने के लिये हमें इन्तजार करना होगा।

इस प्रकार की गतिविधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा आयातित हो रही हैं। यदि हम अभी इसके विषय में नहीं ध्यान देते हैं तो कुछ वर्षों में अपना मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। नैतिकता साथ छोड़ देगी और उसकी जगह भोगवादी संस्कृति स्थापित हो जायेगी देश के युवा पीढ़ी को बेकार साबित होगी। हम अपने घरों में परिवार के साथ-साथ दूरदर्शन प्रोग्राम देखने में अभी शर्म करते हैं परन्तु 21 सदी में हो सकता है कि दूरदर्शन हमें वे चीजें परोसे जो कल्पनीय ही न हो। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा हम आयात-निर्यात तक प्रभावित ही नहीं होंगे बल्कि अपनी नैतिकता, सामाजिक रहन सहन को भी प्रभावित कर रहे हैं। जिस देश की युवा पीढ़ी भोगवादी संस्कृति में डूबी हुई हो तो उस देश का मालिक ईश्वर ही हो सकता है। हमें विश्व व्यापार संगठन

संगठन के द्वारा होने वाले व्यापार पर नजर रखकर यह व्यवस्थित करना होगा कि भोगवादी संस्कृति को प्रभावी न होने दिया जाये यदि तत्काल इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत चंदेलों के शासन काल की तरफ बढ़ जायेगा और गर्त में जाने की स्थिति सुनिश्चित होगी।

### राजनैतिक प्रभाव :

जब—जब किसी देश में वृहद् आर्थिक परिवर्तन का दौर रहा है तो उस देश की राजनैतिक व्यवस्था इससे अप्रभावित रहे। यह सम्भव नहीं है जहाँ पूरे विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ हो तो राजनैतिक प्रभाव पड़ना तो निश्चित है। यदि विकासशील देश की राजनैतिक व्यवस्था पर एक नजर डालें तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता कि राजनैतिक क्रिया कलाप इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रभावित हुए हैं भारतीय उप—महाद्वीप को यदि हम देखें तो निश्चित रूप से भारत और इसके आस—पास के देश जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान आदि देशों की राजनैतिक व्यवस्था इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है भारत में तो इसके प्रारम्भ से ही राजनैतिक एवं सामाजिक विरोध पूरे जोर शोर से होता रहा है यदि 1991 के बाद की स्थिति का आकलन करें तो हमें पूर्ण रूप से यह दिखाई पड़ता है कि आर्थिक उदारता का जो दौर शुरू हुआ वह 1991 में राजनैतिक रूप से विश्व व्यापार संगठन के पूर्व ही स्थिति को संगठन के अनुसार

व्यवस्थित करने की थी। उस समय इस आर्थिक उदारता का लगभग सभी दलो ने विरोध किया चाहे वर्तमान समय में सत्ता में स्थापित भारतीय जनता पार्टी हो, या इसके पूर्व सत्ता एवं सत्ता में भागीदार दल (जनता दल, समा, मार्क्सवादी पार्टी तथा इसके सहयोगी दल आदि) या संयुक्त मोर्चे के सदस्यगण सभी ने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का लोकसभा एवं उसके बाहर विरोध करते हुए कहा था कि इनके द्वारा तैयार की गयी नीति पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक तथा विश्व के शक्तिशाली देशों के दबाव में बनाई गयी है।

परन्तु वास्तविक रूप में यह सब राजनीतिक दल भी उसी प्रकार कार्य करते रहे सत्ता प्राप्त के बाद जिस प्रकार का कार्य श्री मनमोहन के द्वारा किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी ने देश की जनता का राजनैतिक रूप से शोषण किया एवं उनके हितों को नजर अन्दाज किया। लोग डकल का विरोध करते रहे और स्वदेशी का नारा देते आज भी नहीं थकते हैं यह सत्य है कि सत्ता में आकर लोग सारे सिद्धांत भूल जाया करते हैं। यह एक कड़वा सत्य है यदि वामपंथी दलो पर विचार किया जाय तो डकल के मुद्दे पर इनके द्वारा भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि डकल प्रस्ताव के सुझाव के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के गठन तक से आज तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना

हुआ है और वर्तमान समय में भी कुछ सामाजिक संगठन की प्रभावी व्यक्तित्व इसके विरोध को जारी रखे हुए हैं— जैसे विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता वन्दना शिवाजी एव आजादी वचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू में इसका राजनैतिक विरोध हुआ और सत्ता दल को हानि भी हुई और लोगों ने इसका विरोध किया परन्तु किसी न किसी रूप में सभी दल सत्ता में रहकर यह सिद्ध किया कि हम इसको लागू रखेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि राजनैतिक दलों का विरोध स्वार्थ परक एवं भारतीय जनतन्त्र के साथ कपट पूर्ण रहा है जो किसी भी राष्ट्र के लिये शुभ लक्षण नहीं है।

### कृषि पर प्रभाव:

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि होती है। इसी लिये कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। परन्तु वर्तमान समय में कृषि को अर्थव्यवस्था में गौड स्थान प्रदान किया जाता है जो अनुचित है। क्योंकि यदि देश को स्वावलम्बी बनना है तो कृषि को प्रधानता प्रदान करनी होगी। विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत कृषि को स्थापित करके विकसित राष्ट्रों को हानि नहीं पहुँचाया जा सकता है, परन्तु हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इससे विकासशील राष्ट्रों को लाभ भी नहीं होने वाला है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भौगोलिक सीमा के तहत अपने कृषि जन्य उत्पादों को उत्पादित करने की स्वतन्त्रता प्रकृति ने प्रदान की है और

उराकी स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए और उसपर किसी प्रकार का प्रतिबध उचित नहीं है प्रत्येक देश अपने यहां अपनी सुविधाओं एवं क्षमताओं के अनुसार कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते रहे हैं जिससे उनमें किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होती रही है। परन्तु वर्तमान समय में कृषि उत्पादों को भी पेटेन्ट के तहत लाने से कृषकों को असुविधा उत्पन्न हो सकती है। बीज पेटेन्ट करने की प्रक्रिया किसानों में आक्रोश व्याप्त कर सकती है। क्योंकि अभी तक कृषकों के द्वारा एक बार बीज खरीद कर दोबारा पैदा करके उसका विस्तार करने की प्रवृत्ति रही है जो कम खर्चीली थी परन्तु यदि इस प्रक्रिया को पेटेन्ट के तहत प्रतिबधित किया गया तो विकासशील देशों के किसान ज्यादा प्रभावित होंगे। मूल रूप से यदि भारत को देखें तो यहां का किसान निम्न या मध्यम वर्ग का है। जो कृषि पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकता उराको महंगे बीज खरीद कर बोवाई करनी पड़ी तो कृषि कार्य करने में राक्षम नहीं होगा इराके परिणाम स्वरूप मजदूर बन जाने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दूसरे महत्वपूर्ण प्राविधान के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में कृषि सहायकी को समस्त उत्पादन लागत के 10 प्रतिशत से अधिक किसी देश को न रखने का प्रावधान है।<sup>1</sup> परन्तु कुछ क्षेत्रों यथा अन्वेषण और विकास फसल रोग नियंत्रण, प्रसार रोग और अवस्थापना सृजन के लिये अधिक सहायिकी प्रदान करने की छूट है। कृषि सहायिकी

1 त्रिपाठी, डॉ० बन्नी विशाल, भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन एवं विकास, किताब महल, 1996, पृष्ठ 445

कम करने के परिणाम स्वरूप किसानों को हानि होने की सम्भावना बढ़ जाती है। क्यों कि विकाराशील देशों के किसान निम्न या मध्यम वर्ग के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे कृषि उत्पाद पर अधिक पूँजी लगा सकें। साथ ही साथ कृषि उत्पादों की लागत बढ़ने से उन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की प्रबल सम्भावना है जिसका बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता है। निम्न या मध्यम आय वाले वर्ग पर जो कृषि कार्य से सम्बन्धित नहीं है परन्तु कृषि उत्पादों पर आश्रित है।

विश्व व्यापार संगठन में तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि प्रत्येक देश को अपने 1986-88 के उपभोग-स्तर के आधार पर तीन प्रतिशत भाग आयात करना होगा। जो क्रमशः पाँच प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा।<sup>2</sup> प्रत्येक देश विश्व व्यापार संगठन के इस प्रावधान के अन्तर्गत आयात करने के लिये बाध्य होते हैं, चाहे वह एक निर्यातक या आत्मनिर्भर देश ही क्यों न हो। इससे भी विकाराशील देशों को हानि पहुँचने की सम्भावना प्रबल होती है। क्योंकि प्रत्येक विकाराशील देश कृषि उत्पादों का आयात करने की बाध्यता के तहत न चाहते हुये भी आवश्यक आयात करने के लिये अपनी मुद्रा को खर्च करेंगे। जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिये उचित नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन की यह नीति कि सभी वस्तुओं को विश्व व्यापार के तहत राचालित करना सर्वथा अनुचित होगा। वर्तमान विश्व व्यापी परिदृश्य में होने वाले परिवर्तन के

कारण भारतीय कृषि में भी बदलाव आने लगे हैं। आज भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार के लिये खोलना पड़ रहा है और उरुग्वे दौर के कारण ही भारत को भी गैट पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं। डकल प्रस्ताव के कारण भारतीय कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगे। अभी तक कृषि क्षेत्र गैट के दायरे से बाहर था। उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान यह तय किया गया कि गैट के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाये और इस के लिये सदस्य राष्ट्र अपने यहां के बाजार को खोलेंगे, आंतरिक सहायता तथा आयात को बढ़ावा देंगे। इसमें प्रगतिशील देशों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन नये तथ्यों के आने की वजह से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह से समझना होगा। वनस्पति अनुसंधान अधिकार के लागू होने के बाद से कई यूरोपीय राष्ट्र जो कि पूर्व में शुद्ध आयात करने वाले देश थे वे अब कृषि उत्पाद के शुद्ध निर्यातक हो गये हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लागू हो जाने से भारतीय कृषि के विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

गैट वार्ता में बीजों एवं पौधों के पेटेंट का जो प्राविधान दिया गया है। उससे उन भारतीय प्लांट ब्रीडर्स पर असर पड़ेगा जो कि केवल नकल करके बीजों का उत्पादन कर बाजार में बेचने का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों का मत है कि विकसित देशों में किये गये अनुसंधान के सहारे या आड में अपना धंधा चलाया जा सकता है। परन्तु इस तरह के लोग भारत में बहुत ही कम संख्या में पाये जाते हैं। इसके विपरीत



भारत में कई ऐसे प्लॉट ब्रीडर मिल जायेंगे जो कि खुद अनुसंधान द्वारा देश के वातावरण एवं मानक के अनुरूप विभिन्न स्थितियों के लिये बीज एवं पौधे विकसित कर रहे हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अब विकसित देश उच्च कीमत वाली फसलों पर ही अधिक अनुसंधान कर रहे हैं।

इन देशों द्वारा दाल तिलहन, कपास आदि पर बहुत कम अनुसंधान हो रहा है और ये ही मुख्य फसल हैं जो भारत में पैदा की जाती हैं। अतः भारतीय वैज्ञानिकों को इन पर विशेष ध्यान देना चाहिये और इन फसलों की उन्नत किस्में तैयार करनी चाहिये। साथ ही निर्यात योग्य फसल जैसे मसाले, फल, सब्जियाँ आदि की नई किस्मों के आविष्कार पर कोई रोक नहीं है। जब इन सभी की नई किस्में तैयार करके पेटेंट कराली जायेंगी तो हम भी तीसरी दुनिया के देशों को इनका निर्यात करके लाभ उठा सकते हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लागू हो जाने से उच्च श्रेणी के बीजों के दामों में वृद्धि होने की संभावना है। नई किस्मों से पैदावार में जो वृद्धि होगी उसकी तुलना में बीजों के दामों में बढ़ोत्तरी बिल्कुल नगण्य होगी। कुल उपज के अनुपात में बीजों के दामों में वृद्धि 2 से 10 प्रतिशत तक की ही होगी।

अतः बीजों के दामों में वृद्धि फसल उत्पादन ढाँचे पर अधिक असर नहीं डालेगी। भारतीय किसान काफी चतुर हैं और वे किसी भी प्रकार की नई तकनीक को

तब तक नहीं अपनाते हैं जब तक की उससे 30 प्रतिशत से अधिक का लाभ न हो। अतः नई किस्मों से बढ़ी उपज बीजों के दामों से कहीं अधिक होगी। इसमें कोई शक नहीं कि अधिकतर किसान भारत में गरीब हैं परन्तु आर्थिक लाभ की तकनीक को अपनाने से बिलकुल भी नहीं हिचकते हैं।

ट्रिप्पा के अनु० 27 के अनुसार पौधों एवं जानवरों के पेटेन्ट कराने का प्राविधान गैट में है। आने वाले साल के लिये किसान बीजों को सुरक्षित कर सकते हैं। पेटेन्ट बीजों के इस्तेमाल तथा पुनः इस्तेमाल के किसानों और ब्रीडरों के अधिकार पर कोई संकट नहीं है क्योंकि इन के बचाव के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं।

### **कृषि व्यापार पर प्रभावः**

कृषि व्यापार पर, वर्तमान गैट नियमों में, व्यापक खामिया हैं। इनका लाभ उठा कर औद्योगिक राष्ट्र अपने यहां की कृषि को सुरक्षण के लिये एक भारी आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इस प्रकार ये राष्ट्र विश्व में हो रहे उत्पादन को प्रभावित करते अन्न, डेरी उत्पादन, मांस, चीनी, खाद्यान्न तेल आदि पर प्रतिस्पर्धा के चलते आर्थिक सहायता का जो दौर चला है, उसके परिणाम स्वरूप इन उत्पादनों के मूल्यों पर कई वर्षों तक विश्व में मंदी रही और जिन राष्ट्रों में इनका व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता था वे ही सबसे अधिक प्रभावित हुये।

ऐसा प्रतीत होता है कि उरुग्वे दौर में मुख्यता औद्योगिक राष्ट्रों के कृषि व्यापार एवं उत्पादन पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। नेतृत्वविहीनता के आभाव में तीसरी दुनिया के देशों में एकता नहीं कायम हो सकी यह अत्यन्त ही खेद की बात है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने वार्ता को अपने स्वार्थ हेतु पूरे एक वर्ष तक रोके रखा। वही विकाराशील देशों ने आम मुद्दों पर भी एक जुट होने का प्रयास नहीं किया। तत्कालीन भारतीय सरकार पूरे राष्ट्र को इस बात को समझाने की कोशिश में लगी रही कि डकल प्रस्ताव के द्वारा देश का हित होगा।

भारतीय कृषि पर भविष्य में चार पहलुओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये हैं— कृषि हेतु आर्थिक सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा, बाजार की पहुँच और बौद्धिक सम्पदा अधिकार।

### कृषि पर आर्थिक सहायता :

विश्व के लगभग सभी देश अपने कृषकों को कृषि के विकास के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ओ ई सी डी राष्ट्रों में कृषि समर्थन में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और 1990 के अंत तक यह 300 बिलियन डालर पहुँच गई। किसानों को दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता जिसे इस प्रोड्यूसर सहायिकी इक्विवैलेन्ट (पी एस ई) कहते हैं 16 प्रतिशत बढ़ कर 176 बिलियन डालर हो गई जो कि फसल

एव पशुधन के कुल मूल्य का 44 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति अनुदान में अमरीका पूर्ण कालिक किसानों को प्रति वर्ष उत्पादन में 22000 डालर की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जबकि जापान 15000 डालर और यूरोपीय देश 12000 डालर करता है। अमरीका उत्पादन के प्रतिशत के हिसाब से अनाज पर 51.52 प्रतिशत सोरघम (Sorghum) पर 49.51 प्रतिशत और सोयाबीन पर 50.52 प्रतिशत आर्थिक सहायता देता है। जो विश्व भर में सबसे अधिक है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईसीसी) अपने किसानों को प्रति वर्ष 135 बिलियन डालर की आर्थिक सहायता देता है। जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.75 प्रतिशत है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर अपने किरानों को आर्थिक सहायता देने की वजह से उसने अमेरिकी कृषि उत्पादनों के निर्यात के लिये खतरे की घटी बजा दी है। साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा मास एव मास से निर्मित खाद्यान्न को कम दामों पर अमरीका को निर्यात कर रहा है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय आर्थिक समुदाय में कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी वजह कई अमरीकी उत्पादनों के आयात पर रोक है। इन्हीं कारणों की वजह से अमरीका ने उरुग्वे दौर की वार्ता में

कृषि को शामिल करने के लिये ऐडी-चोटी का जोर लगा दिया था ताकि उसके यहाँ के कृषि उत्पादन को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार में प्रवेश मिल सके।

शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि पर आर्थिक सहायता पूरी तरह से वापस लिये जाने के लिये जोर दिया। परन्तु फ्रांस द्वारा इसका पूरी तरह से विरोध किया गया।

1990 में हुई बैठक जिसके अंतर्गत आठवें दौर की वार्ता का समापन होना कृषि के कारण विफल हो गई। इसके उपरान्त आया डकल ड्राफ्ट, जिसके आधार पर भविष्य में होने वाली बातचीत की जायेगी। यद्यपि फ्रांस ने ड्राफ्ट में कृषि के लिये दिये गये प्राविधानों को तुरन्त ही नकार दिया परन्तु वह इस बात के लिये तैयार हो गया कि कृषि के लिये व्यापक सुधार नीति तैयार की जाये। एक समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि आने वाले छ वर्षों में कुछ तरह की कृषि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 20 प्रतिशत की और निर्यात पर आर्थिक सहायता में 36 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

जहाँ तक विकासशील देशों का सवाल है तो उनके लिये यह प्राविधान रखा गया कि अगर कृषि उत्पादन का मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक होता है तो वे आर्थिक सहायता में कटौती करेंगे। भारत सरकार के अनुसार मौजूदा आर्थिक सहायता गैट

द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है और सहायता में कमी के लिये गैट द्वारा कोई दबाव नहीं है।

जिन 15 फसलों पर भारत आर्थिक सहायता प्रदान करता है। उन में से 12 में नमारात्मक और 3 फसल—मूंगफली, गन्ना तथा तम्बाकू में यह सकारात्मक है, परन्तु 10 प्रतिशत से कम है। उत्पादन के कुल मूल्य का एन पी एस (NPS) 6 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन अभी भी आर्थिक सहायता के मूल्यांकन को लेकर काफी भ्रम बना हुआ है। इस बात का डर है कि यदि मूल्यांकन में जरा सी भी हेर फेर हुआ तो भारत द्वारा दी जाने वाली कृषि पर आर्थिक सहायता 10 प्रतिशत के ऊपर पहुँच जायेगी।

डकल प्रस्ताव के अनुसार सभी सदस्य देशों को चाहिये कि वे कृषि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों में कमी लायें। हमारे यहाँ परिणामात्मक प्रतिबंध इस लिये लगाये जाते हैं। ताकि आयात एवं निर्यात पर नियंत्रण रखा जा सके और बदली हुई परिस्थिति में इनके स्थान पर शुल्क एवं प्रशुल्क लगाया जा सके और ऐसी मान्यता है कि बहुराष्ट्रीय निगमित जगत भारतीय बीज बाजार पर कब्जा जमा लेगा, परन्तु यह किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। इस सदर्भ में पाइनियर सीड्स, कारगिल सीड्स तथा सेनडोल सीड्स की चर्चा की जा सकती है। ये कम्पनियाँ कई वर्षों से हमारे यहाँ कार्यरत हैं परन्तु अभी तक भारतीय बीज बाजार में ये अपनी पैठ नहीं बैठा सकी हैं।

कृषि क्षेत्र में लाभ के अतिरिक्त गैट समझौते के तहत भारतीय वैज्ञानिकों को भी बहुत फायदा होगा। इसमें कृषि वैज्ञानिक शामिल हैं। इन लोगों को विकसित देशों में अल्प कालीन सेवा हेतु बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। अमेरिका तथा विश्व व्यापार के प्रमुख राष्ट्रों के एक तरफा तरीकों पर पाबंदी लगेगी। धारा 301 अमेरिकी नियमावली में जरूर रहेगी। परन्तु उपयोग उन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है जो कि आठवें दौर के गैट समझौते के अंतर्गत आते हैं।

इस समझौते में दिये गये उपनियमों से संबंधित कोई भी विवाद बहुस्तरीय विवाद निस्तारण प्रक्रिया के तहत ही किया जायेगा। सभी सदस्य राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे बदले हुए परिदृश्य में मुनाफे में बढ़ोत्तरी के लिये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को अपनायेंगे। यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन गैट वार्ता भारतीय कृषि को विश्वव्यापी बनाने में काफी मदद करेगी। साथ ही कृषि को सभी तरह की कृत्रिम रूकावटों से भी निजात मिल जायेगी इसके कारण न केवल कृषि आय में वृद्धि होगी बल्कि कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। अब जरूरी हो गया है कि आठवें दौर की गैट वार्ता को सही परिदृश्य में राजनीति से हटकर लागू किया जाये और एक जुट होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये।

भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार डकल प्रस्ताव में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। परन्तु तौलने पर सकारात्मक बिन्दु नकारात्मक बिन्दुओं पर भारी

पड़ते हैं। कृषि पर डकल प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का सही आकलन तभी हो सकता है जब हम लाभ एवं हानि बिन्दुओं पर विचार कर लें।

### सकारात्मक प्रभाव :

- 1 गैट के अंतर्गत कृषि पर भी कुछ बंधन लागू होंगे—बाजार में प्रवेश, राष्ट्रीय समर्थन तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा।
- 2 विकासशील देशों में कृषि पर निवेश सहायता तथा गरीब किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को राष्ट्रीय समर्थन कटौती से बाहर रखा गया है।
- 3 उन विकासशील देशों में जहाँ कुल समर्थन स्तर व्यक्तिगत उत्पादों का कुल 10 प्रतिशत हो वे खास—उत्पाद समर्थन में कटौती के लिये बाध्य नहीं हैं।
- 4 सीमा शुल्क में 36 प्रतिशत की कटौती की जायेगी जो कि प्रत्येक टैरिफ लाइन का न्यूनतम 15 प्रतिशत होगा।
- 5 सभी बजट प्रस्तावों पर निर्यात सहायता में 36 प्रतिशत तक की छूट होगी और सभी मात्रा में 24 प्रतिशत की छूट विकासशील देशों के लिये यह 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत होगी जो कि सन् 2005 तक पूरी तरह से लागू हो जायेगी।



- 6 राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन में 20 प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी। जिन विकासशील देशों के यहाँ बकाया धन देय में कोई समस्या है उनके लिये सीमा शुल्क टैरिफ सीलिंग की कोई भी बाधता नहीं है।
- 7 विकासशील देशों को आयात के प्रतिपक्ष में सेनेटरी एव फाइटो-सेनेटरी उपायों पर विशेष ध्यान देना होगा।

### नकारात्मक :

- 1 कृषि पर आर्थिक सहायता केवल गरीब किसानों के लिये ही सीमित होगी।
- 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) द्वारा दी जाने वाली सहायता पोषण के मानक के आधार पर तैयार की जायेगी।
- 3 क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली धनराशि और जुड़ी हुई आय सहायता पर की गई कटौती के वादे पर छूट। इसका लाभ यूरोपीय समुदाय उठा सकता है।
- 4 यदि खारा उत्पाद 10 प्रतिशत से अधिक है तो विकासशील देशों को सन् 2005 तक राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाने वाले समर्थन पर 13 प्रतिशत की कटौती करनी होगी।

- 5 खाद्यान्न की खरीद सरकार द्वारा तत्कालीन बाजार दामों पर की जायेगी ।
- 6 तत्कालीन प्रवेश और न्यूनतम प्रवेश सबंधी जरूरतों के बारे में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है ।

बीज पेटेन्टीकरण के पश्चात् कृषि सहायिकी समाप्त करने की प्रक्रिया का प्रावधान विश्व व्यापार संगठन में प्राविधिक किया गया है । जो विकासशील राष्ट्रों के किसानों के लिये बहुत ही हानिप्रद सिद्ध हो रहा है । अभी तक विकासशील देशों की सरकारों के द्वारा कृषि उत्पादों में सहायक रसायनों (खाद) पर सहायिकी प्रदान की जाती थी । परन्तु अब विश्व व्यापार संगठन के सदस्य विकासशील देश इसको समाप्त कर रहे हैं । यदि भारत के सदस्य में दृष्टि डालें तो सहायिकी कम करने की वजह कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले रासायनों का मूल्य बड़ी तेजी से वृद्धि की ओर उन्मुख हुआ है ।

### **कृषि पर प्रभाव :**

डकल प्रस्ताव और बौद्धिक अधिकार सम्पदा से भारतीय किसानों में काफी रागरमी है । ऐसा माना जा रहा है कि उदारीकरण की नीति तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के आने से भारतीय कृषि विशेषकर बीजों, उर्वरकों तथा पौधों की दवाइयों पर दूरगामी असर पड़ेगा । डकल प्रस्ताव के अनुसार जो भी पौधे एवं जानवरों की किस्में विदेशों में

इजात की जायेगी उनको विदेशी कपनिया पेटेन्ट करा सकती है तथा उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त होगा कि वे पेटेन्ट अधिकार देने से इनकार कर दे ।

अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को पूरी छूट थी कि वे विश्व में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं । परन्तु डकल प्रस्ताव और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लागू हो जाने के बाद में ऐसा करना सम्भव नहीं होगा । यह कदम भारतीय कृषि के लिए आत्मघाती है क्योंकि अब हम अपनी जरूरत के अनुसार फसलों की किस्मों को तैयार नहीं कर सकते हैं । मुख्य फसलों की नई किस्में तभी तैयार की जा सकती हैं जब हम बदली हुई परिस्थितियों में मिट्टी, पानी एवं वातावरण को ध्यान में रखें । यह बहुत ही आवश्यक है कि यदि हमें अपनी कृषि को जीवित रखना है तो यह तभी सम्भव है जब हमें अपनी आवश्यकता अनुसार जीन उपलब्ध हो । अभी तक यह सहूलियत हमारे पास मुफ्त में उपलब्ध थी ।

बहुराष्ट्रीय निगमों के पास आर्थिक ससाधनों की कोई कमी नहीं होती है ऐसी स्थिति में वे पेटेन्टों को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं और फिर बीजों के उत्पादन एवं वितरण पर अपना एकाधिकार जमा लेंगे । पेटेन्ट अधिकार को देने से इनकार वाले उपनियम की वजह से भारतीय कृषि और किसान उन विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हो जायेगी जिनके पास अधिकतर फसलों की नई किस्मों के जीन हैं ।

यदि यह प्रस्ताव मान लिये गये तो ये भारतीय कृषि को दो प्रकार से हानि पहुँचा सकते हैं।

- 1      बहुराष्ट्रीय निगम के पास अधिकतर बीजों के उत्पादन के अधिकार होने की वजह से हमारी खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में आजायेगी। यह बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि युद्ध के लिये विदेशी अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर होना पड़े।
- 2      बीजों के मूल्य बहुत अधिक होंगे जो कि हमारे यहाँ के लाखों गरीब और छोटे किसानों, जिनका प्रतिशत लगभग 76 है, उनकी पहुँच से परे रहेंगे।

बीजों की तरह से उर्वरकों और कीटनाशकों पर भी ऐसा ही असर होगा क्योंकि इन पर भी बहुराष्ट्रीय निगमों का अधिकार जमा है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि डकल रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाये। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हम विश्व व्यापार में पूर्णतः अकेले पड़ जायेंगे। इसके लिये आवश्यक है कि हम खारा मुद्दों पर छूट के लिए वार्ता करें साथ ही जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना करने के लायक नहीं हो जाते तब तक हमें समुचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। अतः अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के लिये इस विषय पर और वार्ता की जरूरत है।

## उद्योग पर प्रभाव:

डकल प्रस्ताव व विश्व व्यापार सगठन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव । केवल कृषि एवं व्यापार पर ही पड़ेगे बल्कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों पर भी पड़ेगा । जहां तक उद्योगों का प्रश्न है अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किस दिशा में प्रभावित करेगा परन्तु इतना अवश्य ही है कि विकासशील देशों के पटल पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा । सच कहा जाये तो वास्तविक रूप से डकल प्रस्ताव एवं आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया व भू-मण्डलीकरण उद्योगों के कारण ही है । 1980 के दशक में अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों में अवसाद के लक्षण दिखाई पड़े थे जिसके कारण उद्योगों में स्थिरता तथा बेरोजगारी की समस्या का खतरा पैदा हो गया था । इस समस्या से निपटने के लिये विकासशील देशों के बाजार को प्राप्त करना एवं यूरोपीय (विशेषकर ओ ई सी डी ) देशों के उद्योगों का विकास करना था । जिसके तहत डकल प्रस्ताव की रूपरेखा निर्मित की गयी और विभाजन तक की यात्रा तय की गयी है ।

विकासशील देशों में यूरोपीय उद्योगों एवं पूंजी निवेश को बढ़ावा देना इस प्रक्रिया में सम्मिलित है । उदारीकरण, एम आर टी पी अधिनियम फेरा में छूट बहुराष्ट्रीय निगमों एवं कम्पनियों के साथ नरम रवैया अपनाकर विकासशील एवं भारत जैसे देशों में विदेशी उद्योगों के द्वार खोलना है । जिससे विकासशील देशों एवं भारत के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और होंगे । भारत का न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र भी एक निश्चित समय एवं सीमा के बाद प्रभावित होगा ।

भारत के दो महत्वपूर्ण एव परम्परागत उद्योग कपड़ा तथा जूट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और वर्ष 2003 के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा, परन्तु अभी कपड़ा एव परिधान उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।

डकल प्रस्ताव के द्वारा कपड़ा उद्योग को वर्तमान विश्व व्यापार सगठन के नियमों के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है। यह प्रस्ताव 10 वर्षों की सक्रमण अवधि में बहुतन्तु व्यवस्था को समाप्त करके विश्व व्यापार में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना है। भारत तथा अन्य देशों के अनुरोध पर ही इस समय अवधि को घटाकर 15 वर्ष से कम करके 10 वर्ष कर दिया गया। भारत से सर्वाधिक मात्रा में कपड़ा एव पोशाक का निर्यात अमेरिका एव यूरोपीय समुदाय के देशों को किया जाता है। इन बाजारों में भारतीय वस्त्रों की अच्छी मांग है वस्तु निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध लगा रखा है। जिसके कारण भारत इन बाजारों में कहीं कम मात्रा में कपड़ा बेच पाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत अपने वस्त्रों एव पोशाकों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि कर सकता है।

विश्व व्यापार सगठन जो वर्तमान में गैट का प्रतिनिधित्व करते हुए डकल प्रस्तावों को कार्यरूप प्रदान कर रहा है का प्रभाव विभिन्न तीन चरणों में 343 के अनुपात में विदेशी प्रतिबन्धों को सन् 2003 तक समाप्त करने के पश्चात् ही भारतीय वस्तु उद्योग को विश्व बाजार में अपनी दक्षता को सिद्ध करने का पूर्ण अवसर प्रदान हो

राकेगा। भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर हम यह मत व्यक्त कर सकते हैं कि भारतीय वस्तु उद्योग विभिन्न देशों में मुक्त व्यापार नीति के तहत अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने में सक्षम हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन भविष्य में सफलता अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करने में सक्षम होगा इसी प्रकार डकल प्रस्ताव एवं उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के परम्परागत निर्यातक उद्योगों की श्रृंखला में जूट उद्योग भी प्रभावित हुआ है। यद्यपि वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1995-96 में वृद्धि हुई है। परन्तु विश्व बाजार में डब्लू टी ओ के तहत जूट को लाभ की संभावनाएँ कम ही नजर आती हैं।

परन्तु समग्र रूप से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि विकासशील देशों एवं भारत के उद्योगों पर उसका प्रभाव सकारात्मक दिशा में पड़ेगा या नकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। कोटा पद्धति एवं उदारीकरण से निश्चित रूप से संगठित उद्योगों का विकास तो होगा, भले ही वे विदेशी पूँजी एवं राहस का परिचय दें। निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय औद्योगिक पटल पर विदेशी पूँजी का आगमन तेजी से हो रहा है जो औद्योगिक विकास को प्रभावित कर रहा है।

### **सेवा क्षेत्र पर प्रभाव :**

आधुनिक समय में किसी भी अर्थव्यवस्था में सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्थाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में

क्रांति पैदा कर दी है। सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से परिवहन, ऊर्जा, संचार, यातायात, बैंकिंग, बीमा एवं सलाहकारी सेवाएँ आदि सम्मिलित की जाती हैं। आज विकासशील देशों के सेवा क्षेत्र में विदेशी सेवाओं का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम के यूरोपीय देशों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भागीदारी प्रारम्भ कर दी है। संचार, परिवहन, बैंकिंग एवं ऊर्जा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की न केवल सलाहकारी सेवाएँ उपलब्ध हैं बल्कि पूँजी निवेश एवं उनके संचालन में भी भागीदारी अदा कर रही है।

यदि वर्ष 1990-91 के बाद की स्थिति का लेखा जोखा लिया जाये तो निष्कर्ष यही निकलता है कि डकल प्रस्ताव एवं विश्व व्यापार संगठन के आ जाने के बाद इस क्षेत्र का प्रचार एवं प्रसार तथा जनता को प्रदान की जा रही सेवा में सुधार हुए हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में दूर संचार एवं ऊर्जा के क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत अधिक सुधार परिलक्षित हुए हैं। निश्चय रूप से इस नयी विश्व व्यापार व्यवस्था के माध्यम से आधुनिक एवं सुधरी हुई उचित मूल्य पर सेवाएँ उपलब्ध होंगी। जहाँ तक बैंकिंग एवं बीमा का प्रश्न है इन सेवाओं का विस्तार एवं सुधार विकासशील देशों में अधिक तेजी से हो रहा है।

विकासशील देशों ने माग की है कि उनके बाजार में जो विकसित देश बैंकिंग, इन्श्योरेंस और अन्य सेवाओं के लिये मुक्त प्रवेश चाहते हैं उसके बदले में उन्हें अपने



यह विकसशील देशों की श्रम सेवाओं के लिये मुक्त प्रवेश प्रदान करना होगा। यह मुद्रा गेट में नहीं शामिल किया गया। गेट में यह भी कहा गया है कि विकसित देशों को विकसशील देशों के लिये सेवा क्षेत्र में और अधिक सूचना प्रदान करनी चाहिये। यह कहा जा सकता है कि गैट्स के अतर्गत सेवा व्यापार को वस्तु व्यापार के समकक्ष लाना है ताकि सेवाएँ राष्ट्रीय नीति प्रशासन के दायरे से बाहर आ सकें। राष्ट्रों को इस बात की स्वीकृति है कि वे अपनी अनुसूची में उन्हीं सेवाओं को शामिल करें जिन्हें वे खोलना चाहते हैं।

भारतीय रोवाएँ क्या विश्व व्यापार संगठन से प्रभावित हुई हैं? इस विन्दु पर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है कि मुक्त व्यापार नीति के तहत इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। परन्तु वर्तमान समय में अभी तक इन सेवाओं पर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। परन्तु एक नजर इस सेवाओं पर डाल कर निरीक्षण कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

सर्व प्रथम भारतीय रेल सेवा का उदाहरण है जिसका व्यय एव आगम लगातार बढ़ रहा है। इसलिये रेल सेवाओं में उदारीकरण एव विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव सकारात्मक ही पड़ा है। सन् 1990-91 में कुल सकल यातायात प्रक्रिया 12096 करोड़ रुपये की रही वहीं कुल कार्यचालन व्यय 11154 करोड़ रूपया रहा।<sup>3</sup> जबकि सन्

1996-97 में कुल कल सकल प्राप्ति 24319 करोड़ रुपये की रही और सकल कार्यचालन व्यय 21001 करोड़ रुपये का रहा। इस उद्योग पर विश्व व्यापार संगठन का कोई अरार स्पष्ट रूप में अभी सामने आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है परन्तु हम यह कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अभी पूर्ण नियमों का कड़ाई से अनुपालन नहीं हुआ है और इन नियमों का यदि पूर्ण अनुपालन हुआ तो अवश्य ही प्रभावित होगा।

(206)

## तालिका\*

सेवाओं पर परिव्यय केन्द्र, राज्य एवं संघशासित प्रदेशों का आठवीं पंचवर्षीय योजना में

(करोड़ रुपये)

| सेवा क्षेत्र                     | 1992-93  | 1993-94  | 1994-95  | 1995-96  | 1996-97  | 1997-98  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I ऊर्जा                          | 20289 80 | 26909 00 | 27482 00 | 30067 00 | 29615 30 | 24234 50 |
| (क) विद्युत                      | 12157 40 | 14773 10 | 1636 40  | 17135 00 | 16532 40 | 8078 90  |
| (ख) पेट्रोलियम                   | 5698 50  | 9589 30  | 8643 60  | 10619 00 | 10528 30 | 12383 60 |
| (ग) कोयला और लिग्नाइट            | 2276 50  | 2293 10  | 2238 70  | 1853 00  | 1932 10  | 3142 60  |
| (घ) ऊर्जा के गैर परम्परागत ससाधन | 157 40   | 253 50   | 253 30   | 460 00   | 622 50   | 629 40   |
| II परिवहन                        | 10662 70 | 11976 70 | 12096 60 | 15921 00 | 18895 90 | 15016 00 |
| (क) रेलवे                        | 6162 00  | 5901 00  | 5472 00  | 7500 00  | 8300 00  | 8300 00  |
| (ख) अन्य                         | 4500 70  | 6075 70  | 6624 60  | 8421 00  | 10595 90 | 6716 00  |
| III संचार सेवाएँ                 | 5150 90  | 6201 60  | 7273 80  | 9778 70  | 10077 40 | 13361 00 |

|                             |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IV सामाजिक सेवाए            | 11322 80 | 14016 60 | 17409 20 | 23237 70 | 27864 80 | 15707 00 |
| (क) शिक्षा                  | 2619 40  | 3147 30  | 3940 00  | 6123 10  | 7346 10  | 4157 90  |
| (ख) चिकित्सा व जन स्वास्थ्य | 1213 90  | 1300 40  | 1625 90  | 2010 20  | 2600 20  | 954 80   |
| (ग) परिवार कल्याण           | 1008 10  | 1312 60  | 1684 90  | 1506 00  | 1547 00  | 1829 30  |
| (घ) आवास                    | 650 60   | 1291 50  | 1055 60  | 1974 70  | 3285 80  | 2150 60  |
| (ङ) शहरी विकास              | 791 30   | 855 80   | 1025 20  | 1797 70  | 2330 00  | 1073 00  |
| (च) अन्य सामाजिक सेवाये     | 5039 50  | 6109 00  | 8077 60  | 9826 00  | 10755 70 | 5541 40  |
| V सामान्य सेवाए             | 266 00   | 462 60   | 651 10   | 1132 80  | 1263 70  | 277 60   |

\* स्रोत : भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 1997-98 पृष्ठ S-46

सेवा क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात परिव्ययो में वृद्धि हुई जो स्थिति के सुधार का द्योतक है जहां ऊर्जा क्षेत्र में सन् 1992-93 से लगातार अपने परिव्यय में वृद्धि करके बेहतर सेवाये प्रदान करती हुई प्रगति की ओर अग्रसर है इसे कुछ सीमा तक उदारीकरण का परिणाम कहा जा सकता है। इसी प्रकार संचार सेवाओं में परिव्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसमें उदारीकरण एवं विश्व व्यापार संगठन के लागू होने के बाद से सुधार भी परिलक्षित हुए हैं संचार सेवाये निरन्तर बेहतर सुविधाये प्रदान करने की कोशिश में अधिक सफलता भी प्राप्त कर रही है।

इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात इसमें निरन्तर वृद्धिमान गति से परिव्यय हुआ है। जहां सन् 1992-93 में कुल सामाजिक सेवाओं पर व्यय 113228 करोड़ रुपये का हुआ वहीं सन् 1996-97 में बढ़कर 2786480 करोड़ रुपये हो गया परन्तु अन्य सेवाओं की भांति यह भी आर्थिक मंदी से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सका और 1997-98 में घटकर 15707 करोड़ रुपये रह गया।

सामान्य सेवाये भी उदारीकरण प्रक्रिया के बाद की स्थिति निरन्तर वृद्धि की रही परिव्यय में परन्तु 1996-97 इसकी भी स्थिति सामाजिक सेवा की भांति कम होने की रही जैसा की तालिका में दिखाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि उदारीकरण लागू होने के बाद सेवाएं अपनी सेवाओं को सुविधा परक बनाने के प्रयास किये परन्तु आर्थिक

मदी के दौर का सामना करने में सक्षम नहीं प्रतीत होती है। केवल संचार सेवा ही अदम्य साहस के साथ अपनी स्थिति सुधारे हुए अपने व्ययों में वृद्धि जारी रख सका है।

## व्यापार पर प्रभाव

भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में जहाँ पूर्व में आयातक देश रहा वहीं आज विगत कई वर्षों से निर्यातक देश बन गया है। भारतीय निर्यात की चर्चा वर्तमान में जब होती है तो इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि खाद्यान्न की चर्चा हो। भारतीय लोग सन् 1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन मात्र 5.08 करोड़ टन करते थे वहीं आज 20 करोड़ टन कर रहे हैं।<sup>4</sup>

विश्व व्यापार में फल एवं सब्जी के निर्यात में भारत का भाग मात्र 1 प्रतिशत है जबकि संसार का 65 प्रतिशत अदरक, 75 प्रतिशत हल्दी एवं 40 प्रतिशत काजू भारत में पैदा होता है। इसी प्रकार फूलों के व्यापार की संभावनाएँ विश्व बाजार में असीमित हो रही हैं और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। भारत के द्वारा इस समय फूलों के निर्यात के द्वारा एक अरब रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा रही है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर पुष्प उत्पादक क्षेत्र को 34 हजार हेक्टेयर करने और नौवीं योजना के अन्त तक निर्यात को बढ़ा कर 48 अरब रुपये प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है।

## तालिका \*

| क्रम<br>संख्या | वस्तुएं                    | 1991-92     | 1996-97 | 2000 (लक्ष्य) |
|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|
| 1              | फल                         | 187         | 355     | उपलब्ध नहीं   |
| 2              | सब्जिया                    | 206         | 415     | 552           |
| 3              | काजू                       | 669         | 1096    | 1658          |
| 4              | मसाले                      | 170         | 272     | उपलब्ध नहीं   |
| 5              | मशरूम                      | 11          | 17      | 32            |
| 6              | फूल                        | 12          | 100     | 200           |
| 7              | सरक्षित पौध                | उपलब्ध नहीं | 15      | 30            |
| 8              | प्रसस्कृत फल<br>एव सब्जिया | 100         | 375     | 656           |

\* स्रोत भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, योजना मई 1998 अंक 2

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट दिखाई पड रहा है कि बागवानी क्षेत्र में भारत सन् 1950-51 की तुलना में निरंतर वृद्धि और अग्रसर रहा है निर्यात के क्षेत्र में यदि डकल के प्रभाव के रूप में हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा की सन् 1991 में की गई उदारीकरण प्रक्रिया इन क्षेत्रों को प्रभावित करती है जो डकल प्रस्ताव को ध्यान में रखकर मुक्त व्यापार नीति को अपनाने की ओर अग्रसर रही ।

बागवानी उत्पादों में जहाँ फलों एवं सब्जियों के निर्यात में वृद्धि 1991-92 की तुलना में 1996-97 में लगभग दो गुने की हुई वहीं काजू के निर्यात में वृद्धि दो गुने से कम रही परन्तु इसके निर्यात में भी 427 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो सफलतम वृद्धि कही जा सकती है भारत जैसे देश के लिये जहाँ की आवादी विश्व में दूसरे स्थान पर है। मराले में भी वृद्धि 198 करोड़ रुपये की निर्यात में रही। मशरूम के निर्यात में 6 करोड़ रुपये की रही है।

फूल के निर्यात में वृद्धि विगत 6 वर्षों में 8 गुने ज्यादा की रही सन् 1990-91 में जहाँ मात्र 12 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ वहीं 1996-97 में 100 करोड़ रुपये का रहा। प्रसरकृत एवं सब्जियों के निर्यात में भी लगभग चार गुने की वृद्धि हुई सन् 1990-91 में की तुलना में 1996-97 में 275 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त तालिका के द्वारा यदि हम सन् 2000 तक लक्ष्य को ध्यान में रखकर विश्लेषण करें तो इन्हें प्राप्त करने वाले लक्ष्य की सज़ा दी जा सकती है। अभी तक की वृद्धि को देखने के उपरान्त यही लगता है कि लक्ष्य पा लिया जायेगा।

मुक्त व्यापार नीति का बागवानी क्षेत्रों के विकास एवं उसको निर्यातोन्मुखी बनाने में सहायक प्रतीत होती है। इस समय जब डकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन अपने कार्यरूप में सन् 1995 जनवरी से है तो इसके विकास की और



भी सभावनाये बनेगी। अभी तक वस्तुओं के निर्यात में तमाम प्रकार की बाधाएँ जैसे लाइसेन्स प्रणाली का गूढ़ होना तथा आयातित दश के द्वारा तटकर आदि लगाये जाने से व्यापार कठिन हो जाता था परन्तु मुक्त व्यापार नीति की ओर अग्रसर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को बागवानी क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात में ओर अधिक सफलता मिलने की सभावनाएँ हैं।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का भविष्य में बागवानी क्षेत्र में लाभ होगा विश्व व्यापार संगठन के कार्य रूप में आने के परिणाम स्वरूप गेट, डकल प्रस्ताव एवं विश्व व्यापार का न केवल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग कृषि पर ही प्रभाव पड़ेगा। जिराका विवरण आगे दिया जा रहा है।

### तालिका व्यापार शेष\*

(मिलियन अमरीकी डालर)

| वर्ष                | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| निर्यात             | 18477   | 18266   | 18669   | 22683   | 26855   | 32311   | 23764   |
| आयात                | 27915   | 21064   | 24316   | 26739   | 25904   | 43670   | 48063   |
| निर्यात एवं<br>आयात | &9438   | &2798   | &5447   | &4056   | &9049   | &11359  | &14296  |

\* स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा, -1997 पृष्ठ 77

उपर्युक्त तालिका के द्वारा हम निर्यात को देखे तो यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं। कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप निर्यात में विशेष लाभ की स्थिति नहीं रही। यह शुरू के वर्षों में स्थिरता की स्थिति में रहा और सन् 1993 एवं 1994 में वृद्धिमान प्रवृत्ति पायी गयी तथा 1995 में वृद्धि दर अधिक और भारतीय निर्यात बढ़कर 32311 अमरीकी मिलियन डालर हो गया जो अब तक के वर्षों सर्वाधिक रहा परन्तु 1996-97 में घटकर 23764 अमरीकी मिलियन डालर रह गया इसी प्रकार उक्त तालिका के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप आयात की स्थिति उदारीकरण के शुरू के वर्षों में कम होकर स्थिर गति से वृद्धिमान रही परन्तु विश्व व्यापार संगठन के लागू होने के पश्चात सन् 1995 में वृद्धि हुई और बढ़कर 436 70 अमरीकी मिलियन डालर हो गई। इसके पश्चात सन् 1996-97 में बढ़कर 48063 अमरीकी मिलियन डालर तक पहुँच गई।

यदि हम तालिका के द्वारा यह देखे कि आयात-निर्यात में विगत वर्षों में स्थिति क्या रही तो हम पाते हैं कि निर्यात में 1996 में कमी हुई है और सभी वर्षों में बढ़ोत्तरी हुई है और आयात में 1991 में कमी हुई है। परन्तु आयात में भी निर्यात की तुलना में वृद्धिदर तीव्र रही।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि भारत का आयात-निर्यात का व्यापार शेष सदैव ऋणात्मक बना हुआ है परन्तु सन् 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद

इसमें सुधार दिखाई पड़ता है जहाँ सन् 1990 में भारत का भुगतान 9438 मिलियन अमरीकी डालर ऋणात्मक था उसमें कमी होकर सन् 1991 में मात्र 2792 मिलियन अमरीकी डालर ऋणात्मक रह गया। परन्तु सन् 1992-93 में तथा 1993-94 में वृद्धि के साथ उतार चढ़ाव की स्थिति रही। उसके बाद के वर्षों में वृद्धि दर अधिक रही और बढ़कर दोगुनी पहुँच गयी।

इस तालिका से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उदारीकरण प्रक्रिया का तो तत्कालीन लाभ व्यापार असंतुलन की स्थिति कम करने पर रहा परन्तु दीर्घकाल में इसका विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यदि इस तालिका से हम देखें कि 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और उदारीकरण प्रक्रिया इसी परिपेक्ष्य में लागू करने का प्रयास रहा तो हम यह कह सकते हैं कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापार असंतुलन में अल्प कालीन कमी तो आयी परन्तु विश्व व्यापार संगठन के कार्य रूप ग्रहण करने के उपरान्त व्यापार असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के लागू होने के पूर्व तो उतार चढ़ाव हुए हैं परन्तु सन् 1995 एवं सन् 1996 में वृद्धि जारी रही।

किसी भी देश के लिये व्यापार असंतुलन की स्थिति अशुभ मानी जाती है यदि यह स्थिति ज्यादा समय तक रहती है तो वह बहुत ही विनाशकारी स्थिति पैदा कर सकती है। भारत का व्यापार संतुलन विगत वर्षों में ऋणात्मक बना हुआ है जो बहुत ही

मिन्ता का विषय है। हम यह कह सकते हैं कि जब विश्व व्यापार संगठन के तहत मुक्त व्यापार नीति को अपना लिया गया है तो अपने निर्यात को बढ़ाया जाय और इस विनाशकारी स्थिति से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर स्थिति को सुदृढ़ किया जाये।

### तालिका \* कुल निर्यात में कृषि उत्पादों के निर्यात

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष    | देश का कुल निर्यात | कृषि उत्पादों का निर्यात | प्रतिशत हिस्सा (भारत) |
|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1992-93 | 53688              | 7884                     | 14.7                  |
| 1993-94 | 69751              | 10811                    | 15.5                  |
| 1994-95 | 82674              | 11051                    | 13.4                  |
| 1995-96 | 106353             | 17496                    | 16.5                  |
| 1996-97 | 118817             | 21021                    | 17.7                  |

\* स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा, 1997-98, पृष्ठ 198

उपर्युक्त तालिका में देश के द्वारा निर्यात में उदारीकरण के पश्चात लगातार वृद्धि हुई है जहाँ भारत के द्वारा 1992-93 में कुल निर्यात 53688 करोड़ था वहीं सन् 1995-96 में 106353 करोड़ रुपये बढ़कर हो गया। यहाँ वृद्धि सन् 1992-93 की तुलना में लगभग 2 गुनी हुई। सन् 1996-97 में वृद्धि जारी है।

यदि डकल प्रभाव के उदारीकरण के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामों के प्रतिफल के रूप में इसे हम देखें तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उदारीकरण प्रक्रिया का प्रभाव देश के निर्यात पर धनात्मक रहा है यदि विश्व व्यापार संगठन के लागू होने और उसके बाद के वर्षों को देखें तो हमें वृद्धि ही दिखाई पड़ती है जो भारतीय निर्यात के लिये शुभ लक्षण है।

भारतीय निर्यात में कृषि जन्य वस्तुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिये बिना कृषि जन्य वस्तुओं के निर्यात के विश्लेषण से यह पूर्ण नहीं होगा। सन् 1992-93 में कृषि जन्य वस्तुओं का निर्माण 7884 करोड़ रुपये था वहीं सन् 1995-96 में 17496 करोड़ रुपये बढ़कर हो गया और सन् 1996-97 में 21021 करोड़ रुपये कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया कृषि उत्पादों का 92-93 में देश के कुल निर्यात का हिस्सा 14.7 प्रतिशत था वहीं सन् 1996-97 में बढ़कर 17.7 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ देश के द्वारा किया जाने वाले निर्यात में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है।

कृषि उत्पादों के निर्यात को हम विश्व व्यापार में हम देखें तो भारत का हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति कृषि उत्पादों के निर्यात में विश्व परिदृश्य में अच्छी है। परन्तु वर्तमान विश्व व्यापार में हमें

और प्रयास करने चाहिये अपने कृषि जन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये उत्पादन वृद्धि को बढ़ावा देकर।

### तालिका —\* उर्वरक आयात एवं आर्थिक सहायता

| वर्ष    | आयात (हजार मीटर टन) | आर्थिक सहायता<br>(करोड़ रुपये में) |
|---------|---------------------|------------------------------------|
| 1990—91 | 2758                | 659                                |
| 1995—96 | 4008                | 1935                               |
| 1996—97 | 2014                | 1350                               |
| 1997—98 | 3246                | 826                                |

\* स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा, 1997—98 पृष्ठ 120

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय उर्वरक उद्योग अभी अपने देश की उर्वरक शक्ति की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप हमें विदेशों से उर्वरक रासायनों की आपूर्ति करनी पड़ती है। यह रासायन काफी महंगे होते हैं और भारतीय किसानों के क्रय करने की क्षमता के बाहर की स्थिति होती है। जिसके लिये सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में डकल प्रस्ताव के कारण उदारीकरण प्रक्रिया के उपरान्त की स्थिति यह रही कि आर्थिक सहायता में कमी की जाये जिसका परिणाम यह हो रहा है कि भारतीय कृषकों को अधिक व्यय करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आयात किये जाने वाले रासायनो के परिव्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व व्यापार सगठन को स्थापित किये जाने के बाद उर्वरक रासायनो के आयात में कमी हुई और सन् 1996-97 में मात्र 2000 मीटरटन ही आयात हुआ।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यदि हम आर्थिक सहायता के विषय वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करें तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार विश्व व्यापार सगठन के नियमों के तहत इसको पूर्ण समाप्त करने की कोशिश जारी रखे हुए है और सन् 1997-98 में इसको कम करके 826 करोड़ रुपये का अनुमान है जो सन् 1995-96 के आधे से भी कम रकम है।

## ट्रिप्स समझौते को लागू करना:

### भारत के समक्ष नीति विकल्प :

ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार सगठन समझौते का एक प्रमुख हिस्सा है जिसे 117 राष्ट्रों ने स्वीकारा है। उरुग्वे दौर की वार्ता के उपरांत विश्व व्यापार सगठन पर हस्ताक्षर किये गये। व्यापार वार्ताओं के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब इस दौर की वार्ता के परिणाम को एक ही बार में पूर्णता स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। अपनी स्वेच्छा से समझौतों और प्राविधानों को चुनने का अधिकार सदस्यों को नहीं

दिया गया। साथ ही प्रथम बार उरुग्वे दौर से उत्पन्न सभी समझौते सभी विकासशील देशों पर लागू होंगे। इन राष्ट्रों को दी गई कोई विशेष छूट लम्बे परिवर्तन अवधि के लिये है। जैसे –कुछ प्राविधानों के अनुपालन अवधि में विलम्ब ट्रिप्स समझौते के प्राविधानों के साथ भी ऐसा ही है। वहाँ ये सभी देशों पर लागू होते हैं पर अल्प विकसित देशों के लिये विकासशील देशों की अपेक्षा लम्बे विलम्ब की छूट का प्राविधान किया गया है।

ट्रिप्स समझौते ने भारत में काफी उथल पुथल कर दी है और इसके कुछ प्रखर विरोधियों का मानना है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन की सही सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। यह सही है कि यह विकल्प भारत के पास है परन्तु वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन ही ऐसी सस्था है और रहेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये नियम बनायेगी और उसका अनुपालन करवायेगी तथा चीन और रूस जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नहीं हैं उनको प्रवेश पाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए भारत, बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता त्यागने की बात नहीं सोच सकता है। दूसरी तरफ यदि भारत विश्व व्यापार संगठन में रहता है तो ट्रिप्स समझौते के अनुपालन हेतु विश्व व्यापार संगठन के भविष्य में विवाद निस्तारण पैनल के समक्ष उसे वास्तविक, पक्का और रक्षात्मक होना पड़ेगा।



आम जनता के हितो और बौद्धिक सम्पदा अधिकार धारको के निजी हितो के बीच तारतम्य बैठा कर भारत ट्रिप्स प्राविधानो को अपना सकता है। जब तक ऐसा है, विश्व व्यापार सगठन को छोड़ना भारत के लिये काफी महंगा साबित हो सकता है।

भारत में पहले से ही जो नियम व कानून बौद्धिक सम्पदा के लिये, जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पेटेन्ट्स तथा औद्योगिक प्रतिरूप को समाहित करते हैं उसके लिये यह आवश्यक है कि क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों की बढ़ोत्तरी के लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण किया जाये। कई नये क्षेत्र जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में नहीं हैं उनको भी ट्रिप्स अपने दायरे में ले लेता है। और साथ ही पहली बार बौद्धिक सम्पदा कानून के संरक्षण और क्रियान्वयन हेतु ट्रिप्स ने पहली बार सतुलित एवं व्यापक पद्धति बनायी है।

ट्रिप्स समझौता 7 प्रकार के बौद्धिक सम्पदा के लिये प्रतिमान और सिद्धांत प्रतिपादित करता है। ये सात हैं— कॉपीराइट और संबंधित राइट, ट्रेडमार्कस, भौगोलिक चिन्ह, इन्डस्ट्रियल डिजायन, पेटेन्ट्स, अघोषित सूचना तथा ले आउट डिजाइन ऑफ इन्टीग्रेटेड सर्किट्स विधिक क्रियान्वयन प्रत्येक विश्व व्यापार सगठन सदस्य पर छोड़ दिया गया है। भारत ने अपने कानून एवं न्याय शास्त्र के माध्यम से ट्रिप्स मानकों के अन्तर्गत कॉपीराइट्स और संबंधित अधिकार व्यापार चिन्ह भौगोलिक

सकेत औद्योगिक प्रतिरूप आदि के कुछ प्राविधानों को अपनाया है। ले आउट डिजाइन फार इन्ट्रीग्रेटेड सर्किट्स के लिये नये नियमों की आवश्यकता है।

व्यापार चिन्ह, भौगोलिक संकेतक एवं गुप्त सूचनाओं पर के संरक्षण ट्रिप्स प्राविधानों की स्वीकृति के लिये वर्तमान नियमों में कुछ संशोधनों की जरूरत है। जैसे भारतीय कानून पृथक् या स्पष्ट चिन्ह या चिन्हों के समूह को व्यापार चिन्हों जिसमें सेवा चिन्ह भी है के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान करता है। परन्तु उनके पंजीयन के लिये व्यापार एवं व्यापारिक अधिनियम 1958 में संशोधन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से व्यापार रहस्यों को सविदा अधिनियम और सामान्य नियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है।

मुक्त व्यापार नीति के तहत भारत एक विकासशील देश जो अत्यधिक जनसंख्या भार को अपने में समाहित किये हुए है। वहां बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ने की प्रबल संभावनाएं पैदा होंगी। वर्तमान में यदि देखें तो इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। बेरोजगारी की समस्याएं निम्न कारणों से बढ़ सकती हैं।

- 1 आधुनिक तकनीक का प्रयोग
- 2 सामाजिक कल्याण की भावनाओं में कमी।
- 3 परम्परागत उद्योग का विकास न होना।
- 4 अधिकतम लाभ कमाने की चेष्टाएं।

विश्व व्यापार सगठन के तहत कल्पना की जाने वाली विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की रही है। और इस दिशा में कार्य भी किये जा रहे हैं इसका सर्वप्रथम प्रभाव विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर था जो पड़ने जा रहा है वह आधुनिक तकनीक के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश से बेरोजगारी की स्थिति भयावह होने की संभावना है।

यदि भारत के परिदृश्य में इसका विश्लेषण करें तो हमारे यहाँ मानव द्वारा सम्पादित होने वाले व्यक्तिगत कार्य को सम्पादित करने वालों की प्रचुरता विद्यमान है परन्तु आधुनिक तकनीक के साथ ही साथ मनुष्यों की कार्य क्षमता के स्थान पर तकनीकों के सहारे मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। जो कई व्यक्तियों का कार्य अकेले सम्पादित करने की क्षमता रखती है।

विश्व व्यापार सगठन के द्वारा परिकल्पित मुक्त विश्व अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकों के विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रवेश तीव्रता से होना शुरू है और बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ रही है जो इन अर्थव्यवस्थाओं के लिये शुभ लक्षण नहीं है।

इसी मुक्त व्यापार की नीति के कारण सामाजिक कल्याण की भावना के तहत सरकारों द्वारा किये जा रहे व्ययों में कटौती प्रारम्भ कर दी गयी है और अर्थव्यवस्था के सामाजिक कार्यों पर व्यय की जा रही मुद्रा को कम या समाप्त करने की योजनाएँ तय

की जा रही है इससे भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने का संकट बरकरार दिखाई पड़ रहा है। अभी तक कुछ उद्योग बिना लाभ हानि पर चलाये जा रहे थे जो अब संभव नहीं होगा इस विश्व बाजार अर्थव्यवस्था के तहत पूरे विश्व को एक बाजार में परिणित करने की जो विश्व व्यापार संगठन की नीति है वह अब अधिकतम बेरोजगारी को बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान करेगा। अभी तक सरकारें इनके क्रिया कलापों पर नजर रखा करती थी और कम लाभ पर भी उद्योग को संचालित कराने में मदद करती थी। परन्तु अब ऐसा संभव नहीं होगा।

## सुझाव :

विश्व जगत में होने वाले किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है और इस स्थिति को पैदा करने में कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिये गये वक्तव्यों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा दिये गये वक्तव्यों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा स्वार्थहित में किये गये व्यक्तिगत लाभ के लिये क्रिया कलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु जब डकल प्रस्ताव एक ऐसा महत्वपूर्ण सविदा के रूप में विश्व व्यापार संगठन के तहत स्थापित हो चुका है तो हम इसका अन्धा विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डकल प्रस्ताव के निर्माता श्री आर्थल डकल जी ने स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैं कि कोई भी देश इस रामझौते से दूर रह सकता है परन्तु उसे विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता गंवानी पड़ेगी।

- 1 भारतीय अर्थ व्यवस्था 99 प्रतिशत स्वदेशी अर्थव्यवस्था रही है जबकि इस अर्थव्यवस्था को मात्र 1 प्रतिशत विदेशी अर्थव्यवस्था पर आश्रित रहना पडा है ।  
यदि भारत चाहे तो अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ करके अपने यहा के मानव शक्ति का सदुपयोग कर सकता है ।

विकसित राष्ट्र वर्तमान समय मे परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर चुके है इस स्थिति के बाद इन राष्ट्रों के द्वारा अत्यधिक उपभोग किया जाता है परन्तु इस उपभोग वाली सस्कृति विकासशील राष्ट्रों के लिये हानिकारक सिद्ध होगी । इस तथ्य को हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा सकते है यदि किसी व्यक्ति की प्रत्येक दिन आय 10,000 रुपये है और वह व्यक्ति अपने उपभोग पर 5,000 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है तो उसपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पडेगा । परन्तु एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय प्रतिदिन 4,000 रुपये है और वह प्रतिदिन 5,000 रुपया उपभोग पर नकल करके खर्च करता है तो स्थिति इस व्यक्ति की भविष्य मे भयावह होगी ।

यह सुझाव मुझे इस लिये देना पड रहा है कि वर्तमान समय मे डकल का परिमार्जित स्वरूप जो विश्व व्यापार सगठन के रूप मे स्थापित हो चुका है इस के कारण पूरा विश्व एक बाजार व्यवस्था की स्थिति मे पहुचने वाला है । इससे पूरे विश्व मे सस्कृति का आदान प्रदान होगा । पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ।

भारतीय परिदृश्य में इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। भारत के वासी नकल प्रक्रिया को अपना कर अपने को श्रेष्ठ साबित करने की जो चेष्टाये पाले हुए हैं वह उनके लिये घातक होगी। वर्तमान आर्थिक युग के तहत (रूपया) अर्थ प्राप्त करना किसी स्रोत से और अपने को श्रेष्ठ साबित करना दूसरों की अपेक्षा बहुत ही गलत परम्परा को अपनाने के तुल्य है। हमारे यहाँ लोगों के खर्च निरन्तर बढ़ रहे हैं इससे तमाम प्रकार की विकृति या उत्पन्न होना स्वाभाविक है जैसे चोरी, दलाली, लूट, घसोट, छीना-झपटी एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की मूल जड़ में अर्थ समाहित है। इन प्रवृत्ति को विदेशी उपभोग वाली संस्कृति के द्वारा भविष्य में बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना विद्यमान है। विकासशील राष्ट्रों को चाहिए कि अपनी स्थिति का आकलन करें और अपने देश के निवासियों को समझाये कि अपनी आय से ज्यादा खर्च उनके लिये ठीक नहीं है। विदेशों की नकल परम्परा हमारे यहाँ उचित नहीं क्योंकि उनकी क्षमता के तुल्य हम नहीं हैं इस वास्तविकता को स्वीकार कराने की चेष्टा और प्रयास से इस पर काबू पाया जा सकता है।

विकासशील देशों को यह भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिये कि डकल प्रस्ताव के वर्तमान रूप विश्व व्यापार संगठन के तहत विदेशों से आयातित तकनीक कहीं बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न नहीं कर रही यदि ऐसा है

तो उसको कम करने एवं अपने (मैन पावर) मानव शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार कहा और कैसे करे इसकी विस्तृत योजना होनी चाहिये।

भारत जैसे विकाशील देश में जनसंख्या वैसे ही भयावह है और बेरोजगारी चरम सीमा पर यदि आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसी तरह कार्य की कुशलता बढ़ाई जाती रही तो बेरोजगारी और ही भयावह स्थिति ले सकती है। क्योंकि आधुनिक समय में बढ़ते हुए कम्प्यूटरों का प्रयोग संभव है बेरोजगारी वृद्धि करे।

विकासशील राष्ट्रों की तकनीक विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा काफी पीछे है। वर्तमान समय में विदेशी पूँजी निवेश और मुक्त व्यापार नीति के तहत आयातित तकनीक के द्वारा अपने देश में औद्योगीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सतुलन स्थापित किया जाये इस पर भी विचार-विमर्श कर एक कार्य योजना तैयार कर उस पर कार्य करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।

भारत में विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ावा मिला है इससे नये-नये क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संभव है परन्तु इसके तीन नकारात्मक प्रभाव प्रधानतः दिखाई पड़ते हैं। प्रथम—बेरोजगारी द्वितीय—स्वदेशी उद्योग का ह्रास एवं तृतीय—पूँजी का बहिर्गमन। इन बिन्दुओं पर देश के बुद्धिजीवियों विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजनीतिज्ञों को गहराई से विचार करना होगा कि किस प्रकार से इसके प्रभावों से बचा जा सकता है।

विकासशील राष्ट्रों का यह भी दायित्व है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी सेवाएँ अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर सिद्ध हों तथा व्यापार में वृद्धि हो, व्यापारिक सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपने व्यापारिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार करना होगा। जिससे ये वस्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने को स्थापित कर सकें। इस समय जो भी देश इसमें पीछे हुआ वह अपने को दिवालिया करने के कगार पर पहुँच सकता है।

परिवहन किसी भी व्यापारिक जगत के लिये सजीवनी का कार्य करती है। इस लिये भारत जैसे विकासशील देशों को चाहिए कि अपने यहाँ की परिवहन सेवाओं का सुधार करें और उसको बेहतर बनायें

इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ भी विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा काफी पीछे हैं इसलिये स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकास कर अपने को सक्षम राष्ट्रों के समतुल्य करना होगा। किसी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के स्वस्थ लोगों पर ही निर्भर करता है।

किसी भी देश के वाणिज्यिक विकास में उस देश की बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसलिये सभी विकासशील देशों को चाहिये कि वे अपने यहाँ बैंकिंग एवं बीमा की सुविधा को और सक्रिय एवं सुचारु रूप



से व्यवस्थित करे जिससे वे अपने यहा व्यापारिक क्रियाओ मे सहयोग प्रदान करे ।  
जिससे विकसित राष्ट्रों की तुलना मे अपने को खड़े कर सके ।

सभी राष्ट्रों के विकास मे वहा की व्यापारिक क्षमता का योगदान होता है यदि आपके देश का निर्यात आयात की अपेक्षा ज्यादा होता है तो स्वाभाविक है कि आप के पास पूँजी निवेश के लिये अधिशेष है और आप अधिक निवेश के माध्यम से अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात कर अधिक अधिशेष प्राप्त कर सकते हैं ।। इस लिये सभी विकासशील राष्ट्रों को चाहिए की वे अपने यहा की निर्यात परक वस्तुओ मे वृद्धि कर निर्यात बढ़ाने की हर सम्भव कोशिश करे ।

## परिशिष्ट 1

डकल प्रस्ताव के परिशिष्ट 1 में प्रयोग की गयी शब्दावली तथा उसकी परिभाषा<sup>1</sup>

150/1EC निर्देशिका 2 1991 के छठे संस्करण में दी गयी शब्दावली इस समझौते में जहाँ भी इस्तेमाल की जायेगी उसका अर्थ निर्देशिका में दी गई परिभाषा के समरूप ही माना जायेगा कि सेवाये इस समझौते के बाहर रखी गयी है। इस समझौते के लिये निम्न परिभाषाये लागू होगी

\*

### 1. तकनीकी नियंत्रण:

वह दस्तावेज है जो कि उत्पाद की विशेषताये या उससे सम्बन्धित बनाने एवं उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताये और साथ में प्रशासनिक प्राविधान जिनका पालन जरूरी है इसके अन्तर्गत शब्दावली, चिन्ह, बैकिंग, मार्किंग या लेबलिंग जो उत्पाद तथा उत्पादन में लाये जाये।

### 2. मानक :

मानक के लिये निम्न परिभाषा लागू होगी – वह दस्तावेज जिसे किसी समिति ने पारित किया हो और जिसमें यह सामान्य एवं उपयोग के बारे में बताया गया हो जैसे कि नियम, दिशा निर्देश या उत्पाद की विशेषताये और जिनका पालन जरूरी नहीं है।

## टिप्पणी

आई ई सी निर्देशिका के भाग 2 में परिभाषित शब्दावली के अन्तर्गत उत्पाद बनाने की विधि एवं सेवाएँ आती हैं। यह समझौता केवल तकनीकी नियंत्रण माप एवं आकलन प्रक्रिया जो कि उत्पाद या बनाने की विधि एवं उत्पादन विधि से सम्बन्धित है। 150/1EC Guide 2 में परिभाषित स्टैन्डर्ड जरूरी या स्वेच्छिक दोनों ही हो सकती हैं। इस समझौते के लिये स्टैन्डर्ड की परिभाषा स्वेच्छिक और तकनीकी नियंत्रण आवश्यक दस्तावेज बताये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानक समुदाय द्वारा तैयार मानक सर्वसम्मति से बनाये जाते हैं। यह समझौता उन दस्तावेजों पर भी लागू होगा जिनपर सर्वसम्मति नहीं है।

## अनुसरण निर्धारण प्रक्रियायें:

कोई भी प्रक्रिया जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोग में लाया जाये ताकि यह जाना जा सके कि तकनीक नियंत्रण एवं मानक के लिये उपयुक्त आवश्यकताएँ पूर्ण हो रही हैं अथवा नहीं।

## टिप्पणी

अनुसरण निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत सैमपलिंग की प्रक्रिया जांच एवं परख, मूल्य निर्धारण, सत्यापन तथा अनुसरण का अश्वासन, रजिस्ट्रेशन, एक्विडेशन और पारण के साथ उनके काम्प्लीनेशन।

#### 4. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था या प्रणाली :

वह संस्था या प्रणाली जिसकी सदस्यता सभी सम्बन्धित संस्थाओं जो कि इस समझौते में शामिल हैं उनके लिये खुली है।

#### 5. क्षेत्रीय संस्था या प्रणाली

वह संस्था या प्रणाली जिसकी सदस्यता केवल कुछ संस्थाओं के लिये ही खुली है।

#### 6. केन्द्रीय सरकार संस्था:

केन्द्रीय सरकार, उसके मंत्रालय एवं विकास या अन्य कोई संस्था जो केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हो और उसके कार्य प्रश्न हो।

#### टिप्पणी :

जो प्राविधान केन्द्रीय सरकार पर लागू होते हैं वही EEC पर भी लागू होंगे लेकिन EEC के अन्तर्गत क्षेत्रीय संस्थाएँ या Conformity Assessment Systems

बनाये जा सकते हैं और ऐसे केशो मे वे इस समझौते के प्राविधानो के अन्तर्गत होंगे ।

## 7. स्थानीय सरकार

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त सरकार (जैसे राज्य, प्रात, लैण्डर, केन्टन, म्यूनिसिपेलटी आदि) उसके मंत्रालय एवं विभाग या अन्य कोई भी सस्था जो उसके अन्तर्गत हो ।

## 8. गैर सरकारी संस्था

कोई भी अन्य सस्था जो केन्द्रीय या लोकल सरकारी सस्था से भिन्न हो और जिसके पास तकनीकी प्राविधानो को लागू करने की कानूनी शक्ति हो ।

## परिशिष्ट 2

### वस्त्र तथा कपडा पर समझौता

वस्त्र एवं कपडा से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये हैं<sup>2</sup>

#### पुन्ताडेल स्टेट (Punta Dal Estate)

- 1 वार्ता के दौरान अनुसमितीय स्तर पर यह सहमति हुई कि वस्त्र एवं कपडा क्षेत्र को गैट नियमों के अन्तर्गत सामिल किया जाये जिससे व्यापार के उदारीकरण प्रक्रिया को और सुदृढ बनाया जा सके।
- 2 इस बात को भी ध्यान में रखा जाये कि अप्रैल 1989 में व्यापार समझौता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार अनुकूलन प्रक्रिया उरुग्वे दौर के बाद चालू हो जावेगी और उसका स्वरूप प्रगतिशील होगा साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाये कि यह अल्प विकसित राष्ट्रों के लिये खराब व्यवस्था की जाये।

#### अनुच्छेद— 1

- 1 पक्षकारों द्वारा बीच के समय के लिये यह समझौता किया गया कि वस्तु एवं कपडा क्षेत्र का अनुकूलन गैट में हो।
- 2 पक्षकार इस बात पर सहमति हैं कि अनुच्छेद 2 18 तथा 6 6 के प्राविधान इस तरह लागू किये जाये जिससे छोटे आपूर्ति कर्ताओं को लाभ मिले और

नये आने वाले पक्षकारों को कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास हेतु व्यापार के अवसर प्राप्त हों

- 3 पक्षकारों उन सभी पार्टियों का ध्यान रखेगी जो एग्रीमेन्ट रिगार्डिंग इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड टेक्सटाइल्स (Agreement Regarding International Trade and Textiles) के प्रोटोकालों में 1986 से भाग नहीं ले पाई है और हर सम्भव तरीके से उन्हें इस समझौते के प्राविधानों को लागू करने के विशेष प्रयास करेंगे।
- 4 इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि पक्षकार इस बात पर सहमत हों कि कपास पैदा तथा निर्यात करने वाले राष्ट्रों की हितों की रक्षा की जाये और उसे समझौते में सम्मिलित किया जाये।
- 5 वस्तु एवं कपड़ा क्षेत्र के गैट में अनुकूलन हेतु पार्टियों को औद्योगिक बढ़ावा तथा अपने बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा।
- 6 जब तक अलग से इस समझौते में न दिया जाये इसके प्राविधान पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्यों पर असर नहीं डालेंगे।
- 7 वस्त्र एवं कपड़ा उत्पाद जिनपर यह समझौता लागू होता है वह इस समझौते के परिशिष्ट में दिये गये हैं। (जो अन्त से परिशिष्ट कहा जायेगा)

### परिशिष्ट 3

## सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता

### प्रस्तावना

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Part-I</b>   | दायरा एव परिभाषा                        |
| अनुच्छेद – I    | - दायरा एव परिभाषा                      |
| <b>Part- II</b> | - सामान्य कर्तव्य तथा क्षेत्र           |
| अनु० II         | - परम मित्र राष्ट्र व्यवहार             |
| अनु० III        | - पारदर्शिता                            |
| अनु० III bis    | - खास सूचना का प्रकाशन                  |
| अनु० IV         | - विकासशील देशों की भागीदारी में वृद्धि |
| अनु० V          | - आर्थिक अनुकूलन                        |
| अनु० VI         | - घरेलू नियमन                           |
| अनु० VII        | - अभिस्वीकार/मान्यता                    |
| अनु० VII        | - एकाधिकारी एव सेवा प्रदान करने वाले    |
| अनु० IX         | - व्यापारिक क्रियाये                    |
| अनु० X          | - आपात कालीन बचाव उपाय                  |
| अनु० XI         | - भुगतान तथा अन्तरण                     |
| अनु० XII        | - भुगतान सतुलन के लिये बचाव प्रतिबन्ध   |
| अनु० XIII       | - सरकारी खरीद/वसूली                     |
| अनु० XIV        | - सामान्य अपवाद                         |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Part- III</b> | - विशिष्ट उत्तरदायित्व                    |
| अनु० XVI         | - बाजार में प्रवेश                        |
| अनु० XVII        | - राष्ट्रीय उपाय                          |
| अनु० XVIII       | - अतिरिक्त उत्तर दायित्व                  |
| <b>Part- IV</b>  | - विकासशील उदारीकरण                       |
| अनु० XIX         | - वार्ता के उत्तरदायित्व                  |
| अनु० XX          | - उत्तर दायित्व की अनुसूची                |
| अनु० XXI         | - अनुसूची के सुधार                        |
| <b>Part- V</b>   | - सस्थागत प्राविधान                       |
| अनु० XXII        | - परामर्श                                 |
| अनु० XXIII       | - विवाद निस्तारण तथा प्रवर्तन             |
| अनु० XXIV        | - सयुक्त क्रिया                           |
| अनु० XXX         | - काउंसिल/परिषद                           |
| अनु० XXVI        | - तकनीकी सहायता                           |
| अनु० XXVII       | - अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बन्ध |
| <b>Part- VI</b>  | - अन्तिम प्राविधान                        |
| अनु० XXVIII      | - स्वीकार करना एवं प्रवेश साधन            |
| अनु० XXIX        | - शक्ति प्रवेश                            |
| अनु० XXX         | - गैर आवेदन                               |
| अनु० XXXI        | - लाभ निषेध                               |
| अनु० XXXII       | - सशोधन                                   |
| अनु० XXXIII      | - वापस लेना                               |
| अनु० XXXIV       | - व्याख्या                                |
| अनु० XXXV        | - परिशिष्ट                                |

## सेवा मे व्यापार पर सामान्य समझौते

अनु० I से XXXV

एग्रेसर ऑन आर्टिकिल सेकेण्ड इक्जेशन

प्राकृतिक मनुष्यो द्वारा सेवा के प्रदान का परिशिष्ट

वाणिज्य सेवाओ पर परिशिष्ट

टेली कम्यूनिकेशन्स पर परिशिष्ट

उड्यन परिवहन सेवाओ पर परिशिष्ट

## अन्य दस्तावेज

सस्थाओ के प्रबध पर अनुसचिवीय निर्णय कुछ विवाद निस्तारण प्रक्रिया पर अनुसचिवीय निर्णय, अनु० XIV (b) से सम्बन्धित निर्णय

वाणिज्य सेवाओ के उत्तर दायित्व पर आपसी सहमति एव उरुग्वे दौर मे मार्ग दर्शन ।

## परिशिष्ट 4

### सम्बंधित उपायों की सूची<sup>3</sup>

टैरिफ (बन्धीकरण के दायरे, जी एस पी प्राविधान मुक्त व्यापार क्षेत्र के सदस्यों तथा कष्टम यूनियन के सदस्यों के लिये लागू दरे अन्य वरीयताये)

टैरिफ कोटा एव सरचार्ज

अन्य गेर टैरिफ उपाय जैसे कि लाइसेंसिंग तथा मिश्रित जरूरते

कष्टम आकलन

उद्गम के नियम

सरकारी खरीद

तकनीकी बाधाये

सुरक्षा क्रियाये

एन्टी डम्पिंग क्रिया

विरोधी प्रक्रिया

निर्यात कर

- निर्यात पर सरकारी छूट, कर छूट तथा निर्यात ऋण के लिये छूट
- मुक्त व्यापार क्षेत्र
- निर्यात प्रतिबध
- अन्य सरकारी सहायता
- राज्य व्यापार उद्यमों का रोल
- आयात एव निर्यात से सम्बन्धित विदेशी पूजी पर नियंत्रण
- सरकारी प्रतिवादी व्यापार

कोई भी अन्य उपाय जो कि सामान्य समझौते के अन्तर्गत आता हो उसके एनेक्सर तथा प्रोटोकाल

## पैनलों की स्थापना .

इस समझौते के अन्तर्गत दिये गये समय के भीतर ही विवाद निस्तारण समिति को अपना कार्य पूरा करना होगा। यदि कोई वादी एक पैनल बनाने की इच्छा जाहिर करता है तो शीघ्र से शीघ्र विवाद निस्तारण की समिति की बैठक में उसे लिया लिया जायेगा और पैनल की स्थापना की जायेगी और यदि समिति एक मत से यह पैनल न बनाने का निर्णय लेती है तो पैनल नहीं बनाया जायेगा।

## पैनलों की संरचना -

- 1 पैनलों में पूर्ण योग्य सरकारी और/या गैर सरकारी व्यक्तियों को ही रखा जायेगा इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पैनल में अपना केस रखा है या वे पूर्व में पैनल के सदस्य रह चुके हैं वे सभी व्यक्ति जो पूर्व में गैट में प्रतिनिधित्व कर चुके हों या समझौते के तहत किसी कमेटी या कौंसिल में रहे हों या सचिवालय में रहे हों वे सभी लोग जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि नीति को पढ़ाया हो या उसपर प्रकाशन हो या किसी सदस्य के यहाँ व्यापार नीति के अधिकारी के रूप में करता हो।
- 2 पैनल सदस्यों के चुनाव हेतु, सचिवालय उन सभी सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों की सूची रखेगी जो उपर्युक्त पैरा में दिये गये अर्हताये पूर्ण करते हों। यह सूची गैट पक्षकारों द्वारा 30 दिसम्बर 1984 में किये गये गैर सरकारी पैनल के रoster का स्थान लेगी। यह अन्य रoster और सूचनात्मक सूची जो कि किसी भी समझौते के अन्तर्गत आती है उनका भी स्थान लेगी। सदस्य समय — समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों

के नामों का सुधार सूचनात्मक सूची में शामिल किये जाने के लिये भेजते रहेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौतों के बारे में सम्बन्धित सूचना प्रदान करना और ये सभी नाम विवाद निस्तारण समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही सूची में शामिल किये जायेंगे। पैनल के हर सदस्य के अनुभव तथा कार्य क्षेत्र के बारे में सूची में विस्तृत विवरण दिया जायेगा।

- 3 यदि पैनल सदस्यों के चुनाव में पैनल के स्थापना के 20 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं हो पाता है तो विवाद निस्तारण समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित कमेटी या कौंसिल के अध्यक्ष से सलाह करके पैनल की स्थापना कर सकता है। विवाद निस्तारण समिति का अध्यक्ष 10 दिनों के भीतर पैनल के सभी सदस्यों को पैनल स्थापना की सूचना देगा।

## परिशिष्ट 5

ड्राफ्ट के कृषि सम्बन्धी अध्याय के अनु० में कुछ परिसीमाये दी गयी है—यथा<sup>4</sup>

### भाग 1

इस समझौते में जब तक कि व्याख्या अन्य न हो

- a सहायता का औसत आय माप (Agreegate Meassurement Support)
- b मूल उत्पाद का अर्थ है उत्पाद जिसे प्रथम विक्री के समय ही स्वदेशी सहायता वादे के निकटतम माना जाये।
- c कर जो छोड़ दिये गये हैं उनके अन्तर्गत बजटरी परिव्यय।
- d समान वादे वे हैं जो स्वदेशी सहायता वाले की अनुसूची हैं और सम्बन्धित सहायक वस्तुओं में वर्णित हैं।
- e निर्यात सहायिकी का अर्थ है वे सहायिकी जो कि निर्यात पर निर्भर हो और जिनके अन्तर्गत इस समझौते के अनुसार अन्च्छेद IX में दी गयी सहायिकी आती है।
- f लागू करने का समय वह समय जो वर्ष 1993 में आरम्भ हुआ और 1999 में समाप्त होगा।
- g मार्केट असेस कन्सेशन के अन्तर्गत वे सभी बाजार प्रवेश वादे आते हैं जो इस समझौते के अन्तर्गत आते हैं।
- h वर्ष वह है जो बिन्दु एफ में बताया गया है और भाग लेने वाले के खास वादों से सम्बन्धित हो इसका अर्थ कैलेंडर वर्ष से है और जिसमें आर्थिक एवं व्यापारिक वर्ष निहित हैं।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

| लेखक                           | पुस्तक   |
|--------------------------------|--|
| त्रिपाठी, डॉ० बद्री विशाल      | भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन एवं विकास, किताब महल, 1997      |
| दत्त, रजनी पाम                 | आज का भारत, दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०, 1977         |
| दत्त, रमेश चन्द्र              | भारत का आर्थिक इतिहास भाग I प्रकाशन विभाग 1987             |
| दत्त, रुद्र, सुन्दरम, के पी एम | भारतीय अर्थव्यवस्था, 1997                                  |
| मिश्र, डॉ जगदीश नारायण         | भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, 1996                       |
| मामोरिया, डॉ० चतुर्भुज         | भारत की आर्थिक समस्याये, साहित्य                           |
| एव जैन, डॉ० एस सी              | भवन पब्लिकेशन आगरा, 1996                                   |
| मिश्र, एस के ,<br>पुरी वी के   | इण्डियान इकोनॉमिक, हिमालया पब्लिकेशन हाउस, 1997            |
| राय, एल एम                     | महान राष्ट्रों का अर्थिक विकास नव विकास प्रकाशन पटना, 1990 |
| राय, एल एम                     | भारत का आर्थिक विकास, 1990                                 |
| राय, एल एम.                    | आर्थिक विकास के सिद्धांत एवं नियोजन                        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Aswathappa, K</b>         | Essentials of Business Environment,<br>Himalaya Publishing House, 1996 |
| <b>Dunkel Draft</b>          |  |
| <b>Dubey Muchkund</b>        | An Unequal Treaty 1996   |
| <b>Sharma, A D , Geetika</b> | Gatt-WTO and the new world Economic<br>Order, Kitab Mahel, 1995        |
| <b>Sharma, Devendra</b>      | Gatt to WTO, Seeds of despair, Konark<br>Publishers Pvt Ltd , 1995     |

## REPORT AND SURVEY

Economic Survey, 1997

Survey to Indian Industry, The Hindu, 1997

Survey of Indian Agriculture, Hindu, 1997

World Development Report, The world Bank, 1991

## पत्र-पत्रिकाएं

- 1 कुरुक्षेत्र
- 2 योजना
- 3 जनसत्ता
- 4 Business India
- 5 Economic Times
- 7 Financial Express
- 8 Hindustan Times
- 9 Weekly